



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]
No. 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1998/श्रावण 17, 1920
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1998/SHRAVANA 17, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 22nd July, 1998

का.आ. 1520.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्याम सिंह यादव, लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मामलों तथा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र जिस पर पूर्वोक्त धारा के उपबंध लागू होते हैं, में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों में उद्भूत अपीलों, पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

S.O. 1520.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Shyam Singh Yadav, Public Prosecutor of the Central Bureau of Investigation as Special Public Prosecutor for the conduct of cases instituted by Delhi Special Police Establishment in the trial courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by Law in any State or Union Territory to which the provision of the aforesaid section apply.

[सं. 225/1/98-ए.वी.डी. II]
हरि सिंह, अवर सचिव

[No. 225/1/98-AVD. II]
HARI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

का.आ. 1521.—केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सी.एस. शर्मा, अधिवक्ता, नई दिल्ली को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.प्र. अय्यर, लखनऊ, विशेष न्यायाधीश, जिला और सेशन न्यायाधीश, लखनऊ के न्यायालय में मामला सं. आरसी-4(एस)/97-एसआईसी-4, सीबीआई, नई दिल्ली (रुंगटा अपहरण मामला) के अभियोजन तथा उनसे संबंधित अथवा आनुषंगिक किसी अन्य विषय का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/7/98-ए.वी.डी. II]

हरि सिंह, अवसर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 1998

S.O. 1521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), The Central Government hereby appoints Shri C. S. Shatma, Advocate, New Delhi Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of case R.C.No. 4(S) 97/SIC. IV/CBI/New Delhi (Rungta Kidnapping case) and any other matter connected therewith or incidental thereto, in the Court of Special Judicial Magistrate/CBI/LKO/Special Judge/Dist. and Sessions Judges, Lucknow,

[No. 225/7/98-AVD. II]

HARI SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 16 अप्रैल, 1998

आयकर

का.आ. 1522.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन चिह्नित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन 'न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा

औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, विध्या नगर, लतूर-4135311, महाराष्ट्र

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभागीय प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र, छः प्रतियों अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1799/एफ.सं.म.नि/आ.क. (छूट)/एम.-15/कल./ 35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF INCOME-TAX (EXEMPTIONS)

Calcutta, the 16th April, 1998

INCOME-TAX

S.O. 1522.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of Sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year 31st May of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemption), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy or audited Income and Expenditure Account in respect of its research

activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Vivekanand Medical Research Society,
Vidya Nagar,
Latur-413531,
Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

Notes : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax, Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be not directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1799/F. No. DG/IT(E)/M-15/CAL/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions).

कलकत्ता, 21 अप्रैल, 1998

आयकर

का०आ० 1523 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिक भवन” न्यू डेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परिक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परिक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : सेंट्रल फोर एकोनॉमिक एण्ड सोशल स्टडीज, निजामियां ओब्सर्वेटोरी कम्पास, बेगूमपेट, हैदराबाद-500016।

यह अधिसूचना दिनांक 3-8-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1800/एफ.सं.म.नि/आ.क. (छूट)/ए.पी.-31/35(1) (iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 21st April, 1998

INCOME-TAX

S.O. 1523.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of Sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year 31st May of each year; &
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemption-), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Economic and Social Studies,
Nizamiah Observatory Campus, Begumpet,
Hyderabad-500016.

This Notification is effective for the period 3-8-1995 to 31-3-1998.

Notes : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax, Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies

of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1800/F. No. DG/IT(E)/AP-31/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions).

कलकत्ता, 13 मई, 1998

आयकर

कां०प्रा० 1524 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परिचित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिस्चर्व किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परिचित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संस्थान का नाम : दिव्याय्योत आयुर्वेदिक रिसर्च फाउण्डेशन (श्री श्री माँ आनन्त आनन्द आश्रम आनन्तधाम, विहलाल, टी०ए० दासकरोई, डीस्ट-महमदबाद-382325।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की

अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1801/एफ.सं.म.नि/आ.क. (छूट)/जी.-49/35(1)
(ii)/90-91)]

मूकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 13th April, 1998

INCOME-TAX

S.O. 1524.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Proscribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of Sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The Organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Divyayot Ayurvedic Research Foundation,
(Shree Shree Maa Anantanand Ashram),
Anantdham, Vehlal, TA. Daskroi,
Dist-Ahmedabad-382325.

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

Notes : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1801/F. No. DG/IT(E)/G-49/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions).

कलकत्ता, 19 मई, 1998

आयकर

कां०प्रा० 1525 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड

(2) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ बाम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, 12, मेरीन लाईन्स, बाम्बे-400020

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियों अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1802/एफ.सं.म.नि/आ.क.(छूट)/कल./एम.-1/35(1)
(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 19th May, 1998

INCOME-TAX

S.O. 1525.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Precribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of Sub-section (1)

of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Insulation" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Medical Research Centre of Bombay Hospital Trust,

12, Marine Lines, Bombay-400020.

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

Notes : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1802/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-1/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax
(Exemptions).

कलकत्ता, 19 मई, 1998

आयकर

क्र०आ० 1526.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा

औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : हरिलाल जेचन्द दोसी मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन, मालवीयनगर, आँफो : गोंडल रोड, राजकोट-360004, (गुजरात)।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियाँ अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1803/एफ.सं.म.नि/आ.क. (छूट)/कल./जी.-26/35(1) (ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 19th May, 1998

INCOME-TAX

S.O. 1526.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of Sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy or audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Harilal Jechand Doshi Medical Research, Foundation, Malaviyanagar,

Off : Gondal Road, Rajkot-360004, (Gujarat).

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

Notes : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax, Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1803/F. No. DG/IT(E)/CAL/G-26/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 20 मई, 1998

आयकर

कां.धा० 1527.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरीली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : दी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ सैन्टीफिक रिसर्च, 78, सेक्टर अमीर अली एवेन्यू, कलकत्ता-700019।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-

धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1804/एफ.सं.म.नि/आ.क.(छूट)/डब्ल्यू.बी.-11/35(1)

(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 20th May, 1998

INCOME TAX

S.O. 1527.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of audited Income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Birla Institute of Scientific Research,
78, Syed Amir Ali Avenue,
Calcutta-700019.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1804/F. No. DG/JT(E)/WB-11/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 28 मई, 1998

आयकर

का.आ. 1528 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड

(iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा गनियों रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन' न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : कोयम्बाटोर कैंसर फाउण्डेशन, जी के० एन०एम० हॉस्पिटल, पी०एन० पलायम, पोस्ट बॉक्स नं० 6327, कोयम्बाटोर-641037।

यह अधिसूचना दिनांक 1-8-97 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1805/एफ.सं.म.नि/आ.क.(छूट)/टी.एन.-82/35(1)
(iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 28th May, 1998

INCOME TAX

S.O. 1528.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-

tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Coimbatore Cancer Foundation,
G.K.N.M. Hospital, P.N. Palayam,
Post Box No. 6327,
Coimbatore-641037.

* This Notification is effective for the period from 1-8-97 to 31-3-99.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1805/F. No. DG/IT(E)/TN-82/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 2 जून, 1998

आयकर

कां०आ०1529:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर

महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में योग्य-परीक्षा आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम : दी शुगर टेक्नोलॉजीस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 21, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है ।

[संख्या : 1806/एफ.सं.म.नि/आ.क.(छूट)/कल. एन.डी.-127/
35(1)(ii)/90-91]
मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 2nd June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1529.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Sugar Technologists' Association
of India, 21, Community Centre,
East of Kailash, New Delhi-110065.

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

Notes—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1806/F. No. DG/IT(E)/Cal/ND-127/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 2 जून, 1998

आयकर

का०आ०1530:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन" न्यू महरूली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : पुष्पावती सिधानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फोर लिवर, रीनल एण्ड डायजेस्टीव डायजीस, लीक हास, 3, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।

यह अधिसूचना दिनांक 2-7-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभागीय प्रस्तुत करना है। उसे आवेदन पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1807/एफ.सं.म.नि/आ.क.(छूट)/एन.डी.-146/35(1)
(2)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 2nd June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1530.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year : and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over, a organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Pushpawati Singhania Research
Institute for Liver,
Renal and Digestive Diseases,
Link House, 3 Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 2-7-96 to 31-3-98.

Notes—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for

extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1807/F. No. DG/IT(E)/ND-146/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 3 जून, 1998

आयकर

का०आ० 1531.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : दी महाराष्ट्र स्टेट ग्रेप ग्रावरस एसोसिएशन, दराकसा भवन, ई/4, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुना-411037।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की विषय को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन-

पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1808/एफ०सं०मं०नि०/आ०क० (छूट)/एम०-13/
35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 3rd June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1531.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Techno Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year : and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax Director of Income tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Maharashtra State Grape Growers' Association,
Draksha Bhawan, E/4, Market Yard,
Gultekdi, Pune-411037.

This Notification is effective for the period from 1-4-1997 to 31-3-2000.

Notes—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1808/F. No. DG/IT(E)/M-13/Cal/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 5 जून, 1998

आयकर

का०आ० 1532.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित

प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संघर्ष के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110 016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर इण्डिया, 172 जी, लोदी ईस्टेट, नई दिल्ली-110 003।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "संघ" जैसा संघर्ष के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन-पत्र छः प्रतियों अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1809/एफ० सं० म० नि०/आ० क० (छूट)/एम०-12/कल०/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 5th June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1532.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (1) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year : and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

World Wide Fund for Nature-India,
172-B, Lodi Estate,
New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1809/F. No. DG/IT(E)/M-12/Cal/35(1)(ii)/90-91]
MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 15 जून, 1998

आयकर

का०आ० 1533.—सर्वसाधारण को पत्रद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संघर्ष के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110 016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: इंडियन बर्नर्स रिसर्च सोसाइटी, श्री छात्रापती शिवाजी महाराज मार्केट बिल्डिंग, 3, थर्ड फ्लोर, पलटन रोड, मुम्बई—400 001।

यह अधिसूचना दिनांक 14-12-97 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन-पत्र पर प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1810/एफ. नं० सं. मं. नि/आ. कं० (छूट)/एम० 202/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 15th June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1533.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Burns Research Society,
Shree Chhatranvati Shivaji Maharaj Market Bldg.,
3rd floor, Palton Road, Mumbai-400001.

This Notification is effective for the period from 14-12-97 to 31-3-99.

Note—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1810/F.No. DG/IT(E)/M-202/35(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 16 जून, 1998

आयकर

का०आ० 1534.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए, अलग लेखा बहियां रखेगा;

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली—110 016 को भेजेगा; और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: थापर कारपोरेट रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर, पोस्ट बॉक्स नं० 68, पटियाला—147 001।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूझा दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन-पत्र की छः प्रतियाँ अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1811/एफ.० सं० मॉनि०/आ०क० (छूट)/कल०/पी०-1/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 16th June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1534.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Thapar Corporate Research and Development Centre,
Post Box No. 68,
Patiala-147001.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

Note—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1811/F. No. DG/IT(E)/Cal/P-1/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income Tax (Exemptions)

2003 GI/98--3.

कलकत्ता, 16 जून, 1998

आयकर

का०आ० 1535.—सर्वसाधारण को पत्रद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए, अलग लेखा बहियां रखेगा
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110 016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में रिसर्च किए गए कार्य से सम्बन्धित दी गई छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : कौंसिल ऑफ साइन्टीफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, रफी मार्ग, नई दिल्ली—110 001।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूझा दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन-पत्र की छः प्रतियाँ अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1812/एफ.० सं० मॉनि०/आ०क० (छूट)/कल०/एन०डी०-77/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 16th June, 1998

कलकत्ता, 25 जून, 1998

INCOME TAX

आयकर

S.O. 1535.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Council of Scientific and Industrial Research,
Rafi Marg, New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1812/F. No. DG/IT(E)/CAL/ND-77
35(1) (ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax
(Exemptions) (HQ-I)

कां०आ० 1536.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अवग लेखा बहियां रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110 016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में रिसर्च किए गए कार्य से सम्बन्धित की गई छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम : धर्मशिला कैंसर फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च सेंटर, बसुन्धरा एनक्लेव, दिल्ली—110 096 ।

यह अधिवृत्तना दिनांक 1-4-98 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन-पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है ।

[संख्या 1813/एफ० सं० म०नि०/आ०क० (छूट)/
एन०डी०-118/35(1) (II)/90-91]
मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th June, 1998

कलकत्ता, 26 जून, 1998

INCOME TAX

आयकर

S.O. 1536.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Dharamshila Cancer Foundation and Research Centre, Vasundhara Enclave, Delhi-110096

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-1999.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1813/F. No. DG/IT(E)/ND-118
35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax
(Exemptions).

कां०आ० 1537—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्व किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

भारती समासकर्ता विद्या निकेतनाम, 12, शंकर कुंज, नीयर हिमालया सोसाइटी, असल्फा, घाट कोपर वेस्ट मुम्बई-400084

यह अधिनूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र को छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है ।

[संख्या : 1814/एफ सं० म० नि०/आ०क० (छूट)/एम०-163/
35(1)(iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 26th June, 1998

कलकत्ता, 30 जून, 1998

INCOME TAX

आयकर

S.O. 1537.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Bharati Samkrta Vidya Niketanam 12, Shankar Kunj, Near Himalaya Society, Asalfa, Ghatkopar West, Mumbai-400084.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

- Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1814/F. No. DG/IT(E)|M-163
35(1)(iii)|90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax (Exemptions).

का०आ० 1538.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

भारत इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ फीजिकल मेडिसन एण्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी फोर प्रोमेशन ऑफ मेडिकल रिसर्च, हाजी अली पार्क, महालक्ष्मी, मुम्बई-400034

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए उद्योग सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है ।

[संख्या : 1815/एफ० सं० म० नि०/आ० क० (छूट)/एम०-134/
35(1)(ii)|90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 30th June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1538.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income tax Rules, for the purposes of Clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Society for Promotion of Medical Research, Haji Ali Park, Mahalaxmi, Mumbai-400034.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-1999.

- Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the

organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1815 F. No. DG|IT|(E)M-134]

35(1)(ii)|90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax
(Exemptions)

कलकत्ता, 30 जून, 1998

आयकर

का०आ० 1539.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नटया शोध संस्थान, 4ली रोड,

कलकत्ता—700020।

यह अधिसूचना दिनांक 29-10-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगी।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन की पत्र छः प्रतियाँ अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1816/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/इल्यू.
की.-59/35/(1) (iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 30th June, 1998

INCOME TAX

S.O. 1539.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rules 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of account for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities

ties for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Natya Shodh Sansthan, 4 Lee Road, Calcutta-700020.

This Notification is effective for the period from 29-4-1997 to 31-3-2000.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1816/F. No. DG/IT(E)/WB-59/35/
(1)(iii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of
Income-tax (Exemptions).

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

कां.आ. 1540.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को, उक्त सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर, कालम (1) में उल्लिखित बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करती है:—

सारणी

1	2	3
सिडिकेट बैंक	श्री पी के० बिश्वास, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, दंगलीर ।	श्री के० शिवरामन

1

2

3

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

यूनियन बैंक श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, श्री आई०डी०
 आफ इंडिया अपर मुख्य महाप्रबंधक, असवाल
 भारतीय रिजर्व बैंक,
 केन्द्रीय कार्यालय,
 मुम्बई ।

[एफ० सं० 9/6/98-बी०ओ०-1]

एम०एस० सीतारामन, अवसर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd July, 1998

S.O. 1540.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the banks specified in column (x) thereof in place of the persons specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

1	2	3
Syndicate Bank	Shri P. K. Viswas, Chief General Manager, Reserve Bank of India, Bangalore.	Shri K. Sivaraman
Union Bank of India	Smt. Shyamala Gopinath Addl. Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai.	Shri I. D. Agarwal

[F. No. 9/6/98-B.O.I.]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

का. आ. 1541 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखंड (1) और खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री रमेशलाल, वर्तमान महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के लिए देना बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 9/25/94-बी. ओ. I]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 24th July. 1998

S.O. 1541.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Romesh Lal, presently General Manager, Punjab National Bank as a whole time director (designated as the Executive Director) of Dena Bank for the period from the date of his taking charge and upto 31st October, 2000.

[F. No. 9/25/94-B.O.I.]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(कॉन्सुलर अनुभाग)

New Delhi, the 30th July, 1998

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1998

का.आ. 1542.—राजनयिक कोसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का बुतावास मेडरीड में सहायक श्री जे. श्रीनिवासन को 14-7-98 से सहायक कोसली अधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/1/98]

एन.यू. अविराचन, अवसर सचिव (पी.बी.एस.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Consular Section)

New Delhi, the 14th July, 1998

S.O. 1542.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri J. Srinivasan, Assistant in Embassy of India, Madrid to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 14-7-1998.

[No. T-4330/1/98]

N. U. AVIRACHAN, Under Secy. (Cons.).

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1998

का. आ. 1543.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिमूर्चन करती है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में 21 जुलाई, 1998 को सदन द्वारा लोक सभा के निम्नलिखित संसद सदस्यों को उक्त अधिनियम के उपबंधों की शर्त पर तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधिवत निर्वाचित किया है :

1. श्री के. एच. मुनिप्पा
2. श्री के. पलानीम्बामी
3. श्री विजय शंकर
4. श्री के. यगनयाडू

[फा.सं. 25012/3/96-रेशम]

अजित कुमार, निदेशक

S.O. 1543.—The Central Government of India hereby notifies that in pursuance of clause (c) of Sub-Section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the following members of Lok Sabha have been duly elected by the House on 21st July, 1998 to serve as members of the Central Silk Board for a period of three years subject to the provisions of the said Act :—

1. Shri K. H. Muniappa
2. Shri K. Palaniswami
3. Shri Vijay Shankar
4. Shri K. Yerranaidu

[File No. 25012/3/96-Silk]
AJIT KUMAR, Director

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1998

का. आ. 1544.—चलचित्रकी (प्रमाणन) नियम 1983 के नियम, 3 के साथ पठित चलचित्रकी अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मुश्री आशा पारेख को अवैतनिक क्षमता में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 25-6-98 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या 809/2/98-एफ (सी.)]

आई. पी. मिश्रा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st July, 1998

S.O. 1544.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 3 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government is pleased to appoint Ms. Asha Parekh as Chairperson, Central Board of Film Certification in an honorary capacity from 25-6-98 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

[File No. 809/2/98-F(C)]
I. P. MISHRA, Desk Officer

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

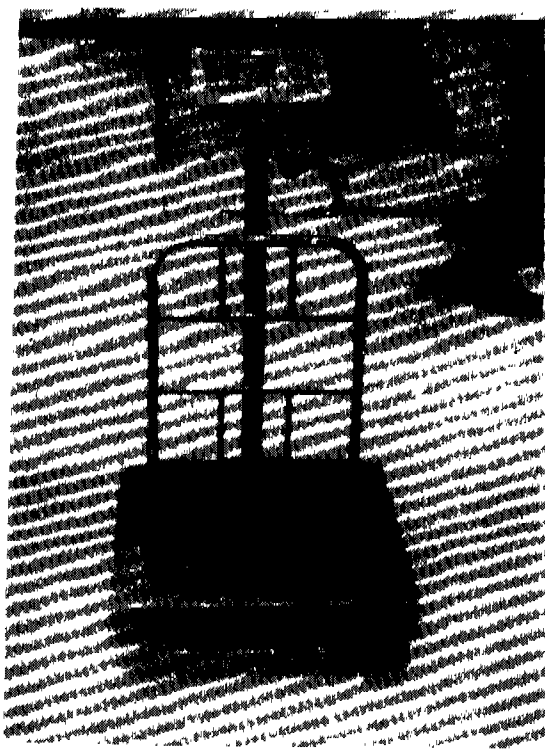
नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1998

का.आ. 1545.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखिए) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (उच्च) यथार्थता वर्ग 2 की टीडीपी सिरीज के "स्विफ्ट" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स तुला डिजिटल्स, (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 302, गुरु नानक हाऊस, बी-9, रनजीत नगर कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110008 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./09/97/09 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

माडल (आकृति देखिए) एक उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग 2) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 200 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही आयताकार सैक्शन का है जिसका आकार 550×660 मि.मी. है। प्रकाशउत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।

(आकृति)



आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 60 कि.ग्रा./5 या 10 ग्रा., 100 कि.ग्रा./10 ग्रा., 120 कि.ग्रा./10 ग्रा. या 20 ग्रा., 150 कि.ग्रा./20 ग्रा., 200 कि.ग्रा./20 ग्रा., 300 कि.ग्रा./50 ग्रा., 500 कि.ग्रा./50 ग्राम, 600 कि.ग्रा./100 ग्रा., 1000 कि.ग्रा./100 ग्रा., 1500 कि.ग्रा./200 ग्रा. और 2000 कि.ग्रा./200 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(38)/96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

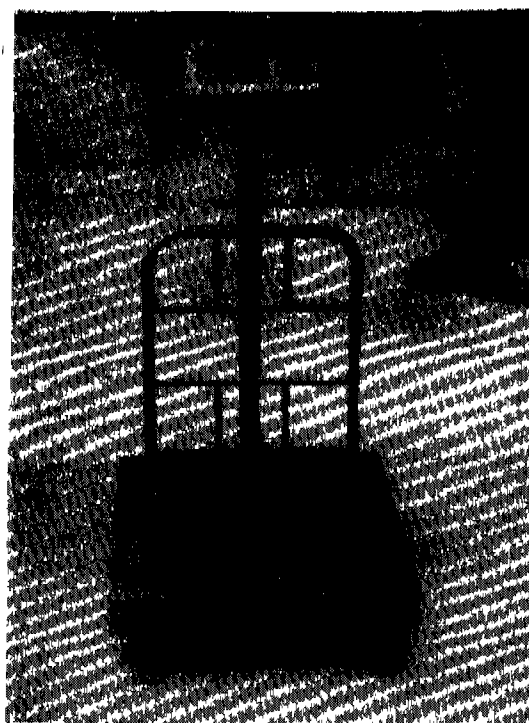
(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 17th July, 1998

S.O. 1545.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic electronic platform weighing machine of class II (High) accuracy of TDP series with brand name "SWIFT" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Tula Digitals (India) Private Limited, 302, Guru Nanak House, B-9, Ranjit Nagar Commercial Complex, New Delhi-110008, and which is assigned the approval mark IND/09/97/09;

The Model is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 200kg and minimum capacity of 400g. The verification scale interval (e) is 20 g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of size 550 X 600 millimetre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternate current power supply;



(Fig.)

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 60kg/5 or 10g, 100kg/10g, 120kg/10 or 20g, 150kg/20g, 200kg/20g, 300kg/50g, 500kg/50kg, 600 kg/100g, 1000kg/100g, 1500 kg/200g and 2000kg/200g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21(38)/96]

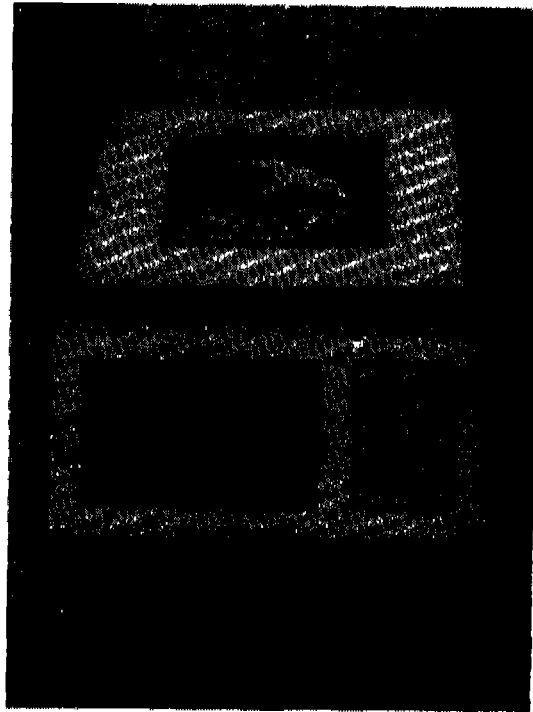
RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1998

का० आ० 1546.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखिए) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (उष्ण) यथार्थता वर्ग 2 की टी डी टी सिरिज के "स्विफ्ट" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इलैक्ट्रॉनिक टेबल टॉप तोलन मशीन के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात्, माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मै० तुला डिजिटल्स, (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 302, गुरु नानक हाउस, बी-9, रनजीत नगर, कामशियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110008 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई०एन०डी०/09/97/08 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

माडल (आकृति देखिए) एक उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग 2) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 15 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ई) 2 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही वर्गाकार सैक्शन का है जिसका आकार 300×300 मि.मी. है। प्रकाशउत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।



आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है। विनिर्मित 500 ग्राम/0.05 ग्राम, 1 कि०ग्रा०/0.1 ग्राम, 2 कि०ग्रा०/0.2 ग्राम, 6 कि०ग्रा०/0.5 ग्राम, 10 कि०ग्रा०/0.5 ग्राम, 12 कि०ग्रा०/1 ग्राम, 24 कि०ग्रा०/2 ग्राम, 25 कि०ग्रा०/2 ग्राम, 30 कि०ग्रा०/5 ग्राम, 50 कि०ग्रा०/5 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी सिरिज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(38)/96]

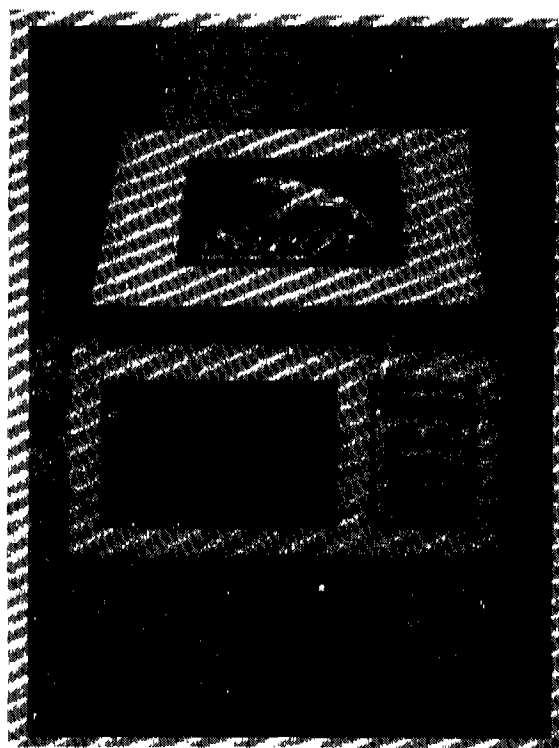
राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 17th July, 1998

S.O. 1546.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic electronic table top weighing machine of class II (High) accuracy of TDT series with brand name "SWIFT" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Tula Digital (India) Private Limited, 302, Guru Nanak House, B-9, Ranjit Nagar Commercial Complex, New Delhi-110008, and which is assigned the approval mark IND/09/97/08;

The Model is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 15 kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2 g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square section of size 300 × 300 millimetre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply;



(Fig.)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 500 g/0.05 g, 1 kg/0.1 g, 2 kg/0.2 g, 6 kg/0.5 g, 10 kg/0.5 g, 12 kg/1 g, 24 kg/2 g, 25 kg/2 g, 30 kg/5 g and 50 kg/5 g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

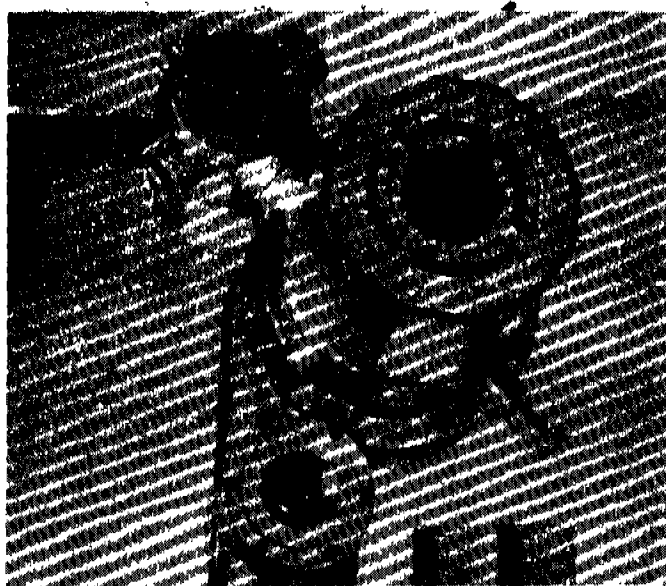
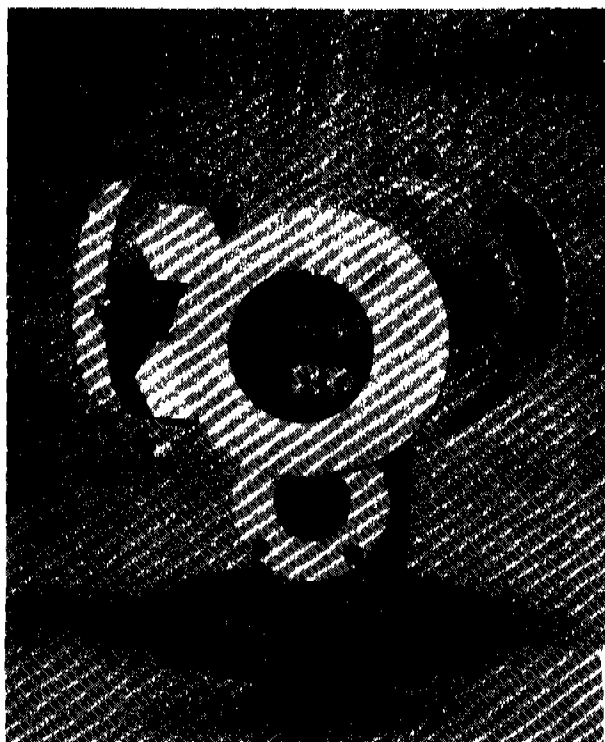
[File No. WM 21(38)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

का० आ० 1547.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना यह है कि अविरत उपयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टैंक साईड इन्डीकेटर और रिमोट इन्डीकेटर वाले सर्वो टाईप लेबल गाजिस, माडल का जिसका ब्रांड नाम "टी जी एम, 4100 ई, टी जी एम 4620 ई" डी आर एम 9700 ई, एम आई सी 1331 वाले रिमोट इन्डीकेटर सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स सपुरा एण्ड्रेस कम्पनी, लि० 862-1, मिल्सकुनुगी सकारागाबा-मूरा, हिगाशी यात्शुशिरी-गुन, 406, यामनाशी पी, जापान, जिसे भारत में मैसर्स एण्ड्रेस होजा-आई बी ओ, 301, सईनारा, नार्थ एवेन्यु, लिंकिंग रोड जंक्शन सांताक्रुज, मुम्बई-400054 द्वारा बेचा जा रहा है, द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई०एन०डी०/13/97/103 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।



आकृति

यह माडल (आकृति देखें) टैंक साईड इन्डीकेटर और रिमोट इन्डीकेटर वाले सर्वो टाईप लेबल गाजिस है जिसकी मापन रेंज 0-25 मीटर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इन्डीकेटर मापन परिणाम उपदर्शित करता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत इसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, के अनुसार विनिर्मित समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले एन एम एस 531 टाईप वाले आटोमेटिक लेबल गाज जिनसे भंडागार टैंक में द्रव के स्तर को मापा जाता है और जो एन आर एफ 560 टाईप वाले लोकल रोड आउट से युक्त है जिसकी मापन रेंज, 0-28 मीटर है, भी है।

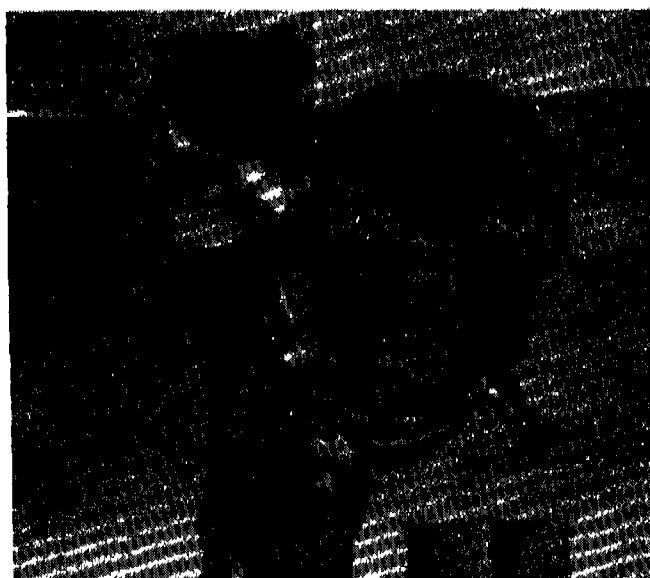
[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(93)/96]

राजीव श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव

New Delhi, the 22nd July, 1998

S.O. 1547.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Servo Type Level Gauges with Tank side Indicator and remote indicator of brand name "TGM 4100E, TGM 4620E" with remote indicator of "DRM 9700E, MIC 1331", (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Sakura Endress Co., Ltd., 862-1, Mitsukunugi Sakaigawa-mura, Higashi Yatshushiro-gun, 406, Yamanashi P, Japan and sold in India by M/s Endress Hauser—IBO, 301, Sainara, 21 North Avenue, Linking Road Jn, Santacruz, Mumbai-400054, and which is assigned the approval mark IND/13/97/103.



(Fig.)

The Model (see the figure) is a Servo Type Level Gauges with Tank Side indicator and remote indicator with a measuring range of 0-25 metre. The liquid crystal display indicator indicates the measurement result.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the automatic level gauge of similar make accuracy and performance of type NMS 531 destined for measuring the level of liquid in storage tanks and equipped with a local read-out type NRF 560 with a measuring range of 0-28 metre manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21(93)/96]

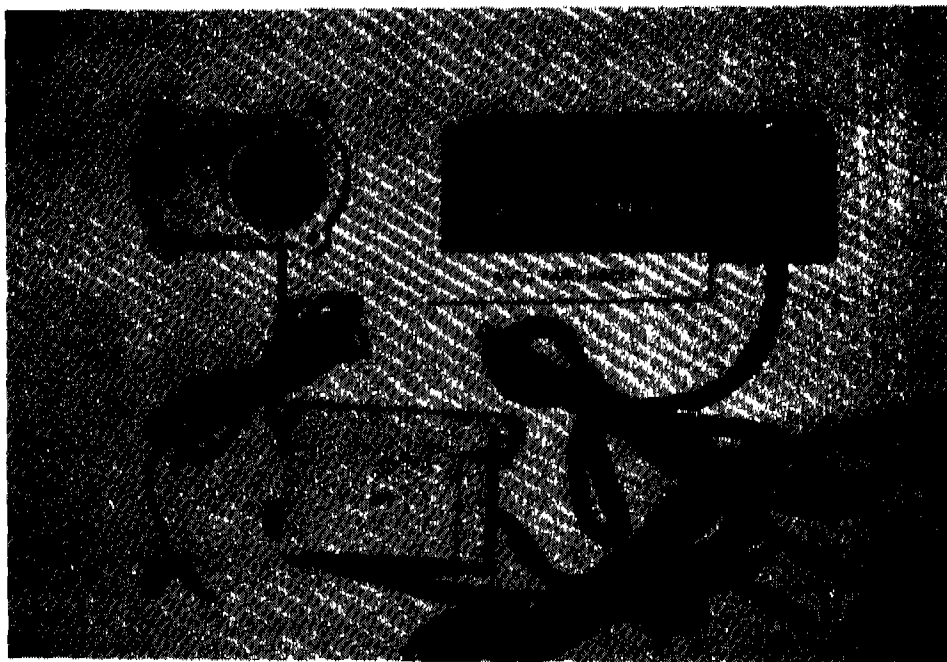
RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1998

का० आ० 1548.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना यह है कि अविरत उपयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ई टी-120 सीरीज के इलैक्ट्रॉनिक टैक्सी फेयर मीटर के मॉडल का जिसका ब्रांड नाम "पेरीकौल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स प्रीमियर इन्स्ट्रुमेन्ट्स एण्ड कंट्रोलस लिमिटेड पोस्ट बाक्स सं० 4209, पैरियाने केरपलायम, कोयम्बटूर-641020 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई०एन०डी०/10/98/2 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।

यह मॉडल इलैक्ट्रॉनिक टैक्सी फेयर मीटर का है और यह ई टी-120 सीरीज का "पेरीकौल" मॉडल है। इसमें दूरी और समय को मापने वाली युक्ति सम्मिलित है। यह लगातार बढ़ता है और यात्रा के किसी भी समय यात्री द्वारा संदेय "किराया" को प्रभार के रूप में उपदर्शित करता है। "संदेय किराया" तय की गई दूरी और सड़क परिवहन प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट गति से कम उसमें लगे समय सीमा का फलन है। किराया 5 अंकीय प्रकाशयुक्त इलैक्ट्रॉनिक युक्ति (एल ई डी) के संप्रदर्शन द्वारा उपदर्शित करता है।



आकृति

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(41)/97]

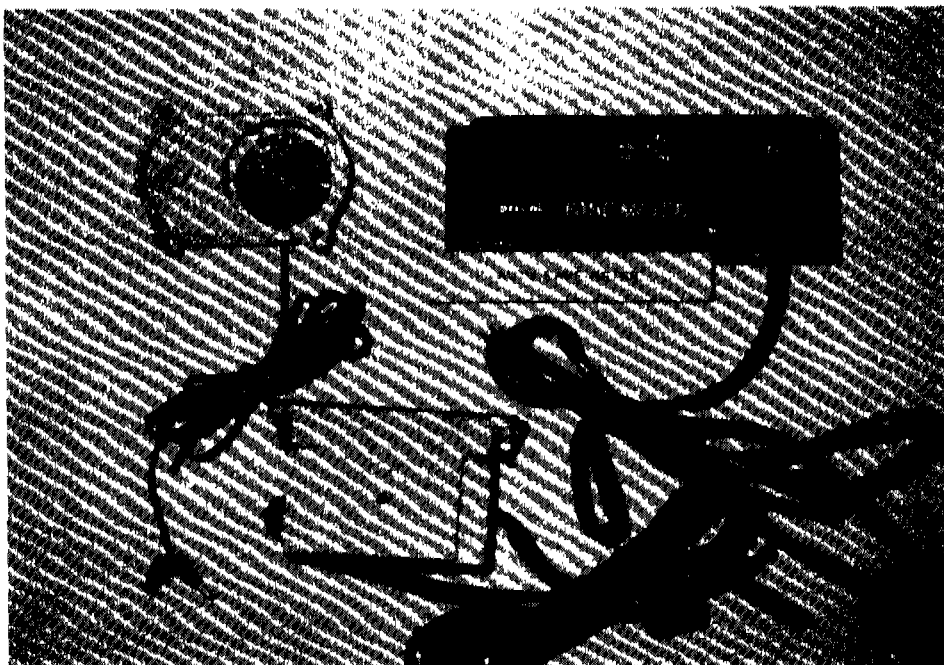
राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 1998

S.O. 1548.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of said act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the Electronic Taxi Fare Meter of 'ET-120' series with brand name "PRICOL" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s PREMIER INSTRUMENTS & CONTROLS LIMITED P.B. No. 4209, Perianaickenpalayam, Coimbatore-641020, and which is assigned the approval mark IND/10/98/2;

The said model is a Electronic Taxi Fare Meter and is of "PRICOL" Model ET 120 series. It is incorporated with a distance and time measuring device. It totalises continuously and indicates at any moment of journey, the charges payable by the passenger as 'fare' indication. The 'fare to pay', is a function of the distance travelled and the length of time occupied below a speed specified by road transport authorities. The fare is indicated by 5 digit LED display.



(Fig.)

[File No. WM-21(41)/97]

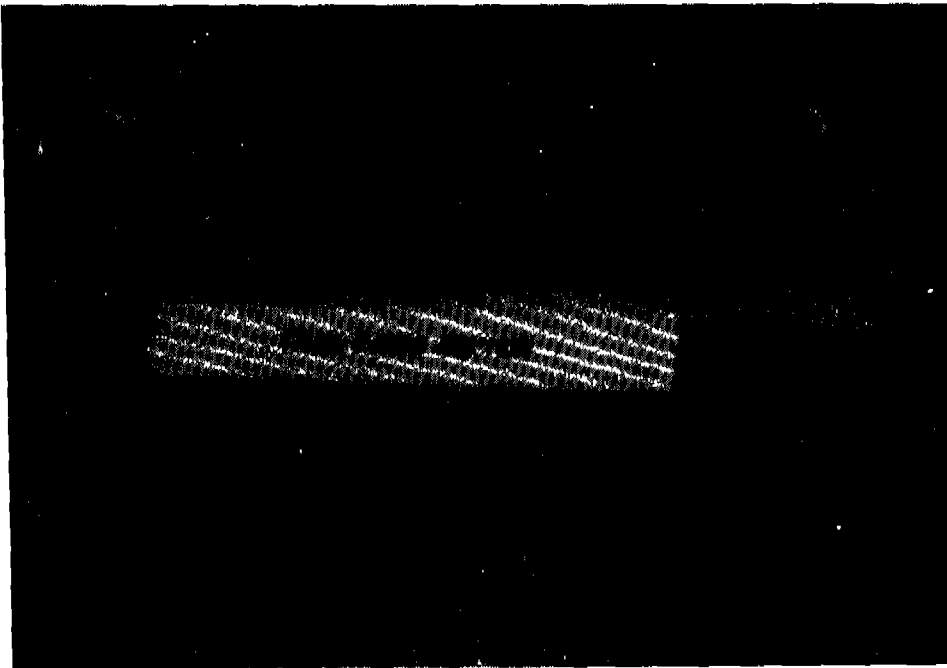
RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1998

का. आ. 1549.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुसरण है और संभावना यह है कि अविरत उपयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए '10 आर' सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक आटो फेयर मीटर के माडल का जिसका ब्रांड नाम "पैरीकौल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स प्रीमियर इन्स्ट्रुमेंट्स एण्ड कंट्रोल्ल्स लिमिटेड पोस्ट बाक्स सं. 4209, पेरियानेकेनपलायम, कोयम्बटूर 641020 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./10/98/3 समनुदेशित किया है अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी फेयर मीटर का है और यह 10 आर सीरीज का "पैरीकौल" माडल है। इसमें दूरी और समय को मापने वाली युक्ति सम्मिलित है। यह लगातार बढ़ता है और यात्रा के किसी भी समय यात्री द्वारा संदेश "किराया" को प्रभार के रूप में उपदर्शित करता है। "संदेश किराया" तय की गई दूरी और सड़क परिवहन प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट गति से कम उसमें लगे समय सीमा का फलन है। सामान आदि के परिवहन के लिए अन्य प्रभार किराया प्रभारों से प्रथक होंगे। किराया 7 अंकीय प्रकाशयुक्त इलेक्ट्रॉनिक युक्ति (एल ई डी) के संप्रदर्शन द्वारा उपदर्शित करता है।



(आकृति)

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(41)/97]

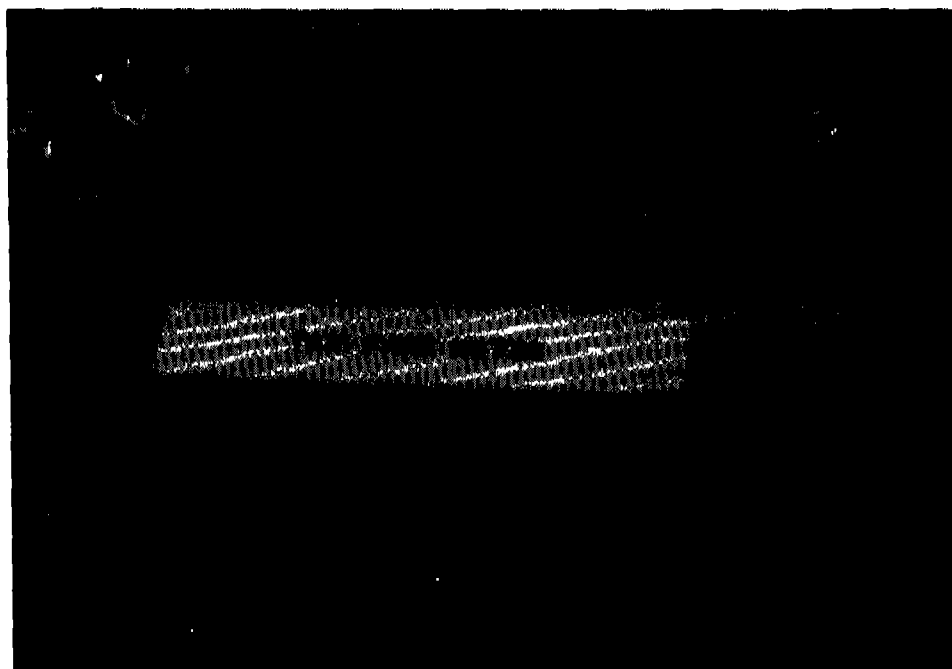
राजीव श्रीवास्तव अपर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 1998

S.O. 1549.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of said act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the Electronic Auto Taxi Fare Meter of '10 R' series with brand name "PRICOL" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s PREMIER INSTRUMENTS & CONTROLS LIMITED P.B. No. 4209, Perianaickenpalayam, Coimbatore-641020, and which is assigned the approval mark IND/10/98/3;

The said model is a electronic Auto Fare meter and is of "PRICOL" Model 10 R series. It is incorporated with a distance and time measuring device. It totalises continuously and indicates at any moment of journey, the charges payable by the passenger as "fare" indication. The 'fare to pay', is a function of the distance travelled and the length of time occupied below a speed specified by road transport authorities. The fare charges are independent of other charges like for transporting luggage etc. The fare is indicated by 7 digit LED display.



(Fig.)

[File No. WM 21(41)/97]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1998

का.आ. 1550.—केन्द्रीय सरकार/सरकारी परिसर अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 1971 का 40 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो कथित तालिका के कालम 2 में समरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित सरकारी परिसरों के संबंध में अपनी अधिकारिकता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सम्पदा अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेंगे :-

तालिका

अधिकारी का पद नाम	सरकारी परिसरों की श्रेणियां तथा अधिकारी की स्थानीय सीमाएं
1. प्रशासनिक अधिकारी भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल	भारतीय वन प्रबंध संस्थान सोसायटी, भोपाल तहसील जिला मध्य प्रदेश से संबंधित भोपाल या संस्थान की ओर से पट्टे लीज पर ली गयी अथवा प्राप्त सम्पत्तियां ।

[सं. 12-1/98-आर.टी.]

सर्वेश्वर झा, संयुक्त सचिव

Ministry of Environment & Forests

New Delhi, the 4th August, 1998

S.O. 1550.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column 1 of the table below, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table

I A B L E

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1. Administrative Officer, Indian Institute of Forest Management.	Premises belonging to or taken on lease or requisition by or on behalf of the Indian Institute Forest Management Society, Bhopal, Bhopal Tehsil, Bhopal District, Madhya Pradesh.

[No. 12-1/98-RT]

SARWESHWAR JHA, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1998

अधिसूचना

क्र.आ. 1551.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम के परिवहन के लिए कर्नाटक राज्य में मंगलूर से बेंगलूर तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि इस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है तो वह इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रतियों के जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि में उपयोग का अधिकार द्वारा भूमि में पाइपलाइन बिछाने पर लिखित रूप में आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, मंगलूर-बेंगलूर पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 7, मागडी रोड, बेंगलूर-560 023, कर्नाटक को कर सकेगा।

अनुसूची

राज्य: कर्नाटक

जिला: तुमकूर

तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं०	भाग/ हिस्सा सं० (यदि कोई है)	क्षेत्रफल एकड़-गुन्टा
1	2	3	4	5
तुरूवेकेरे	इंदुमारानाहल्ली	129		0 - 01
		116		0 - 20
		100		0 - 26
		12		0 - 08
		8		0 - 36
		13		0 - 13
		7		0 - 08
		6		0 - 02
		5		0 - 16
		29		0 - 18
		31		0 - 16
		132		0 - 18
		25		0 - 17
		26		0 - 13
		45		0 - 25
		47		0 - 03

1	2	3	4	5
		46		0 - 07
		44		0 - 02
		50		0 - 24
		43		0 - 02
		51		0 - 07
		61		0 - 09
		60		0 - 03
		52		0 - 03
		53		0 - 11
		57		0 - 04
		55		0 - 11
	डब्बेगट्टा	258		0 - 17
		259		0 - 16
		260		0 - 14
		265		0 - 18
		264	2	0 - 09
		302		0 - 10
		301		0 - 17
		300		0 - 13
		299		0 - 14
		298		0 - 17
		297		0 - 16
		296		0 - 13
		306		0 - 09
		307		0 - 09
		308		0 - 09

1	2	3	4	5
		309		0 - 10
		317		0 - 14
		16		0 - 02
		316		0 - 15
		7		0 - 26
		6		0 - 19
		5		0 - 12
		37		1 - 19
		48		1 - 06
		49		0 - 18
		33		0 - 12
		32		0 - 23
		31		0 - 19
		30		0 - 09
		109		0 - 12
		110		0 - 16
		112		0 - 18
		114		0 - 09
		113		0 - 25
		116		1 - 16
		117		1 - 27
	गुरलामाता	50		2 - 06
		17		0 - 05
		80		0 - 17
		76		0 - 15
		77		0 - 10

1	2	3	4	5
		78		0 - 19
		79		0 - 06
		69		0 - 15
		68		0 - 03
		67		0 - 15
		59		0 - 06
		66		0 - 01
		65		0 - 21
		62		0 - 09
		63		0 - 06
	इल्लेनाहल्ली कावल	7		4 - 22
		4		0 - 14
		3		0 - 11
		2		0 - 04
		1		0 - 01
	राचापुरा	88		1 - 05
	माविनाकेरे	136		3 - 08
	कारडागेरे	66		2 - 24
		67	4	0 - 29
		67	3	
		111		0 - 30
		55		0 - 02
		112		0 - 28
		32		0 - 32
		53		0 - 19
		41		1 - 03

1	2	3	4	5
		40		1 - 32
		42		0 - 11
		44		0 - 01
		46	1	0 - 38
		46	2	
		47		0 - 31
	दननायकनापुरादा कावल	113		0 - 32
		110		0 - 28
		108	2	0 - 22
		109		0 - 27
		121		0 - 04
		122		0 - 17
		127		0 - 31
		78		0 - 19
		77		0 - 24
		76		0 - 29
		76		0 - 19
		74		1 - 32
		73		0 - 09
		72		0 - 14
		5		0 - 07
		4		0 - 22
		3		0 - 22
		6		0 - 11
	दोड्डाबीरनाकेरे	168		0 - 01
		145		0 - 14

1	2	3	4	5
		146		0 - 25
		164		0 - 21
		143		0 - 07
		152		0 - 09
		140		0 - 20
		160		0 - 05
		161		0 - 14
		134		0 - 18
		132		0 - 43
		133		0 - 15
		130		0 - 28
		127		0 - 10
		120		0 - 01
		125		0 - 16
		126		0 - 23
		123		0 - 38
		75		0 - 32
		71		0 - 13
		198		0 - 19
		199		0 - 07
		200		0 - 08
		68		0 - 18
		67		0 - 13
		69		0 - 31
		19		0 - 03
		17		0 - 01

1	2	3	4	5
		14		0 - 26
		37		0 - 06
		38		0 - 28
		36		0 - 02
	रामासागर	37		0 - 32
		103		0 - 04
	ब्यातरा होसाहल्ली	66		1 - 06
		60		0 - 28
		59		0 - 09
		58		0 - 06
		55		0 - 13
		56		0 - 15
		11		0 - 03
		51		0 - 20
		38		0 - 09
		39		0 - 17
		40		0 - 05
		48		0 - 15
		47		0 - 09
	वराहासंद्रा	151		0 - 31
		153		0 - 02
		148		0 - 06
		156		0 - 02
		157		0 - 13
		158		0 - 02
		159		0 - 04

1	2	3	4	5
		160		0 - 02
		161		0 - 17
		137		0 - 01
		133		0 - 31
		132		0 - 05
		134		0 - 07
		130		0 - 01
		129		0 - 32
		127		0 - 03
		125		0 - 13
		124		0 - 02
		112		0 - 24
		113		0 - 13
		73		0 - 13
		72		1 - 11
		64		0 - 31
	मल्लेनाहल्ली	100		0 - 30
		101		0 - 2
		95		0 - 31
		94		0 - 05
		92		0 - 13
		91		0 - 10
		70		0 - 10
		71		0 - 20
		72		0 - 27
		73		0 - 17

1	2	3	4	5
		74		0 - 10
		81		0 - 16
		80		1 - 24
		79	5	0 - 02
	नेरिगे हल्ली	84		0 - 17
		86		0 - 28
		92		0 - 10
		89	1	0 - 19
		89	2	
		89	3	
		90	6	0 - 35
		90	8	
		90	9	
		90	10	
		91	1	0 - 05
		99		0 - 14
		100	1	0 - 18
		100	2	
		9	1	1 - 05
		9	2	
		9	3	
		9	4	
		9	5	
		8		0 - 30
		16		0 - 01
		17		0 - 28

1	2	3	4	5
	गविनाथापुरा	18		1 - 30
		19		0 - 18
		35		0 - 38
		36		0 - 01
		37		0 - 24
		33		0 - 33
		30		0 - 23
		31	1	0 - 20
		73		0 - 30
		74		0 - 20
		75		0 - 11
		3		0 - 17
		24	2	0 - 26
		24	3	
		25		0 - 10
कुणिगल	सिंघाट्टाहल्ली	62		2 - 14
		63		3 - 33
		7		0 - 08
	मदुरै कावल	1		12 -29
	चेतनाहल्ली	50		0 - 17
		35		0 - 04
		29		1 - 02
		28		0 - 06
		27		0 - 12
		15		0 - 19
		14		0 - 31

1	2	3	4	5
	हंपापुरा	13		0 - 01
		31		0 - 21
		32		0 - 17
		27		0 - 06
		33		0 - 19
		16		1 - 16
		17		0 - 06
	जड्डीगेरे	189		0 - 23
		188		0 - 39
		192		0 - 34
		186		0 - 09
		194		0 - 24
		195		0 - 02
		133		0 - 22
		132		0 - 06
		134		0 - 29
		130		0 - 26
		137		0 - 11
		138		0 - 09
	हेडिगेरे	96		1 - 08
		97	5	0 - 01
		91		0 - 14
		90		0 - 06
		89		0 - 13
		61		0 - 16
		88		0 - 05

1	2	3	4	5
		87		0 - 11
		86		0 - 06
		60		0 - 05
		62		0 - 02
		66		0 - 20
		67		0 - 22
		78		0 - 30
		79		0 - 15
	गुन्नागारा	112		1 - 14
		100		0 - 35
		99		1 - 13
		91		0 - 05
		92		0 - 07
		93		0 - 09
		94		0 - 28
		95		0 - 16
		96		0 - 09
		125		0 - 12
		128		0 - 07
		129		0 - 08
		131		0 - 10
		172		0 - 31
		171		0 - 17
		170		0 - 23
		180		0 - 20
		181		0 - 29

1	2	3	4	5
		182		0 - 01
		202		0 - 01
		183		0 - 26
		201		1 - 15
		190		1 - 15
		197		1 - 10
	रंगस्वामी बेट्टादा कावल	2	A	0 - 30
		2	B	
	रायगोनाहल्ली	52		1 - 05
		51		1 - 24
		50		0 - 11
		49		0 - 09
		48		1 - 14
		47		1 - 04
		38		0 - 13
		37		0 - 17
		30		1 - 04
		96		0 - 04
		97		11 - 00
		29		0 - 24
		27		0 - 11
		28		0 - 25
		24		1 - 32
		118		0 - 13
	वनागिरी	201		1 - 11
		146		0 - 09

1	2	3	4	5
		145		0 - 10
		143		0 - 01
		144		0 - 11
		141		0 - 09
		138		0 - 20
		124		0 - 30
		25		0 - 32
	भवटराहली	4		0 - 01
		35		0 - 36
		36		0 - 16
		23		1 - 19
		30		1 - 28
	कुरुडीहल्ली	89		1 - 04
		90		0 - 17
		70		0 - 12
		91		0 - 14
		69		0 - 12
		65		0 - 09
		64		0 - 29
		139		0 - 10
		58		0 - 30
		56		0 - 01
		62		0 - 30
	कुरुडीहल्ली चतुरवागा	41		0 - 01
		3		0 - 16
		45		0 - 05

1	2	3	4	5
		28		0 - 22
		3		0 - 03
		4		0 - 03
		5		0 - 04
		6		0 - 08
		7		0 - 10
		9		0 - 14
	बागेनाहल्ली	27		0 - 39
		28		0 - 29
		30		0 - 25
		31		0 - 06
		32		0 - 07
		33		0 - 06
		34		0 - 07
		35		0 - 08
		36		0 - 06
		38		0 - 07
		39		0 - 12
		40		0 - 02
		44		2 - 19
		45		1 - 09
	केंपासागर	119		0 - 03
		120		0 - 28
		121		0 - 34

1	2	3	4	5
		122		0 - 36
		127		0 - 21
		128		0 - 20
		129		0 - 17
		130		0 - 14
		151		0 - 02
		148		0 - 14
		149		0 - 02
		144		0 - 15
		143		0 - 29
		156		0 - 01
		157		0 - 25
		162		0 - 05
		163	1	1 - 04
		165		1 - 02
		166		0 - 23
		167		0 - 19
		8		0 - 18
		9		0 - 22
		10		0 - 17
		12		0 - 28
		11		0 - 08
		26		0 - 32
		25		0 - 24
		22		0 - 17
		21		0 - 17

राज्य : कर्नाटक

जिला : मंडिया

तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं०	भाग/ हिस्सा सं० (यदि कोई है)	क्षेत्रफल एकड़-गुन्टा
1	2	3	4	5
नागमंगला	सिद् दापुरा	58		2 - 38
		23	3	0 - 29
		23	4	
		23	5	
		24	1	0 - 31
		26	6	0 - 15
		27	2	0 - 36
		27	3	
		27	4	
		27	5	
		69		0 - 25
		34		1 - 16

राज्य : कर्नाटक

जिला: बेंगलूर-ग्रामीण

तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे सं०	भाग/ हिस्सा संख्या (यदि कोई है)	क्षेत्रफल एकड़-गुंटा
1	2	3	4	5
मागडी	नार यनपुरा	14		1 - 05
		16		0 - 16
	हेब्बालालु	100	1	0 - 22
		100	2	
		99		0 - 19
		98		0 - 19
		97		0 - 09
		94		0 - 16
		93		0 - 19
		87		2 - 16
		90		0 - 02
		89		0 - 03
		88		0 - 02
		40		0 - 06
		39		0 - 01
		42		0 - 06
		43		0 - 14
		44		0 - 12
		35		0 - 10
		34		0 - 17

1	2	3	4	5
		26		0 - 16
		29		0 - 27
		30		0 - 22
	सांकीगट्टा	215		0 - 11
	मुततागाहल्ली	41		0 - 26
		37		0 - 09
		40		1 - 28
		38		0 - 01
		24		0 - 20
		23		0 - 08
		22		0 - 09
		20		0 - 23
		16		0 - 14
		17	1	0 - 17
		17	2	
		14		0 - 14
		13		1 - 03
		12	4	0 - 02
	सांकीगट्टा कावल	37		0 - 21
		1		0 - 24
	हुल्लेनहल्ली	118		0 - 19
		120		0 - 03

1	2	3	4	5
		117		0 - 05
		122		0 - 05
		121		0 - 16
		123		0 - 12
		89		0 - 01
		90		0 - 27
		91		0 - 14
		92		0 - 28
		85		0 - 07
	पालेद हल्ली	24		1 - 02
		32		0 - 07
		34		0 - 12
		35		0 - 10
		36		0 - 10
		21		0 - 10
		18		0 - 13
		17		0 - 15
		1		0 - 39
		3		0 - 06
		5		0 - 18
		4		0 - 20
	बिसगुरू	81		0 - 27
		78		0 - 22
		82		1 - 02

1	2	3	4	5
		70		0 - 29
		69		0 - 13
		67		0 - 08
		65		0 - 08
		63		0 - 10
		60	1	0 - 19
		60	2	
		60	3	
		60	4	
		60	5	
		62		0 - 13
		49		0 - 08
		47		0 - 11
		43		0 - 23
		41		0 - 05
		39		0 - 11
		38		0 - 14
		34		0 - 14
		32		0 - 13
		30		0 - 06
		29		0 - 12
		28		0 - 16
		22		0 - 08
		21		0 - 31
	मुत्तासागर	28		0 - 01

1	2	3	4	5
		27		0 - 17
		25		0 - 12
		23		0 - 32
		22		0 - 09
		7		0 - 14
		4		0 - 09
		5		0 - 02
	बिसलाहल्ली	33		0 - 09
		34		0 - 10
		35		0 - 07
		41		0 - 01
		36		0 - 10
		38		0 - 20
		62		0 - 16
		60		0 - 18
	कृष्णापुरा	17		0 - 27
		16		0 - 15
		19		0 - 19
		20		0 - 18
		21		0 - 29
		18		0 - 01
		27		0 - 13
		26		0 - 20
		1		0 - 19

1	2	3	4	5
		3	1	0 - 26
		3	2	
		3	3	
		4		0 - 20
	बैरापुरा	58		0 - 25
		67		0 - 26
		66		0 - 23
		65		0 - 31
		74		0 - 17
		73		0 - 05
		71		0 - 39
		7		1 - 30
	मल्लीगुन्टे	43		2 - 15
		40		0 - 06
		39		1 - 01
		48		0 - 22
		50		0 - 22
		52		0 - 16
		53		0 - 35
		17		0 - 18
		18		0 - 24
		16		0 - 16
		20		1 - 30
		49		0 - 13

1	2	3	4	5
	केन्चनापुरा	5		0 - 32
	आरासिनागुन्टे	40		1 - 18
		41		0 - 28
		42		0 - 16
		43		0 - 31
		33		0 - 01
		52		0 - 39
		31		0 - 26
		30		0 - 08
		29		0 - 18
		25		0 - 13
		22		1 - 05
		15		0 - 11
		16		0 - 05
		13		1 - 01
		9		1 - 02
	ओमबट्नागुन्टे	26		1 - 03
		37		0 - 02
		35		0 - 31
		27		0 - 11
		29		0 - 26
		30		1 - 21

1	2	3	4	5
	तट्टेकेरे	64		1 - 29
		65		2 - 07
		66		1 - 30
		67		0 - 39
		68		0 - 28
	मुप्पेनाहल्ली	78		0 - 35
		77		1 - 26
		76		0 - 33
		65		1 - 06
		64		0 - 23
		62		0 - 10
		59		1 - 11
		61		1 - 13
	कन्केनाहल्ली	41		0 - 23
		39		0 - 45
		40	1	1 - 10
		40	2	
		19		0 - 45
		36		0 - 23
		20		0 - 04
		21		0 - 28
		15		0 - 37
		14		0 - 08
		13		0 - 19

1	2	3	4	5
		12		0 - 07
		18		1 - 12
		17		0 - 08
	बैरापुरा	6		1 - 06
		10		0 - 05
		11		0 - 12
		12		0 - 07
		13		0 - 10
		14		0 - 11
		15		0 - 08
		47		0 - 01
		48		0 - 16
		16		0 - 06
		17		0 - 09
	वड्डराहल्ली	43		0 - 01
		46	1	0 - 22
		46	2	
		63	1	0 - 35
		63	2	
		63	3	
		65		0 - 22
		66		0 - 12
		68		0 - 26
		5		0 - 22

1	2	3	4	5
		6		0 - 22
		7		0 - 04
	एनैगेरे	21		0 - 27
		23		0 - 21
		24		0 - 26
		27	1	0 - 28
		27	2	
		28		0 - 13
		29		0 - 01
		30		0 - 15
		14		0 - 10
		13		0 - 20
		36		0 - 05
		35		0 - 10
		34		0 - 16
		46		0 - 18
		45		0 - 08
		41		0 - 06
		77		0 - 31
		67	7	0 - 01
		67	8	
		68	1	0 - 15
		68	2	
		69		0 - 12
		70		0 - 27

1	2	3	4	5
		72		0 - 24
		73		1 - 25
		60	1	0 - 01
	कुप्पेमेला	21		0 - 16
		22		0 - 02
नैलमंगला	बैरासंदरा	171	1	0 - 19
		171	2	
		171	3	
		171	4	
		177		0 - 19
		169	1	0 - 22
		169	2	
		169	3	
		168		0 - 14
		166		0 - 24
		160		0 - 11
		159		0 - 09
		154		0 - 34
		151		0 - 30
		150		0 - 23
		149		0 - 06
		194		0 - 03
		202		0 - 18
		203		0 - 08

1	2	3	4	5
		204		0 - 11
		206		0 - 07
		207		0 - 13
		211		0 - 29
		114		0 - 13
		113		0 - 19
		80		1 - 01
		81		0 - 34
		78		0 - 05
		77		0 - 23
		61		0 - 04
		62		0 - 36
		60		0 - 29
		55		0 - 09
	हाजीपालया	22		0 - 32
		23		0 - 13
		27		0 - 06
	यालिचीगेरे	6		0 - 21
		5	1	0 - 33
		5	2	
		5	3	
		4		0 - 05
		12		0 - 01
		3		0 - 36

1	2	3	4	5
		2		0 - 24
		21		0 - 06
		29		0 - 04
		1		0 - 15
		30		0 - 23
		46		0 - 23
		47		0 - 14
		48		0 - 03
		49		0 - 22
		50		0 - 18
		52		0 - 18
		51		0 - 07
		88		0 - 30
		90		0 - 01
		68		0 - 07
		69		0 - 07
		70		0 - 32
		71		1 - 15
	ओबनायकनाहल्ली	4		0 - 34
		5	1	0 - 29
		5	2	
		6		0 - 11
	गंडारागोलीपुरा	34		0 - 12

1	2	3	4	5
	बैयादाराहल्ली	43	1	1 - 06
		43	2	
		43	3A	
		43	3B	
		43	4	
		43	5	
		44		0 - 02
		42		1 - 14
		41	1	0 - 20
		41	2	
		41	3	
		48		0 - 13
		25		0 - 18
		49	1	1 - 01
		49	2	
		49	3	
		49	4	
		51		0 - 01
		7	1	1 - 14
		7	2	
		7	3A	
		7	3B	
		7	3C	
		3		0 - 16
		4		0 - 33
		5		0 - 02

1	2	3	4	5
	विसवेसवरपुरा	32		0 - 15
		40		0 - 13
		41	1	1 - 02
		41	2	
		41	3	
	बसवनाहल्ली	88		0 - 29
		87		1 - 08
		91		0 - 10
		90		0 - 10
		4		0 - 28
		3		0 - 14
		7		0 - 20
		23		0 - 01
		9		0 - 15
		10		0 - 12
		11		0 - 02
		22		0 - 07
		32		0 - 29
		33		0 - 13
		34		0 - 20
	कुलिपुरा	69		0 - 14
		70		0 - 30
		71		0 - 22
	कृष्णराजापुरा	1		0 - 11
होसकोटे	डोड्डा अमानिकेरे	422	1	0 - 04
		422	2	

1	2	3	4	5.
		439		0 - 12
		438		0 - 09
		442		0 - 12
		437	1	0 - 15
		437	2	
		437	3A	
		437	3B	
		435	2B	0 - 04
		434		0 - 06
		433		0 - 02
	भक्ताराहल्ली	105		0 - 02
		106		0 - 23
		107		0 - 06
		108		0 - 07
		109		0 - 02
	मल्लसांदरा	105		0 - 01
		107		0 - 06
		108		0 - 05
		109		0 - 14
		126		0 - 15
		111	1	0 - 01
		125		0 - 13
		119		0 - 18
		118		0 - 05
		12		0 - 30
		15		1 - 01

1	2	3	4	5
	नडुवती	16		0 - 05
		27		0 - 36
		132		0 - 01
		130		0 - 39
		125		0 - 15
		124		0 - 13
		121		0 - 21
		120		0 - 01
		122		0 - 05
		119		0 - 08
		118		0 - 14
		117		0 - 28
		90		0 - 29
		101		1 - 00
		177		0 - 19
		88		1 - 14
		178		0 - 15
	अप्पाजीपुरा	179		0 - 19
		36		0 - 19
		37	1	0 - 15
		37	2	
		37	3	
		37	4	
		34	1	0 - 24
		34	2	
		2		0 - 25

1	2	3	4	5
		3		0 - 08
		4		0 - 06
		6		0 - 11
		9		0 - 02
		10		0 - 31
		11		0 - 02
	काचाराकानाहल्ली	76	3	0 - 01
		45	1	0 - 27
		45	2	
		46		0 - 29
		47		0 - 04
		48		0 - 26
		49		0 - 20
		52		0 - 17
		53		0 - 12
		54	2	0 - 08
		54	1	
		55	1	0 - 14
		55	2	
		62		0 - 20
		61	1	0 - 24
		61	2	
		60		0 - 22
		24		0 - 03
		23		0 - 20
	कनेकल्लु	151		0 - 13

1	2	3	4	5
		150		0 - 09
		149		0 - 11
		148		0 - 02
		147		0 - 10
		146		0 - 12
		163		0 - 02
		66		0 - 15
		59		0 - 08
		60		0 - 04
		65		0 - 05
		86		0 - 08
		84		0 - 07
		81		0 - 07
		87		0 - 05
		104		0 - 10
		105		0 - 13
		108		0 - 07
		107		0 - 02
		109		0 - 02
		23		0 - 14
		22		1 - 15
		21		0 - 32
	डोड्डादासराहल्ली	85		2 - 23
	तराबाहल्ली	23		3 - 28
		41		0 - 12
	देवनागोंडी	125		0 - 05

राज्य : कर्नाटक

जिला: बेंगलूर-नगर

तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे सं०	भाग/ हिस्सा सं० (यदि कोई है)	क्षेत्रफल एकड़-गुन्टा
1	2	3	4	5
बेंगलूर-उत्तर	सौदामियापाल्या	4	1	1 - 08
		4	2	
		4	3	
		5	1A	0 - 12
		5	1B	
		5	2	
		5	3	
		5	4	
		6	1	0 - 30
		6	2	
	बेट्नागेरे	148		0 - 30
		12		0 - 16
		11		1 - 10
		10		0 - 02
		9		1 - 20
		6		0 - 26
		151		0 - 06
		2		0 - 20
		44		0 - 20
		63		0 - 01

1	2	3	4	5
		62		1 - 14
		69		1 - 04
		56		0 - 20
		55		0 - 20
		54		0 - 11
	रामपालया	30		0 - 28
		31		0 - 12
		32		0 - 11
		33	1	0 - 24
		33	2	
		34		0 - 36
	हुसकुर	159		0 - 07
		158		0 - 37
		157		2 - 00
		147		0 - 12
		146		0 - 17
		145		0 - 13
		143		0 - 28
		142		1 - 12
	होनासांदरा	27	1A	1 - 02
		27	1B	
		27	1C	
		27	2	

1	2	3	4	5
		25	1A	0 - 35
		25	1B	
		25	1C	
		25	2	
		25	3	
		25	4	
		25	5	
		23	1	0 - 35
		23	2	
		23	3	
		21		0 - 03
		22	1A	1 - 03
		22	1B	
		22	1C	
		22	2	
		22	3	
		13		0 - 15
		11	2	0 - 26
		11	3	
		11	4	
	मत्तहल्ली	42		0 - 34
		43		0 - 05
		44		0 - 31
		47	8	0 - 38
		47	9	

1	2	3	4	5
		47	10	
		47	11	
		47	12	
		47	13	
		54	1A	0 - 19
		54	2	
		53		0 - 01
		55	1A	0 - 02
		55	1B	
		56		0 - 15
		110	1	0 - 26
		110	2	
		110	3	
		109	3	0 - 20
		112	3	0 - 01
		112	4	
		107		0 - 24
		113		0 - 01
		115	2	0 - 27
		115	3	
		115	4	
	नरसीपुरा	75		0 - 38
		77		0 - 14
		94	1	0 - 29
		94	2	

1	2	3	4	5
		92		0 - 03
		93		0 - 06
		5	2	0 - 22
		5	3	
		6	1	0 - 16
		6	2	
		15		0 - 12
		16		0 - 15
	तोरेगंनासांदरा	35	1	0 - 14
		36		0 - 17
		30	1	0 - 12
		30	2	
		29		0 - 14
		26	1	0 - 33
		26	2	
		31		0 - 01
		25	3	0 - 12
		23		0 - 09
		22		0 - 12
		19	5	0 - 17
		19	7	
		19	12	
		18		0 - 07
		17	1	0 - 21
		17	2	

1	2	3	4	5
		17	3	
		17	5	
		17	7	
		4	1	0 - 18
		4	2	
	केड़ागीतीरूमलापुरा	60		0 - 36
		56		0 - 26
		57	1	0 - 13
	हुरूलीचिकवनाहल्ली	25	2	0 - 25
		26		0 - 12
		27		0 - 10
		28		0 - 06
		1		0 - 19
		128		0 - 03
		127		0 - 16
		125		0 - 12
		126		0 - 02
		123	1	0 - 31
		65		0 - 08
		66		1 - 00
		67		0 - 22
		68		0 - 12
		69		2 - 14
		70		0 - 27

1	2	3	4	5
		71		0 - 04
	कुंबाराहल्ली	7		0 - 30
		6	1	0 - 19
		6	2	
		5	1	0 - 24
	केंपापुरा	30		0 - 39
	केसागट्टापुरा	37		0 - 01
		40	2	0 - 25
		38		0 - 07
		44	3	0 - 20
		44	4	
		50		0 - 10
		49		0 - 05
		48		0 - 10
		47		0 - 08
		46		0 - 08
		54		0 - 26
		58		0 - 20
	कालातम्मनाहल्ली	110		0 - 06
		111		0 - 35
		112		0 - 03
		113		0 - 03

1	2	3	4	5
		130		0 - 28
		129	1	0 - 27
		125		0 - 01
		128		0 - 33
		126		0 - 03
		127		0 - 20
		137	1	0 - 17
		137	2	
		137	3	
		138	1	0 - 20
		138	2	
		138	3	
		44		0 - 09
		1	1	0 - 02
	बयलाकेरे	63	3A	0 - 14
		63	3B	
		63	3C	
		62	1A	1 - 13
		62	1B	
		62	1C	
		62	2	
		62	3	
		62	4	
		62	5A	
		62	5B	

1	2	3	4	5
		62	5C	
		62	6	
		47	1	0 - 01
		48		1 - 12
		43	1	0 - 22
		43	2A	
		43	2B	
		39	2A	1 - 02
		39	2B	
		40	1A	0 - 25
		40	2	
		41		0 - 10
	मेड़ी अगराहारा	52		0 - 03
		51		0 - 12
		53	1	0 - 19
		53	2	
		53	3	
		53	4	
		53	5	
		53	6	
		55	1	0 - 19
		55	2	
		55	3	
		55	4	
		56		0 - 26

1	2	3	4	5
		11		0 - 07
		4	1	0 - 12
		4	2	
		4	3	
		4	4	
		5		0 - 04
		3		0 - 15
		20		0 - 08
		19		0 - 20
		22		0 - 08
	बड़े राहल्ली	42		0 - 17
		43		0 - 35
		44		0 - 16
		45		0 - 35
		46		0 - 30
	ओइबेट्टाहल्ली	13		1 - 11
		15		1 - 07
		16	1	0 - 08
		14		0 - 11
		19		0 - 32
		22		1 - 04
		20		0 - 06
		29		1 - 01
		39		1 - 03

1	2	3	4	5
		38		0 - 30
		50		0 - 37
		51		0 - 04
		52	1	0 - 30
		52	2	
		52	3	
	तिनडलूपलाटेशन	1		5 - 00
	अट्टुर	32		0 - 18
	तिनडलू	16		0 - 20
	चिक्कबोम्मासांदरा	6		0 - 33
	कोडीगीहल्ली पलांटेशन	1		6 - 27
	अल्लाल सांदरा	101		0 - 07
		87		1 - 26
		88		1 - 31
		84		0 - 02
	जक्कुर पलांटेशन	1		5 - 00
		4		1 - 23
	जक्कुर	103		0 - 16
		98		0 - 35

1	2	3	4	5
		91		1 - 15
		76		0 - 05
		85		1 - 20
		79		0 - 03
		78		0 - 26
		82		1 - 02
	श्री रामपुरा	61		0 - 03
		16		0 - 11
		15		0 - 16
		14		0 - 29
		13		1 - 06
		4		0 - 07
		32		0 - 06
		66		0 - 37
		31		0 - 31
		67		0 - 16
		30		1 - 12
बेंगलूर-दक्षिण	राचेनाहल्ली	113		0 - 20
		114		0 - 05
		107		0 - 08
		108		0 - 09
		109		0 - 10
		110		0 - 10
		111		0 - 10

1	2	3	4	5
		112		0 - 11
		95		0 - 14
	तनीसांदरा	87		0 - 37
		106		0 - 08
		105		0 - 13
		104		0 - 02
		89		0 - 27
		112		0 - 11
		93		0 - 20
		94		0 - 23
		110		0 - 01
		109		0 - 01
		108		0 - 01
		107		0 - 01
	कोत्तानुर नारायनपुरा	12		0 - 42
		10		0 - 11
		4		1 - 32
		3		0 - 01
	कोत्तानुर	25		0 - 05
		26		0 - 15
		28		0 - 28
		30		0 - 23
		32		0 - 10
		33		0 - 23
		50		1 - 09
	बैराती	6		0 - 16

1	2	3	4	5
		7		0 - 25
		8		0 - 24
		123		0 - 04
	कयलासानाहल्ली	11		1 - 21
		12		1 - 14
		16		0 - 03
		19		0 - 38
		18		0 - 30
		17		0 - 21
		72		0 - 15
	बिलेशिवाली	9		1 - 34
		7	2	0 - 13
		7	3	
		12	2	0 - 20
		15		0 - 12
		46		0 - 01
		45	1	0 - 05
		44		0 - 10
		43		0 - 03
		42		0 - 06
		35	1	0 - 08
		35	2	
		34		0 - 30
		32		0 - 12
		31		0 - 11
		29		0 - 03

1	2	3	4	5
		30		0 - 25
	बड़ेराहल्ली	4	1	0 - 33
		4	2	
		4	3	
		5	1	0 - 19
		5	2	
		13		0 - 37
	रामपुरा	40		0 - 21
		41		0 - 26
		42		0 - 39
		118		0 - 18
		71		0 - 08
		120		0 - 13
		70		0 - 22
		69	2	0 - 01
		60		0 - 33
		62		0 - 01
		59		0 - 01
		63		0 - 21
		65		0 - 06
		66		0 - 15
		78		0 - 01
		80		0 - 09
		81		0 - 19
		82		0 - 31
		85		0 - 07

1	2	3	4	5
	आडुर	53		0 - 33
		54	1	0 - 18
		54	2	
		52		0 - 20
		33		0 - 26
		34		0 - 09
		35		0 - 04
		39	4	0 - 04
		39	5	
		39	6	
		39	7	
		36		0 - 05
	हविनाने	21		0 - 14
		20		0 - 21
		19		0 - 04
		23		0 - 23
		24		0 - 07
		25		0 - 16
		14		0 - 09
		5		0 - 02
		4		0 - 22
	बिदराहल्ली	120		0 - 08
		119		1 - 25
		118		0 - 06

1	2	3	4	5
		117		0 - 02
	हेरंडाहल्ली	121		0 - 10
		122		0 - 19
		123	2	0 - 08
		123	3	
		128	3	0 - 13
		128	4	
		129		0 - 28
		130		0 - 01
		132		0 - 33
		133	1	1 - 14
		133	2	
		133	3	
		133	4	
		133	5	
		133	6	
		116		0 - 09
		134		0 - 08
		111		0 - 26
		110		0 - 14
		109		0 - 05
		108		0 - 11
		105		0 - 07
		104	1	0 - 07
		104	2	

1	2	3	4	5
		103	1	0 - 01
		103	2	
		102	2	0 - 04
		88		0 - 08
		89	1	0 - 33
		89	2	
		93	1B	0 - 24
		93	1C	
		93	2	
		66		1 - 14
		63		0 - 29
	आवलाहल्ली	17		0 - 23
		16		0 - 02
		18		0 - 18
		2		0 - 14
		3	1	0 - 02
		65		0 - 01
		1		0 - 01
		64		0 - 01
		50		0 - 13
		47		0 - 11
		46	1	0 - 22
		46	2	
		46	3	
		46	4	

1	2	3	4	5
		46	5	
		46	6	
		45		0 - 08
		44		0 - 07
		43		0 - 18
		42		0 - 39
		41		0 - 10
	बिदरे अगरहारा	68		0 - 13
		69		0 - 12
		70	1	0 - 25
		70	2	
		63		0 - 14
		62	3	0 - 05
		56		0 - 22
		55		0 - 17
		54	1	0 - 18
		54	2	
		54	3	
		54	4	
		54	5	
	डोड्डाबनाहल्ली	115		0 - 12
		120		0 - 12
		7		0 - 12
		12		0 - 27

1	2	3	4	5
		11		0 - 24
		3		0 - 13
	कन्नामंगला	164		0 - 12
		199		0 - 15
		197		1 - 09
		160		0 - 27
		157		0 - 22
		158		0 - 19
		141		0 - 36
		142	1	1 - 10
		142	2	
		89		0 - 13
		88		0 - 20
		87		1 - 04
		86		0 - 03
		85		0 - 23
	चिक्काबनाहल्ली	4		0 - 01
		5		0 - 19
		6		0 - 14
		7		0 - 20
		8		0 - 16
		10		0 - 20

(फा. सं० आर- 31015 / 4 / 98 -ओआर-II)

के.सी. कटोच, अवर सचिव

Ministry Of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 31th July, 1998

NOTIFICATION

S.O. 1551.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum from Mangalore to Bangalore in the State of Karnataka through Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying the said pipeline it is necessary to acquire the right of users in the land described in the scheduled annexed to this notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (I) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962, the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for the laying of the pipeline under the land to the competent authority, Mangalore - Bangalore Pipeline Project. Hindustan Petroleum Corporation Limited, No.7, Magadi Road, Bangalore-560023, Karnataka.

SCHEDULE**STATE : KARNATAKA****DISTRICT : TUMKUR
AREA**

Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Part/ Hissa No. (if any)	EXTENT Acre - Guntas
1	2	3	4	5
TURUVEKERE	Indumaranahalli	129		0 - 01
		116		0 - 20
		100		0 - 26
		12		0 - 08
		8		0 - 36
		13		0 - 13
		7		0 - 08
		6		0 - 02
		5		0 - 16
		29		0 - 18
		31		0 - 16
		132		0 - 18
		25		0 - 17
		26		0 - 13
		45		0 - 25
		47		0 - 03
		46		0 - 07
		44		0 - 02
		50		0 - 24
		43		0 - 02
		51		0 - 07
		61		0 - 09
		60		0 - 03
		52		0 - 03
		53		0 - 11
		57		0 - 04
		55		0 - 11
	Dabbeghatta	258		0 - 17
		259		0 - 16
		260		0 - 14
		265		0 - 18
		264	2	0 - 09
		302		0 - 10
		301		0 - 17
		300		0 - 13
		299		0 - 14
		298		0 - 17
		297		0 - 16
		296		0 - 13
		306		0 - 09
		307		0 - 09
		308		0 - 09

1	2	3	4	5
		309		0 - 10
		317		0 - 14
		16		0 - 02
		316		0 - 15
		7		0 - 26
		6		0 - 19
		5		0 - 12
		37		1 - 19
		48		1 - 06
		49		0 - 18
		33		0 - 12
		32		0 - 23
		31		0 - 19
		30		0 - 09
		109		0 - 12
		110		0 - 16
		112		0 - 18
		114		0 - 09
		113		0 - 25
		116		1 - 16
		117		1 - 27
	Gurlamata	50		2 - 06
		17		0 - 05
		80		0 - 17
		76		0 - 15
		77		0 - 10
		78		0 - 19
		79		0 - 06
		69		0 - 15
		68		0 - 03
		67		0 - 15
		59		0 - 06
		66		0 - 01
		65		0 - 21
		62		0 - 09
		63		0 - 06
	Illehalli Kaval	7		4 - 22
		4		0 - 14
		3		0 - 11
		2		0 - 04
		1		0 - 01
	Rachapura	88		1 - 05
	Mavinakere	136		3 - 08
	Karadagere	66		2 - 24
		67	4	0 - 29
		67	3	
		111		0 - 30
		55		0 - 02
		112		0 - 28
		32		0 - 32
		53		0 - 19
		41		1 - 03
		40		1 - 32
		42		0 - 11

1	2	3	4	5
		44		0 - 01
		46	1	0 - 38
		46	2	
		47		0 - 31
	Dananayakanapurada			
	Kaval	113		0 - 32
		110		0 - 28
		108	2	0 - 22
		109		0 - 27
		121		0 - 04
		122		0 - 17
		127		0 - 31
		78		0 - 19
		77		0 - 24
		76		0 - 29
		75		0 - 19
		74		1 - 32
		73		0 - 09
		72		0 - 14
		5		0 - 07
		4		0 - 22
		3		0 - 22
		6		0 - 11
	Doddabeeranakere	168		0 - 01
		145		0 - 14
		146		0 - 25
		164		0 - 21
		143		0 - 07
		152		0 - 09
		140		0 - 20
		160		0 - 05
		161		0 - 14
		134		0 - 18
		132		0 - 43
		133		0 - 15
		130		0 - 28
		127		0 - 10
		120		0 - 01
		125		0 - 16
		126		0 - 23
		123		0 - 38
		75		0 - 32
		71		0 - 13
		198		0 - 19
		199		0 - 07
		200		0 - 08
		68		0 - 18
		67		0 - 13
		69		0 - 31
		19		0 - 03
		17		0 - 01
		14		0 - 26
		37		0 - 06
		38		0 - 28

1	2	3	4	5
	Ramasagara	36		0 - 02
		37		0 - 32
		103		0 - 04
	Byatara Hosahalli	66		1 - 06
		60		0 - 28
		59		0 - 09
		58		0 - 06
		55		0 - 13
		56		0 - 15
		11		0 - 03
		51		0 - 20
		38		0 - 09
		39		0 - 17
		40		0 - 05
		48		0 - 15
		47		0 - 09
	Varahasandra	151		0 - 31
		153		0 - 02
		148		0 - 06
		156		0 - 02
		157		0 - 13
		158		0 - 02
		159		0 - 04
		160		0 - 02
		161		0 - 17
		137		0 - 01
		133		0 - 31
		132		0 - 05
		134		0 - 07
		130		0 - 01
		129		0 - 32
		127		0 - 03
		125		0 - 13
		124		0 - 02
		112		0 - 24
		113		0 - 13
		73		0 - 13
		72		1 - 11
		64		0 - 31
	Mallenahalli	100		0 - 30
		101		0 - 20
		95		0 - 31
		94		0 - 05
		92		0 - 13
		91		0 - 10
		70		0 - 10
		71		0 - 20
		72		0 - 27
		73		0 - 17
		74		0 - 10
		81		0 - 16
		80		1 - 24
		79	5	0 - 02

1	2	3	4	5
KUNIGAL	Nerigehalli	84		0 - 17
		86		0 - 28
		92		0 - 10
		89	1	0 - 19
		89	2	
		89	3	
		90	6	0 - 35
		90	8	
		90	9	
		90	10	
		91	1	0 - 05
		99		0 - 14
		100	1	0 - 18
		100	2	
		9	1	1 - 05
		9	2	
		9	3	
		9	4	
		9	5	
		8		0 - 30
		16		0 - 01
		17		0 - 28
		18		1 - 30
		19		0 - 18
	Gavinathapura	35		0 - 38
		36		0 - 01
		37		0 - 24
		33		0 - 33
		30		0 - 23
		31	1	0 - 20
		73		0 - 30
		74		0 - 20
		75		0 - 11
		3		0 - 17
		24	2	0 - 26
		24	3	
		25		0 - 10
	Shingattahalli	62		2 - 14
		63		3 - 33
	Maduri Kaval	7		0 - 08
		1		12 - 29
	Chetanahalli	50		0 - 17
		35		0 - 04
		29		1 - 02
		28		0 - 06
		27		0 - 12
		15		0 - 19
		14		0 - 31
		13		0 - 01
	Hampapura	31		0 - 21
		32		0 - 17

1	2	3	4	5
		27		0 - 06
		33		0 - 19
		16		1 - 16
		17		0 - 06
	Jaddigere	189		0 - 23
		188		0 - 39
		192		0 - 34
		186		0 - 09
		194		0 - 24
		195		0 - 02
		133		0 - 22
		132		0 - 06
		134		0 - 29
		130		0 - 26
		137		0 - 11
		138		0 - 09
	Hedigere	96		1 - 08
		97	5	0 - 01
		91		0 - 14
		90		0 - 06
		89		0 - 13
		61		0 - 16
		88		0 - 05
		87		0 - 11
		86		0 - 06
		60		0 - 05
		62		0 - 02
		66		0 - 20
		67		0 - 22
		78		0 - 30
		79		0 - 15
	Gunnagara	112		1 - 14
		100		0 - 35
		99		1 - 13
		91		0 - 05
		92		0 - 07
		93		0 - 09
		94		0 - 28
		95		0 - 16
		96		0 - 09
		125		0 - 12
		128		0 - 07
		129		0 - 08
		131		0 - 10
		172		0 - 31
		171		0 - 17
		170		0 - 23
		180		0 - 20
		181		0 - 29
		182		0 - 01
		202		0 - 01

1	2	3	4	5
		183		0 - 26
		201		1 - 15
		190		1 - 15
		197		1 - 10
	Rangaswamy Bettada			
	Kaval	2	A	0 - 30
		2	B	
	Rayagonahalli	52		1 - 05
		51		1 - 24
		50		0 - 11
		49		0 - 09
		48		1 - 14
		47		1 - 04
		38		0 - 13
		37		0 - 17
		30		1 - 04
		96		0 - 04
		97		11 - 00
		29		0 - 24
		27		0 - 11
		28		0 - 25
		24		1 - 32
		118		0 - 13
	Vanagere	201		1 - 11
		146		0 - 09
		145		0 - 10
		143		0 - 01
		144		0 - 11
		141		0 - 09
		138		0 - 20
		124		0 - 30
		125		0 - 32
	Bhakthrahalli	34		0 - 01
		35		0 - 36
		36		0 - 16
		23		1 - 19
		30		1 - 28
	Kurudihalli	89		1 - 04
		90		0 - 17
		70		0 - 12
		91		0 - 14
		69		0 - 12
		65		0 - 09
		64		0 - 29
		139		0 - 10
		58		0 - 30
		56		0 - 01
		62		0 - 30
	Kurudihalli Chaturbhaga	41		0 - 01

1	2	3	4	5
		43		0 - 16
		45		0 - 05
		28		0 - 22
		3		0 - 03
		4		0 - 03
		5		0 - 04
		6		0 - 08
		7		0 - 10
		9		0 - 14
	Bagenahalli	27		0 - 39
		28		0 - 29
		30		0 - 25
		31		0 - 06
		32		0 - 07
		33		0 - 06
		34		0 - 07
		35		0 - 08
		36		0 - 06
		38		0 - 07
		39		0 - 12
		40		0 - 02
		44		2 - 19
		45		1 - 09
	Kempasagara	119		0 - 03
		120		0 - 28
		121		0 - 34
		122		0 - 36
		127		0 - 21
		128		0 - 20
		129		0 - 17
		130		0 - 14
		151		0 - 02
		148		0 - 14
		149		0 - 02
		144		0 - 15
		143		0 - 29
		156		0 - 01
		157		0 - 25
		162		0 - 05
		163	1	1 - 04
		165		1 - 02
		166		0 - 23
		167		0 - 19
		8		0 - 18
		9		0 - 22
		10		0 - 17
		12		0 - 28
		11		0 - 08
		26		0 - 32
		25		0 - 24
		22		0 - 17
		21		0 - 17

STATE: KARNATAKA

DISTRICT: MANDYA

Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	AREA		EXTENT
			Sub-Division Hissa No. (if any)	Acres	Guntas
1	2	3	4	5	
NAGAMANGALA	Siddapura	58		2	38
		23	3	0	29
		23	4		
		23	5		
		24	1	0	31
		26	6	0	15
		27	2	0	36
		27	3		
		27	4		
		27	5		
		69		0	25
		34		1	16

STATE : KARNATAKA

DISTRICT : BANGALORE RURAL

AREA

Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Part/ Hissa No. (if any)	EXTENT Acres - Guntas
1	2	3	4	5
MAGADI	Narayanapura	14		1 - 05
		16		0 - 16
	Hebbalalu	100	1	0 - 22
		100	2	
		99		0 - 19
		98		0 - 19
		97		0 - 09
		94		0 - 16
		93		0 - 19
		87		2 - 16
		90		0 - 02
		89		0 - 03
		88		0 - 02
		40		0 - 06
		39		0 - 01
		42		0 - 06
		43		0 - 14
		44		0 - 12
		35		0 - 10
		34		0 - 17
		26		0 - 16
		29		0 - 27
		30		0 - 22
	Sankigatta Muttagadahalli	215		0 - 11
		41		0 - 26
		37		0 - 09
		40		1 - 28
		38		0 - 01
		24		0 - 20
		23		0 - 08
		22		0 - 09
		20		0 - 23
		16		0 - 14
		17	1	0 - 17
		17	2	
		14		0 - 14
		13		1 - 03
		12	4	0 - 02
	Sankigatta Kaval	37		0 - 21
		1		0 - 24
	Hullenahalli	118		0 - 19

1	2	3	4	5
		120		0 - 03
		117		0 - 05
		122		0 - 05
		121		0 - 16
		123		0 - 12
		89		0 - 01
		90		0 - 27
		91		0 - 14
		92		0 - 28
		85		0 - 07
	Paledahalli	24		1 - 02
		32		0 - 07
		34		0 - 12
		35		0 - 10
		36		0 - 10
		21		0 - 10
		18		0 - 13
		17		0 - 15
		1		0 - 39
		3		0 - 06
		5		0 - 18
		4		0 - 20
	Bisaguru	81		0 - 27
		78		0 - 22
		82		1 - 02
		70		0 - 29
		69		0 - 13
		67		0 - 08
		65		0 - 08
		63		0 - 10
		60	1	0 - 19
		60	2	
		60	3	
		60	4	
		60	5	
		62		0 - 13
		49		0 - 08
		47		0 - 11
		43		0 - 23
		41		0 - 05
		39		0 - 11
		38		0 - 14
		34		0 - 14
		32		0 - 13
		30		0 - 08
		29		0 - 12
		28		0 - 16
		22		0 - 08
		21		0 - 31
	Muthasagara	28		0 - 01
		27		0 - 17
		25		0 - 12
		23		0 - 32
		22		0 - 09

1	2	3	4	5
		7		0 - 14
		4		0 - 09
		5		0 - 02
	Bisalahalli	33		0 - 09
		34		0 - 10
		35		0 - 07
		41		0 - 01
		36		0 - 10
		38		0 - 20
		62		0 - 16
		60		0 - 18
	Krishnapura	17		0 - 27
		16		0 - 15
		19		0 - 19
		20		0 - 18
		21		0 - 29
		18		0 - 01
		27		0 - 13
		26	1	0 - 20
		1		0 - 19
		3	1	0 - 26
		3	2	
		3	3	
		4		0 - 20
	Bairapura	58		0 - 25
		67		0 - 26
		66		0 - 23
		65		0 - 31
		74		0 - 17
		73		0 - 05
		71		0 - 39
		7		1 - 30
	Malligunte	43		2 - 15
		40		0 - 06
		39		1 - 01
		48		0 - 22
		50		0 - 22
		52		0 - 16
		53		0 - 35
		17		0 - 18
		18		0 - 24
		16		0 - 16
		20		1 - 30
		49		0 - 13
	Kenchanaपुरa	5		0 - 32
	Arasigunte	40		1 - 18
		41		0 - 28
		42		0 - 16
		43		0 - 31
		33		0 - 01
		52		0 - 39
		31		0 - 26
		30		0 - 08
		29		0 - 18

1	2	3	4	5
		25		0 - 13
		22		1 - 05
		15		0 - 11
		16		0 - 05
		13		1 - 01
		9		1 - 02
	Ombathanagunte	26		1 - 03
		37		0 - 02
		35		0 - 31
		27		0 - 11
		29		0 - 26
		30		1 - 21
	Tattekere	64		1 - 29
		65		2 - 07
		66		1 - 30
		67		0 - 39
		68		0 - 28
	Muppenahalli	78		0 - 35
		77		1 - 26
		76		0 - 33
		65		1 - 06
		64		0 - 23
		62		0 - 10
		59		1 - 11
		61		1 - 13
	Kanakenahalli	41		0 - 23
		39		0 - 25
		40	1	1 - 10
		40	2	
		19		0 - 45
		36		0 - 23
		20		0 - 04
		21		0 - 28
		15		0 - 37
		14		0 - 06
		13		0 - 19
		12		0 - 07
		18		1 - 12
		17		0 - 08
	Balrapura	6		1 - 06
		10		0 - 05
		11		0 - 12
		12		0 - 07
		13		0 - 10
		14		0 - 11
		15		0 - 08
		47		0 - 02
		48		0 - 16
		16		0 - 06
		17		0 - 09
	Voddarahalli	43		0 - 01
		46	1	0 - 22
		46	2	
		63	1	0 - 35

1	2	3	4	5
NELAMANGALA	Ennegere	63	2	
		63	3	
		65		0 - 22
		66		0 - 12
		68		0 - 26
		5		0 - 22
		6		0 - 22
		7		0 - 04
		21		0 - 27
		23		0 - 21
		24		0 - 26
		27	1	0 - 28
		27	2	
		28		0 - 13
		29		0 - 01
		30		0 - 15
		14		0 - 10
		13		0 - 20
		36		0 - 05
		35		0 - 10
	Kuppemela Byrasandra	34		0 - 16
		46		0 - 18
		45		0 - 08
		41		0 - 06
		77		0 - 31
		67	7	0 - 01
		67	8	
		68	1	0 - 15
		68	2	
		69		0 - 12
		70		0 - 27
		72		0 - 24
		73		1 - 25
		60	1	0 - 01
		21		0 - 16
		22		0 - 02
		171	1	0 - 19
		171	2	
		171	3	
		171	4	
		177		0 - 19
		169	1	0 - 22
		169	2	
		169	3	
		168		0 - 14
		166		0 - 24
		160		0 - 11
		159		0 - 09
		154		0 - 34
		151		0 - 30
		150		0 - 23
		149		0 - 06
		194		0 - 03
		202		0 - 18

1	2	3	4	5
		203		0 - 08
		204		0 - 11
		206		0 - 07
		207		0 - 13
		211		0 - 29
		114		0 - 13
		113		0 - 19
		80		1 - 01
		81		0 - 34
		78		0 - 05
		77		0 - 23
		61		0 - 04
		62		0 - 36
		60		0 - 29
		55		0 - 09
	Hajlpalya	22		0 - 32
		23		0 - 13
		27		0 - 06
	Yalachigere	6		0 - 21
		5	1	0 - 33
		5	2	
		5	3	
		4		0 - 05
		12		0 - 01
		3		0 - 36
		2		0 - 24
		21		0 - 06
		29		0 - 04
		1		0 - 15
		30		0 - 23
		46		0 - 23
		47		0 - 14
		48		0 - 03
		49		0 - 22
		50		0 - 18
		52		0 - 18
		51		0 - 07
		88		0 - 30
		90		0 - 01
		68		0 - 07
		69		0 - 07
		70		0 - 32
		71		1 - 15
	Obanayakanahalli	4		0 - 34
		5	1	0 - 29
		5	2	
		6		0 - 11
	Gandragolipura	34		0 - 12
	Byadarahalli	43	1	1 - 06
		43	2	
		43	3A	

1	2	3	4	5
		43	3B	
		43	4	
		43	5	
		44		0 - 02
		42		1 - 14
		41	1	0 - 20
		41	2	
		41	3	
		48		0 - 13
		25		0 - 18
		49	1	1 - 01
		49	2	
		49	3	
		49	4	
		51		0 - 01
		7	1	1 - 14
		7	2	
		7	3A	
		7	3B	
		7	3C	
		3		0 - 16
		4		0 - 33
		5		0 - 02
	Visveswarapura	32		0 - 15
		40		0 - 13
		41	1	1 - 02
		41	2	
		41	3	
	Basavanahalli	88		0 - 29
		87		1 - 08
		91		0 - 10
		90		0 - 10
		4		0 - 28
		3		0 - 14
		7		0 - 20
		23		0 - 01
		9		0 - 15
		10		0 - 12
		11		0 - 02
		22		0 - 07
		32		0 - 29
		33		0 - 13
		34		0 - 20
	Koolpura	69		0 - 14
		70		0 - 30
		71		0 - 22
	Krishnarajapura	1		0 - 11
HOSKOTE	Hoskote Dodda Amanikere	422	1	0 - 04
		422	2	

1	2	3	4	5
		439		0 - 12
		438		0 - 09
		442		0 - 12
		437	1	0 - 15
		437	2	
		437	3A	
		437	3B	
		435	2B	0 - 04
		434		0 - 06
		433		0 - 02
	Bhaktharahalli	105		0 - 02
		106		0 - 23
		107		0 - 06
		108		0 - 07
		109		0 - 02
	Mallasandra	105		0 - 01
		107		0 - 06
		108		0 - 05
		109		0 - 14
		126		0 - 15
		111	1	0 - 01
		125		0 - 13
		119		0 - 18
		118		0 - 05
		12		0 - 30
		15		1 - 01
		16		0 - 05
		27		0 - 36
	Naduvathi	132		0 - 01
		130		0 - 39
		125		0 - 15
		124		0 - 13
		121		0 - 21
		120		0 - 01
		122		0 - 05
		119		0 - 08
		118		0 - 14
		117		0 - 28
		90		0 - 29
		101		1 - 00
		177		0 - 19
		88		1 - 14
		178		0 - 15
		179		0 - 19
	Appajipura	36		0 - 19
		37	1	0 - 15
		37	2	
		37	3	
		37	4	
		34	1	0 - 24
		34	2	

1	2	3	4	5
		2		0 - 25
		3		0 - 08
		4		0 - 06
		6		0 - 11
		9		0 - 02
		10		0 - 31
		11		0 - 02
	Kacharakanahalli	76	3	0 - 01
		45	1	0 - 27
		45	2	
		46		0 - 29
		47		0 - 04
		48		0 - 26
		49		0 - 20
		52		0 - 17
		53		0 - 12
		54	2	0 - 08
		54	1	
		55	1	0 - 14
		55	2	
		62		0 - 20
		61	1	0 - 24
		61	2	
		60		0 - 22
		24		0 - 03
		23		0 - 20
	Kanekallu	151		0 - 13
		150		0 - 09
		149		0 - 11
		148		0 - 02
		147		0 - 10
		146		0 - 12
		163		0 - 02
		66		0 - 15
		59		0 - 08
		60		0 - 04
		65		0 - 05
		86		0 - 08
		84		0 - 07
		81		0 - 07
		87		0 - 05
		104		0 - 10
		105		0 - 13
		108		0 - 07
		107		0 - 02
		109		0 - 02
		23		0 - 14
		22		1 - 15
		21		0 - 32
	Doddadasarahalli	85		2 - 23
	Tarabahalli	23		3 - 28
		41		0 - 12
	Devanagundi	125		0 - 05

STATE : KARNATAKA

DISTRICT : BANGALORE URBAN
AREA

Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Part/ Hissa No.	EXTENT Acres -Guntas
1	2	3	4	5
BANGALORE NORTH	Saidamia Palya	4	1	1 - 08
		4	2	
		4	3	
		5	1A	0 - 12
		5	1B	
		5	2	
		5	3	
		5	4	
		6	1	0 - 30
		6	2	
	Bethanagere	148		0 - 30
		12		0 - 16
		11		1 - 10
		10		0 - 02
		9		1 - 20
		6		0 - 26
		151		0 - 06
		2		0 - 20
		44		0 - 20
		63		0 - 01
		62		1 - 14
		69		1 - 04
		56		0 - 20
		55		0 - 20
		54		0 - 11
	Ramapalya	30		0 - 28
		31		0 - 12
		32		0 - 11
		33	1	0 - 24
		33	2	
		34		0 - 36
	Huskur	159		0 - 07
		158		0 - 37
		157		2 - 00
		147		0 - 12
		146		0 - 17
		145		0 - 13
		143		0 - 28

1	2	3	4	5
		142		1 - 12
	Honnasandra	27	1A	1 - 02
		27	1B	
		27	1C	
		27	2	
		25	1A	0 - 35
		25	1B	
		25	1C	
		25	2	
		25	3	
		25	4	
		25	5	
		23	1	0 - 35
		23	2	
		23	3	
		21		0 - 03
		22	1A	1 - 03
		22	1B	
		22	1C	
		22	2	
		22	3	
		13		0 - 15
		11	2	0 - 26
		11	3	
		11	4	
	Mathahalli	42		0 - 34
		43		0 - 05
		44		0 - 31
		47	8	0 - 38
		47	9	
		47	10	
		47	11	
		47	12	
		47	13	
		54	1A	0 - 19
		54	2	
		53		0 - 01
		55	1A	0 - 02
		55	1B	
		56		0 - 15
		110	1	0 - 26
		110	2	
		110	3	
		109	3	0 - 29
		112	3	0 - 01
		112	4	
		107		0 - 24
		113		0 - 01
		115	2	0 - 27
		115	3	
		115	4	

1	2	3	4	5
	Narasipura	75		0 - 38
		77		0 - 14
		94	1	0 - 29
		94	2	
		92		0 - 03
		93		0 - 06
		5	2	0 - 22
		5	3	
		6	1	0 - 16
		6	2	
		15		0 - 12
		16		0 - 15
	Torenagasandra	35	1	0 - 14
		36		0 - 17
		30	1	0 - 12
		30	2	
		29		0 - 14
		26	1	0 - 33
		26	2	
		31		0 - 01
		25	3	0 - 12
		23		0 - 09
		22		0 - 12
		19	5	0 - 17
		19	7	
		19	12	
		18		0 - 07
		17	1	0 - 21
		17	2	
		17	3	
		17	5	
		17	7	
		4	1	0 - 18
		4	2	
	Kodagithirumalapura	60		0 - 36
		56		0 - 26
		57	1	0 - 13
	Hurlichikkanahalli	25	2	0 - 25
		26		0 - 12
		27		0 - 10
		28		0 - 06
		1		0 - 19
		128		0 - 03
		127		0 - 16
		125		0 - 12
		126		0 - 02
		123	1	0 - 31
		65		0 - 08
		66		1 - 00
		67		0 - 22
		68		0 - 12

1	2	3	4	5
		69		2 - 14
		70		0 - 27
		71		0 - 04
	Kumbarahalli	7		0 - 30
		6	1	0 - 19
		6	2	
		5	1	0 - 24
	Kempapura	30		0 - 39
	Kasagattapura	37		0 - 01
		40	2	0 - 25
		38		0 - 07
		44	3	0 - 20
		44	4	
		50		0 - 10
		49		0 - 05
		48		0 - 10
		47		0 - 08
		46		0 - 08
		54		0 - 26
		58		0 - 20
	KalathamanaHalli	110		0 - 06
		111		0 - 35
		112		0 - 03
		113		0 - 03
		130		0 - 28
		129	1	0 - 27
		125		0 - 01
		128		0 - 33
		126		0 - 03
		127		0 - 20
		137	1	0 - 17
		137	2	
		137	3	
		138	1	0 - 20
		138	2	
		138	3	
		44		0 - 09
		1	1	0 - 02
	Byalakere	63	3A	0 - 14
		63	3B	
		63	3C	
		62	1A	1 - 13
		62	1B	
		62	1C	
		62	2	
		62	3	
		62	4	
		62	5A	
		62	5B	

1	2	3	4	5
		62	5C	
		62	6	
		47	1	0 - 01
		48		1 - 12
		43	1	0 - 22
		43	2A	
		43	2B	
		39	2A	1 - 02
		39	2B	
		40	1A	0 - 25
		40	2	
		41		0 - 10
	Medi Agrahara	52		0 - 03
		51		0 - 12
		53	1	0 - 19
		53	2	
		53	3	
		53	4	
		53	5	
		53	6	
		55	1	0 - 19
		55	2	
		55	3	
		55	4	
		56		0 - 26
		11		0 - 07
		4	1	0 - 12
		4	2	
		4	3	
		4	4	
		5		0 - 04
		3		0 - 15
		20		0 - 08
		19		0 - 20
		22		0 - 08
	Vaderahalli	42		0 - 17
		43		0 - 35
		44		0 - 16
		45		0 - 35
		46		0 - 30
	Doddabettahalli	13		1 - 11
		15		1 - 07
		16	1	0 - 08
		14		0 - 11
		19		0 - 32
		22		1 - 04
		20		0 - 06
		29		1 - 01
		39		1 - 03
		38		0 - 30
		50		0 - 37

1	2	3	4	5
		51		0 - 04
		52	1	0 - 30
		52	2	
		52	3	
	Thindlu Plantation	1		5 - 00
	Attur	32		0 - 18
	Thindlu	16		0 - 20
	Chikkabommasandra	6		0 - 33
	Kodagihally Plantation	1		6 - 27
	Allalasandra	101		0 - 07
		87		1 - 26
		88		1 - 31
		84		0 - 02
	Jakkur Plantation	1		5 - 00
		4		1 - 23
	Jakkur	103		0 - 16
		98		0 - 35
		91		1 - 15
		76		0 - 05
		85		1 - 20
		79		0 - 03
		78		0 - 26
		82		1 - 02
	Srirampura	61		0 - 03
		16		0 - 11
		15		0 - 16
		14		0 - 29
		13		1 - 06
		4		0 - 07
		32		0 - 06
		66		0 - 37
		31		0 - 31
		67		0 - 16
		30		1 - 12
BANGALORE SOUTH	Rachenahalli	113		0 - 20
		114		0 - 05
		107		0 - 08
		108		0 - 09
		109		0 - 10
		110		0 - 10
		111		0 - 10
		112		0 - 11
		95		0 - 14

1	2	3	4	5
	Thanisandra	87 106 105 104 89 112 93 94 110 109 108 107		0 - 37 0 - 08 0 - 13 0 - 02 0 - 27 0 - 11 0 - 20 0 - 23 0 - 01 0 - 01 0 - 01 0 - 01
	Kothanur Narayanapura	12 10 4 3		0 - 42 0 - 11 1 - 32 0 - 01
	Kothanur	25 26 28 30 32 33 50		0 - 05 0 - 15 0 - 28 0 - 23 0 - 10 0 - 23 1 - 09
	Bhairathi	6 7 8 123		0 - 16 0 - 25 0 - 24 0 - 04
	Kyalasanahalli	11 12 16 19 18 17 72		1 - 21 1 - 14 0 - 03 0 - 38 0 - 30 0 - 21 0 - 15
	Blleshivali	9 7 7 12 15 46 45 44 43 42 35 35 34 32	2 3 2 1 1 2	1 - 34 0 - 13 0 - 20 0 - 12 0 - 01 0 - 05 0 - 10 0 - 03 0 - 06 0 - 08 0 - 30 0 - 12

1	2	3	4	5
		31		0 - 11
		29		0 - 03
		30		0 - 25
	Vaderahalli	4	1	0 - 33
		4	2	
		4	3	
		5	1	0 - 19
		5	2	
		13		0 - 37
	Rampura	40		0 - 21
		41		0 - 26
		42		0 - 39
		118		0 - 18
		71		0 - 08
		120		0 - 13
		70		0 - 22
		69	2	0 - 01
		60		0 - 33
		62		0 - 01
		59		0 - 01
		63		0 - 21
		65		0 - 06
		66		0 - 15
		78		0 - 01
		80		0 - 09
		81		0 - 19
		82		0 - 31
		85		0 - 07
	Adoor	53		0 - 33
		54	1	0 - 18
		54	2	
		52		0 - 20
		33		0 - 26
		34		0 - 09
		35		0 - 04
		39	4	0 - 04
		39	5	
		39	6	
		39	7	
		36		0 - 05
	Hoovlnane	21		0 - 14
		20		0 - 21
		19		0 - 04
		23		0 - 23
		24		0 - 07
		25		0 - 16
		14		0 - 09
		5		0 - 02
		4		0 - 22

1	2	3	4	5
	Bidarahalli	120		0 - 08
		119		1 - 25
		118		0 - 06
		117		0 - 02
	Herandahalli	121		0 - 10
		122		0 - 19
		123	2	0 - 08
		123	3	
		128	3	0 - 13
		128	4	
		129		0 - 28
		130		0 - 01
		132		0 - 33
		133	1	1 - 14
		133	2	
		133	3	
		133	4	
		133	5	
		133	6	
		116		0 - 09
		134		0 - 08
		111		0 - 26
		110		0 - 14
		109		0 - 05
		108		0 - 11
		105		0 - 07
		104	1	0 - 07
		104	2	
		103	1	0 - 01
		103	2	
		102	2	0 - 04
		88		0 - 08
		89	1	0 - 33
		89	2	
		93	1B	0 - 24
		93	1C	
		93	2	
		66		1 - 14
		63		0 - 29
	Avalahalli	17		0 - 23
		16		0 - 02
		18		0 - 18
		2		0 - 14
		3	1	0 - 02
		65		0 - 01
		1		0 - 01
		64		0 - 01
		50		0 - 13
		47		0 - 11
		46	1	0 - 22
		46	2	

1	2	3	4	5
		48	3	
		46	4	
		46	5	
		46	6	
		45		0 - 08
		44		0 - 07
		43		0 - 18
		42		0 - 39
		41		0 - 10
	Bidara Agrahara	68		0 - 13
		69		0 - 12
		70	1	0 - 25
		70	2	
		63		0 - 14
		62	3	0 - 05
		56		0 - 22
		55		0 - 17
		54	1	0 - 18
		54	2	
		54	3	
		54	4	
		54	5	
	Doddabanahalli	115		0 - 12
		120		0 - 12
		7		0 - 12
		12		0 - 27
		11		0 - 24
		3		0 - 13
	Kannamangala	164		0 - 12
		199		0 - 15
		197		1 - 09
		160		0 - 27
		157		0 - 22
		158		0 - 19
		141		0 - 36
		142	1	1 - 10
		142	2	
		89		0 - 13
		88		0 - 20
		87		1 - 04
		86		0 - 03
		85		0 - 23
	Chikkabanahalli	4		0 - 01
		5		0 - 19
		6		0 - 14
		7		0 - 20
		8		0 - 16
		10		0 - 20

(File No. R-31015/4/98-OR II)

K.C.KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1998

का. भा. 1552.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार म. बी. सी. सी. एल. के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं-2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/353/92-आई आर (सी-1)]

अजय कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 13th July, 1998

S.O. 1552.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Govt. Industrial Tribunal, (No.-2) Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 13-7-98.

[No. L-20012/353/92-IR (C-1)]

AJAY KUMAR, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

Reference No. 185 of 1993

PARTIES :

Employers in relation to the management of Barora Coal Washery of M/s. B.C.C.L. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—None.

On behalf of the employers.—None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 30th June, 1998

AWARD

The Govt of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(353)/92-IR. (Coal-I), dated, the 3/9-11-93

SCHEDULE

"Whether the action of the Project Officer, Barora Coal Washery of M/s. BCCL. P.O. Nawagarh, Dt. Dhanbad in denying to promote Sh. Ram Kripal Singh, Fitter Operators Cat. V to Cat. VI w.e.f. May 1990 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. But none of the parties turned up nor took any steps. Then again notices were issued to them but in spite of the issuance of notices to them

they neither appeared nor took any steps. It therefore leads me to an inference that presently there is no dispute existing between the parties. In the circumstances, I have no other alternative but to pass a 'No dispute, Award' in this reference.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998

का. भा. 1553.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आर्डिनेंस फैक्ट्री, खमरिया जबलपुर के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/14/89-डी-2 (बी)]

वे. बी. बी. उण्णो, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th July, 1998

S.O. 1553.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ordnance Factory, Khamaria, Jabalpur and their workman which was received by the Central Government on 16-7-98.

[No. L-14012/14/89-D II (B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर
(म. प्र.)

डी. एन. दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

प्र. क्र. सीजीआईटी/एलसीआर/42/90

मोहम्मद ईसहाक खां

आत्मज नम्बू खां

चारखम्भा पुलिस चौकी

गोहलपुर के पीछे, जनता

माध्यमिक शाला पसियाना मस्जिद

शास्त्री बाईनं. 6, जबलपुर (म. प्र.)

विरुद्ध

महाप्रबंधक,

आर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया,

जबलपुर (म. प्र.)

...प्रतिपक्षी

अर्वाइ

दिनांकित : 3-8-1998

1. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या एल-14012/14/88-डी-2 (बी) दिनांकित 31-1-90 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है:—

अनुसूची

“व्याग्रार्डनेस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर के प्रबंधकों द्वारा श्री मोहम्मद ईसहाक खां अत्याज नव्बू खां एक्स-श्रमिक, टि. न. ए-3/2/53907, आर्डनेस फैक्ट्री जबलपुर की सेवाएं प्रबंधकों के आदेश दिनांक 2-6-88 से समाप्त किये जाने की कार्यवाही न्यायोचित है। यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किम अनुतोष का हक्दार है।”

2. श्रमिक मोहम्मद ईसहाक खान के अनुसार वह आर्डनेस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर में कार्यरत था। दिनांक 29-1-83 को उसे आरोप पत्र दिया गया, जिसमें उल्लेख था कि उसने फैक्ट्री की सम्पत्ति की चोरी की और उसका चाल-चलन संबद्धान्य है। श्रमिक के विरुद्ध विभागीय जांच इस आरोप पर हुई। जांचकर्ता अधिकारी ने आरोप सिद्ध पाए। श्रमिक को दिनांक 2-6-88 को सेवा में पृथक् किया गया। श्रमिक विभागीय जांच और उसके निष्कर्ष को चुनौती देता है। उनके अनुसार जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति नियमानुसार नहीं थी। जांचकर्ता अधिकारी ने विधिवत जांच नहीं की। श्रमिक की सहायक को मुविधा नहीं दी गई। जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष दोषपूर्ण है। श्रमिक चाहता है कि उसे पुनः सेवा में लिया जाए तथा नियम के अनुसार वेतन और भत्ते लगातार दिए जाए।

3. प्रबंधन के अनुसार दिनांक 5-1-83 को माय 5.55 पर जब श्रमिक की ललाड़ी ली गई तथा उसके कब्जे में एक वपड़े की थैली बरामद हुई, जिसमें 117 पीतल के खाली कारतूस थे। एक दूसरी थैली भी बरामद हुई, जिसमें पीतल की 7 किडो 530 ग्राम वजन की छद्म बरामद हुई। श्रमिक के विरुद्ध आरोप दि. 6-1-83 को लगाए गए और विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच विधिवत और नियमों के अनुसार है तथा श्रमिक पर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए। चूंकि श्रमिक ने फैक्ट्री के सामान की चोरी की थी, इस कारण उसे दण्ड दिया गया। प्रबंधन चाहता है कि श्रमिक को पुनः सर्विस में लिया जाये।

4. वर्तमान प्रकरण में श्रमिक के विरुद्ध जो विभागीय जांच हुई, उसका लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन को दिनांक 9-7-90 से लगातार विभागीय जांच के लेखों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दिनांक 1-9-94 को प्रकरण विभागीय जांच की वैधता के संबंध में तर्क हेतु नियत निगा गया। प्रबंधन विभागीय जांच के कागजात न्यायालय सेवापत्र ले गये। प्रबंधन ने 18-4-96 को कहा गया कि वह विभागीय जांच के कागजात प्रस्तुत करें। दिनांक 27-5-97 से 2-6-98 तक प्रबंधन को लगातार अवसर विभागीय जांच के कागजात प्रस्तुत करने के लिए दिए गये, किन्तु उनसे द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रबंधन ने लगातार मौका दिए जाने के बाद भी

विभागीय जांच के कागजात नहीं दिए हैं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को विभागीय जांच के कागजात उपलब्ध नहीं है। विभागीय जांच के कागजात देखना इस प्रकरण में आवश्यक है और बिना इनके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

5. दिनांक 24-2-98 को प्रबंधन अनुपस्थित हो गया। उनके विरुद्ध एक्पक्षीय कार्यवाही की गई।

6. अवार्ड दिया जाता है कि श्रमिक श्री मोहम्मद ईसहाक खान की सेवा समाप्ति का आदेश दिनांकित 2-6-88 अवैधानिक है। श्रमिक लगातार सेवा में माना जायेगा तथा उसे नियम के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धियां और प्रमोशन मिलेंगे। चूंकि श्रमिक ने 2-6-88 से आज की तारीख तक काम नहीं किया है, इस कारण इस अवधि का वेतन पाने का वह अधिकारी नहीं है। अवार्ड मुद्रित होने की दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रबंधन श्रमिक का वेतन निर्धारण करें और भुगतान करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो तीन माह के पश्चात् से भुगतान की तारीख तक इस राशि पर रुपये 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष श्रमिक को ब्याज प्रबंधन देगा। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

7. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियां भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी. एन. दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998

का.आ. 1554.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक नोट प्रेस देवास के प्रबंधन के संबंध निगोहों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-16012/2/93—आई आर (डी.यू.)]

के.वी.बी. उण्णा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th July, 1998

S.O. 1554.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank Note Press, Dewas (M.P.) and their workman, which was received by the Central Government on 16-7-98.

[No. L-16012/2/93-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय

जबलपुर म.प्र.

डी.एन. दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

प्र.क्र. सीजीआईटी/एलसी/आर/130/94

श्री कांतिलाल मंडलोई

आत्मज श्री गिरधारी मंडलोई,

9 एस.टी. कानूनगोवाखल, प्रार्थी

देवास (म. प्र.)

विरुद्ध

दी जनरल मेनेजर

बैंक नोट प्रेस

देवास-455 001 (म.प्र.) प्रतिप्राथी

अर्थात्

दिनांकित: 22-06-1998

1. भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या: एल-16012/2/93/आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 11-8-94 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है:—

अनुसूची

“Whether the action of the management of Bank Note Press, Dewas in terminating the services of Shri Kantilal Mandloie & Sri Girdharilal Mandloie by an order dated 23-4-98 is justified? If not, what relief he is entitled to?”

2. दोनों पक्षों को स्वीकार है कि श्रमिक कांतिलाल मंडलोई की नियुक्ति बैंक नोट प्रेस, देवास में गणक के पद पर वि. 19-10-85 को हुई थी। श्रमिक को दिनांक 10-8-89 को आरोप-पत्र दिया गया और इनके विरुद्ध विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में दो आरोप थे। प्रथम यह कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में शिक्षक के रूप में जुलाई 83 से दिनांक 17-10-85 तक कार्य किया था और यह तथ्य इन्होंने अपने आवेदन-पत्र में छिपाया था। दूसरा आरोप यह था, इन्होंने जब आवेदन-पत्र भरा, उस समय इनकी दो पत्नियां थी, किन्तु इस तथ्य को जानबूझकर इन्होंने छिपाया। इन दोनों आरोपों पर श्रमिक के विरुद्ध विभागीय जांच हुई। इस जांच में श्रमिक ने हिस्सा लिया और जांचकर्ता अधिकारी ने दोनों आरोपों में श्रमिक को दोषी पाया। नियुक्तिकर्ता अधिकारी ने जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट पर श्रमिक को सेवा से पृथक किया।

3. श्रमिक के अनुसार विभागीय जांच में उसे पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। श्रमिक विभागीय जांच में अध्यापक के माध्यम से अपने पक्ष का समर्थन करना चाहता था, परन्तु यह सुविधा उसे नहीं दी गई। श्रमिक ने कुछ

लेखों की मांग की, जो उसे नहीं दिए गए। श्रमिक के अनुसार जांच, नियमों के विपरीत है और निरस्त होने योग्य है। श्रमिक के अनुसार अगर आरोप सिद्ध भी माना जाए तो सेवा से पृथक करने का आदेश अत्यन्त कठोर है। श्रमिक के बर्ताव को देखते हुए सजा में परिवर्तन आवश्यक है।

4. प्रबंधन के अनुसार श्रमिक ने जानबूझकर यह तथ्य छिपाया कि वह मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सहायक अध्यापक था। श्रमिक ने जानबूझकर अपनी दूसरी शादी के संबंध में तथ्य छिपाए। विभागीय जांच विधिवत की गई तथा श्रमिक को पूरा अवसर अपना पक्ष समर्थन के लिए दिया गया। श्रमिक को दिया गया दण्ड कदाचार की गंभीरता को देखते हुए उचित है। श्रमिक के साथ किसी हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है।

5. इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 28-2-95 के द्वारा यह पाया कि श्रमिक के विरुद्ध जो विभागीय जांच की गई, वह विधिवत और नियमों के अनुसार है।

6. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष विधिवत है तथा क्या श्रमिक को उचित सजा दी गई है। श्रमिक ने अपने आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सहायक अध्यापक के पद पर जुलाई 83 से 17-10-85 तक कार्यरत था। जिस दिन श्रमिक ने यह फार्म भरा उस दिन वह सहायक अध्यापक था। नियमों के अनुसार अगर इस बात का उल्लेख श्रमिक आवेदन में करता तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाता, कारण यह है कि भर्ती नियमों में यह प्रावधान है कि जो अभ्यर्थी राज्य शासन या केन्द्र शासन के कर्मचारी हैं, वे अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र दें। इस प्रकार जो आवेदन इस वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा सीधे प्राप्त होते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाता। अभ्यर्थी श्रमिक का आवेदन विभागीय प्रमुख के माध्यम से नहीं भेजा गया, इस कारण यह नियमों के अनुसार विचार में नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में श्रमिक को बैंक नोट प्रेस में नियुक्त नहीं मिल सकती। इस तथ्य को छिपाने में श्रमिक ने जानबूझकर प्रबंधन को धोखा दिया है तथा सेवा समाप्ति की सजा उचित सजा है।

7. श्रमिक ने श्रीमति सुधा से दिनांक 7-8-83 को दूसरा विवाह किया। इनकी पहली पत्नि का नाम श्रीमति द्रौपदीबाई है। श्रमिक ने पद के लिए आवेदन दिनांक 27-9-84 को दिया, उसमें केवल एक पत्नि का पति होता दर्शाया। बाद में भी 12-10-85 को, 27-6-87 और 20-4-89 को श्रमिक ने जो अलग-अलग फार्म भरे, उसमें केवल एक पत्नि श्रीमति द्रौपदीबाई का नाम बताया। श्रमिक ने जानबूझकर गलत सूचना प्रबंधन को अपनी पत्नियों के बारे में दी। श्रमिक ने कभी भी प्रबंधन को यह नहीं बताया कि उसकी दो पत्नियां हैं। आवेदन पत्र भरने से पहले ही श्रमिक की दो पत्नियां थी। बैंक नोट प्रेस में प्रचलित

सेवा शर्तों के अनुसार जो भी अभ्यर्थी यह प्रकट करता है कि उसकी दो पत्नियाँ हैं, उनको नियुक्ति नहीं दी जाती। अगर श्रमिक यह बता देता तो उसे नियुक्ति नहीं मिलती। श्रमिक को सेवा में नियुक्ति और बातों के साथ इस आधार पर दी गई कि उसकी एक ही पत्नी है। श्रमिक ने प्रबंधन को अंगरे में रखकर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में जहाँ धोखा सिद्ध हो जाए वहाँ एक मात्र दण्ड सेवा में प्रथक करने का ही होता है।

8. मेरे मत में श्रमिक को उचित दण्ड दिया गया है और जाँच अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधिदत्त है।

9. अवार्ड दिया जाता है कि श्रमिक को सेवा से प्रथक करने का दण्ड उचित है तथा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

10. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियाँ भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं।

डी.एन. दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

का.आ.1555—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिवाजनल इंजीनियर, सीतापुर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-40011/46/95-आई.आर. (डी.यू.)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd July, 1998.

S.O. 1555.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Divisional Engineer, Sitapur and their workman, which was received by the Central Government on 22-7-1998.

[No. L-40011/46/95-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 106 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

State Secretary
National Union Line Staff and Class IV U.P. Circle
204 P&F Colony, Aliganj, Lucknow,

AND

The Telecom Divisional Engineer,
Sitapur.

APPEARANCES :

S. B. Singh—for the workman and
None—for the Management.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide Notification No. L-40011/46/95-IR (DU) dated 10-7-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Telecom Divisional Engineer, Sitapur in terminating the services of Sri Arun Kumar Dixit casual Lorry Driver is legal and justified? If not to what relief he is entitled to?

2. According to rules a claim statement like its pleading is required to be filed alongwith due verification of facts. The instant claim statement of the concerned workman Arun Kumar Dixit is defective inasmuch as it backs verification of facts. It has been alleged that the concerned workman has worked for more than 240 days in a year as Lorry Driver. His termination is bad but reasons have not been given. Even the date of appointment and termination have not been given. The details of provisions of which breach has been committed have also not been given.

3. The opposite party has not filed any reply. The concerned workman has filed 10 documents. On 1-4-98 the auth. representative S. B. Singh for the concerned workman informed the court that no oral evidence will be adduced.

4. Perhaps from the allegations that the concerned workman has worked for more than 240 days and no notice has been given the concerned workman want to plead breach of provisions of Section 25-F of I. D. Act. Simple averment is not enough. The date of appointment, the date of termination should have been given to ascertain these facts. Further in the absence of any oral evidence it is also not proved that the concerned workman was given notice pay or retrenchment compensation. Hence breach of provisions of Section 25-F of I. D. Act is not proved.

5. As there is neither any pleading nor there is any proof about breach of any other provisions of I. D. Act. it is held that termination of the concerned workman is not bad. Hence, my award is that termination of the concerned workman is not bad and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का.आ.1556—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सब-डिवीजनल ऑफिसर, टेलीकॉम, महाबनगर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद, नं. 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 40012/50/96-आई. आर. (डी यू.)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1556.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad. No. II as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sub-Divisional Offices, Telecom, Mahabubnagar and their workman, which was received by the Central Government on 24-7-98.

[No L-40012/50/96-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

**ANNEXURE
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-II, AT
HYDERABAD**

PRESENT .

Sri G. Bhoopathi Reddy, B.A., LL.B., Chairman.

Dated : 1-7-1998

I.D. No. 20/1998

(CENTRAL)

BETWEEN :

Sri S. Hazee.

H. No. 8-2-46/B.

Mettugadda.

Mahaboobnagar-500 007 (A.P.).

.. Petitioner.

AND

The Sub-Divisional Officer,

Telecommunications,

Mahaboobnagar-500 007.

.. Respondent.

APPEARANCES :

Petitioner being called absent.

Sri P. Damodhar Reddy, Addl. Standing Counsel
—for Respondent.**AWARD**

The Dispute is referred by the Ministry of Labour, Government of India vide their order No. L-40012/50/96-IR (DU) to adjudicate the dispute "Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Mahaboobnagar is justified in terminating the services of Sri S. Hazee, Ex-casual Mazdoor w.e.f 8-9-90 is legal and justified? If not what relief he is entitled to?"

The reference is received on 16-3-1998 and Registered on 18-3-98. Notices were issued through Registered Post to both parties to appear on 20-4-1998. Notice was not served on the petitioner, hence a fresh notice was issued through R.P.A.D. to the petitioner and the case was adjourned to 11-5-98. After receiving the notice the petitioner was called absent on 11-5-98 and Sri P. Damodhar Reddy, Addl. Standing Counsel filed memo of appearance for Respondent. The matter was adjourned to 8-6-98.

Finally today i.e., on 1-7-98 the Petitioner called absent despite service of notice. Hence the reference is closed and a 'NIL AWARD' is passed.

Dictated to the Typist corrected by me and given under my hand and the Seal of this Tribunal on this the 1st day of July, 1998.

G. BHOOPATHI REDDY, Chairman, Industrial Tribunal

APPENDIX OF EVIDENCE

No oral or documentary evidence has been adduced on either side.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

का.आ.1557—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ट ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(ii) में दिनांक 22 मार्च, 1997 को प्रकाशित श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 796(अ) दिनांक 4 मार्च, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में—

(i) क्रमांक 12 के सामने स्तम्भ सं.(3) के अश्वीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पंजाब राज्य और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़

(ii) क्रमांक 16 के नीचे निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

17. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/ हिमाचल प्रदेश
सहायक भविष्य निधि आयुक्त, हिमाचल राज्य
प्रदेश क्षेत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन।

[सं.आर-11013/2/90-एस.एस.-II]

जे.पी. शुक्ला, अवसर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 1998

S.O. 1557.—In exercise of the powers conferred by clause (kb) of Section 2 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Labour S.O. No 796 dated the 4th March, 1997 published in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated the 22nd March, 1997 namely :—

In the schedule to the said Notification :—

(i) Against Serial No. 12 under column (3) for the entries the following shall be substituted namely :—

"The State of Punjab and Union territory of Chandigarh.

(ii) Below serial No. 16 the following serial No. and entries shall be inserted namely :—

17. Regional Provident Fund Comm. The State of
sioners/Assistant Provident Fund Himachal Pradesh
Commissioners in Himachal Pradesh
Pradesh Region, of the Employee's
Provident Fund Organisation.

[No. R-11013/2/90-SS-II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1998

का.आ. 1558.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कम-लेबर-कोर्ट, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/24/95-आई.आर. (बी-I)]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

Ntw Delhi, the 15th July, 1998

S.O. 1558.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employer, in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 10-7-1998.

[No. L-12011/24/95-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. L. JATAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 78/93

Gurdev Singh

Vs.

State Bank of India.

For the workman—Shri Gurdev Singh.

For the management—Shri Ashok Khullar.

AWARD

The Central Government vide Gazette Notification No. L-12012/105/93-IR (B-I) dated 15th July 1993, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India in transferring Shri Gurdev Singh, Clerk, promoted from Subordinate cadre to Makhu Branch is legal and justified? If not to what relief the concerned workman is entitled to?"

Today the case was fixed for evidence of the management. Petitioner Gurdev Singh appeared and made the following statement :

"I do not want to pursue with the present reference as the management posted me at Morinda ADB Branch. The reference may be returned as not pressed."

In view of the above recorded statement of the workman, the present reference is returned as not pressed. Appropriate Government be informed.

Chandigarh

Dated : 15-6-1998.

B. L. JATAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998

का.आ. 1561.—श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, इन्दौर (एमपी) के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कम-लेबर-कोर्ट, जबलपुर (एम.पी.) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/65/93-आई.आर. (बी-1)]
पी.जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th July, 1998

S.O. 1561.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur (MP) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Indore (M.P.) and their workman, which was received by the Central Government on 15-7-1998.

[No. L-41012/65/93-IR (B-1)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
जबलपुर, म.प्र.

डी.एन. दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

प्र.क्र. सीजीआईटी/एनसी/(आर.)/(33)/95

श्री बाबूलाल सूर्यवंशी,

ग्राम : गुजरखेड़ा,

पोस्ट : मोहाव

जिला : इन्दौर (म.प्र.)

---प्रार्थी

विरुद्ध

दी डिबीजनल रेलवे मैनेजर,

पश्चिम रेलवे,

रतनाम (म.प्र.)

---प्रतिप्रार्थी

अर्वाई

दिनांकित : 22/6/1998

1. भारत सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या एल-41012/65/93-आई.आर. (बी) विनांकित 6/2/95 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

अनुसूची

"Whether the action of the management of Divisional Rly. Manager, W. Rly. Ratlam in terminating the services of Shri Baboolal Suryavanashi S/o Sh. Sawaji w.e.f. 16-10-92 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. दिनांक 16/7/97 को श्रमिक के अभिभाषक ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने विवाद को सही प्रकार से अधिकरण को नहीं भेजा है तथा वे इस संबंध में लिखित प्रतिवेदन देना चाहते हैं। दिनांक 5/11/97 को श्रमिक अनुपस्थित हुआ तथा उनके अधिकरण को सूचना देने के लिये आदेश दिया गया। दिनांक 17/2/98 को पुनः श्रमिक के अभिभाषक को सूचना देने के लिये आदेश हुआ दिनांक 30/3/98 को श्रमिक ने कैप इन्दौर में केस रखने की प्रार्थना की जो स्वीकार हुई। दिनांक 16-4-98 को श्रमिक कैम्प इन्दौर में उपस्थित नहीं हुआ। प्रबंधन का तर्क सुनकर अर्वाई के लिये नियत किया गया। श्रमिक को 4 अर्बसर रिफरेंस में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिये गये किन्तु उसने इन अवसरों का लाभ नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक की वर्तमान प्रकरण में रुचि नहीं है।

3. श्रमिक के अनुपस्थित रहने से यह अर्वाई दिया जाता है कि श्रमिक को किसी सहायता की पावता नहीं है। दोनों पक्ष इस प्रकरण पर अपना-अपना व्यय वहन करें।

4 नियमानुसार अर्वाइ की प्रतिष्ठा भारत सरकार
श्रम मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी. एन. वीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली 21 जुलाई 1998

का. प्रा. 1562.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय
सरकार नोर्दन रेलवे, लखनऊ के प्रबंधन के संबंध
नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण
कम-लेबर-कोर्ट कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती
है जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/59/94-आई.आर. (बी.-1)]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1998

S.O. 1562.—In pursuance of Section 17 of the Industrial
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the award of the Central Government
Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in
the Annexure, in the industrial dispute between the employers
in relation to the management of Northern Railway, Lucknow
and their workman, which was received by the Central
Government on 20-7-1998.

[No. L-41012/59/94-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 94 of 1996

In the matter of dispute :

BETWEEN

The Divisional Railway Manager
Northern Railway Hazratganj
Lucknow.

AND

Zonal Working President
Northern Railway Karamchari Union
96/196 Roshan Lane
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide Noti-
fication No. L-41012/59/94-IR, (B-I) dated 23-6-95, has
referred the following dispute for adjudication to this
Tribunal—

Whether the action of the management of Northern
Railway Lucknow in terminating the services of
Sri Ashish Kumar Barua Porter w.c.f. 11-6-87 is
just and legal? If not to what relief is the work-
man entitled to?

2. The case of the casual labour Ashish Kumar Barua
is that he was engaged as casual labour. In this regard he
was declared successful in medical test as well on 10-12-82.

He was given A-2 Grade. Accordingly w.c.f. 22-11-82, he
was appointed as substituted porter in the grade of Rs. 196-
232. As he has completed more than 240 days he has
attained temporary status as well. He has continuously worked
at Parwana Railway Station of the opposite party. From
11-6-87, his services were abruptly terminated in breach of
provisions of Section 25-F of I. D. Act. No notice pay and
retrenchment compensation was given to him, hence this
termination is bad.

3. The case of the opposite party is that the concerned
workman was a casual labour. He never attained temporary
status. He had not completed 240 days in a year. Further
he was never removed from service.

4. In the rejoinder, nothing new has been alleged.

5. In support of his case, the concerned workman Ashish
Kumar Barua has examined himself beside he has filed
Ext. W-1 to W-10. Out of which Ext. W-1 is relevant. It
is also pertinent to note that the opposite party railway has
not adduced any evidence. Ext. W-1 is the letter dated
20-12-82 which shows that the concerned workman should
be allowed to work as substitute porter against day to day
casual vacancies. He has passed medical examination in
A-2. Further it was admitted that he had worked prior
to 1-6-78 as well. Thus from this letter his appointment as
substitute porter has been proved which is the own docu-
ment of the railway. The concerned workman has stated
that he had completed more than 240 days in a year and
no retrenchment compensation and notice pay was given
to him. There is no evidence in rebuttal. Hence, I accept
it.

6. Accordingly it is held that the concerned workman has
completed for more than 240 days in a year but he was
not paid retrenchment compensation and notice pay hence
his termination is bad being in breach of provisions of
Section 25-F of I. D. Act. Accordingly my award is that
the concerned workman will be entitled for reinstatement
as substitute porter but without back wages.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 जुलाई 1998

का. प्रा. 1563.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय
सरकार पश्चिम रेलवे कोटा के प्रबंधन के संबंध
नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण
कोटा (राज.) के पंचपट को प्रकाशित करती है जो
केन्द्रीय सरकार को 22-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/47/94-आई.आर. (बी.-1)]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd July, 1998

S.O. 1563.—In pursuance of Section 17 of the Industrial
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal,
Kota (Raj.) as shown in the Annexure in the industrial
dispute between the employers in relation to the manage-
ment of Paschim Railway, Kota and their workman, which
was received by the Central Government on 22-7-1998.

[No. L-41011/47/94-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा (राज)
निर्देश प्रकरण क्रमांक अ०.न्या. (केन्द्रीय)-7/96
दिनांक स्थापित, 23/3/96

प्रसंग भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश
क्रमांक एल-41011/47/94-आई. आर. (बी-1)
दिनांक 19/3/96

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

कैलाशचन्द्र द्वारा मण्डल सचिव, पी.आर.के.पी.
स्टेशन रोड, कोटा।

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

मण्डल रेल प्रबन्धक, पश्चिम रेलवे, कोटा।

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि—श्री ए.डी. ओवर
प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि—श्री सी. एम. शर्मा
अधिनिर्णय दिनांक 20/5/98

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न
निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा
10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधि-
निर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :-

“Whether the action of the DRM, W. Railway,
Kota Division, Kota in allowing the
workmen S/Shri Mukhtiyar and Ram Dev
who were decategorised on medical un-
fitness from the post of Khalasi to
Chowkidar, in Trade test for promotion
to the post of Helper Khalasi Gr.
800—1150 and giving promotion to
them on the said post Debaring one Sh.
Kailash Chand, Khalasi is fair and
justified? If not, what relief the work-
man Sh. Kailash Chand is entitled?”

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर
किया गया व पक्षकारों को सूचना जारी की गयी। प्रार्थी
कर्मकार की ओर से क्लेम स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर संक्षेप में
तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि प्रतिपक्षी द्वारा
कर्मकार मुख्तियार व रामदेव जिन्हें खल्लासी के पद का
अनुभव भी नहीं था और जो निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण
श्रेणी-ब में भी अनुत्तीर्ण हो चुके थे, व अन्य प्रकार से भी
ट्रेड टेस्ट में बैठने के पात्र भी नहीं थे, उन्हें निर्धारित
प्रक्रिया में अनियमितता कर ट्रेड टेस्ट हेतु बुलाया गया
तथा ट्रेड टेस्ट में पास कर हैल्पर/खल्लासी के पद पर पदोन्नत
कर दिया गया जबकि प्रार्थी कर्मकार पूर्ण योग्यताधारक था,
उसे ट्रेड टेस्ट में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। प्रार्थी कर्मकार

द्वारा दुगारा ट्रेड टेस्ट पास भी कर लिया गया परन्तु उसे
पहले ट्रेड टेस्ट पास करने वाले उक्त कर्मकारों से वरीयता
में कनिष्ठ कर दिया गया जबकि प्रार्थी कर्मकार को भी
उक्त कर्मकारों को पदोन्नत किये जाने की निम्न से ही
पदोन्नत किया जाना चाहिए था और समस्त लाभ दिये
जाने चाहिए थे जो प्रतिपक्षी द्वारा नहीं दिये गये। अतः
क्लेम स्वीकार किया जावे।

3. प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से जवाब क्लेम प्रस्तुत
कर उक्त क्लेम को अस्वीकार किया गया है तथा किसी
प्रकार की कोई अनियमितता किये जाने से इन्कार किया
गया है और प्रार्थी के उक्त क्लेम को अस्वीकार किये जाने
का निवेदन किया गया है।

4. प्रार्थी कर्मकार को क्लेम समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत
किये जाने हेतु दि. 9-7-97 से निरन्तर अवसर प्रदान
किये जाते रहे हैं तदुपरान्त भी प्रार्थी कर्मकार द्वारा क्लेम
समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही
प्रस्तुत न किये जाने का आज तक कोई कारण ही दर्शाया
गया है। अतः प्रार्थी कर्मकार की साक्ष्य बन्द की गयी है।
जब प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत
नहीं करना चाहता है। अतः दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधि की
बहस सुनी गयी।

5. पत्रावली के अवलोकन पर यह स्पष्ट प्रकट हुआ
है कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रार्थी कर्मकार के प्रस्तुत क्लेम स्टेट-
मेन्ट को जवाब क्लेम प्रस्तुत कर पूर्णतः अस्वीकार किया
गया है तब प्रार्थी कर्मकार को क्लेम स्टेटमेन्ट को प्रमाणित
करना आवश्यक रहा है। प्रार्थी कर्मकार की क्लेम स्टेट-
मेन्ट समर्थन में कोई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य नहीं रही
है तब साक्ष्य अभाव में प्रस्तुत क्लेम प्रमाणित नहीं हुआ
है और प्रार्थी कर्मकार कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी
नहीं रहता है। अतः भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई
दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश को इसी प्रकार उत्तरित किया
जाता है।

इस अधिनिर्णय को समुचित सरकार को नियमानुसार
प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

जगदीश प्रसाद शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1998

का०आ० 1564.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय
सरकार उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० के प्रबन्ध-
तन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच,
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार
औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती
है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29012/76/96-आई०आर० (विधि)]

बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th July, 1998

S.O. 1564.—In pursuance of Section 17 of the Industrial
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the award of the Central Government
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in

the industrial dispute between the employers in relation to the management of U.P. Rajya Khanij Vikas Nigam Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 20-7-1998.

[No. L-29012/76/96-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 94 of 1993

In the matter of dispute :

BETWEEN

Kamlesh Srivastava
Member Pradesh Karyakarini
Bhartiya Mazdoor Sangh
32 Chakrata Road Dehradun.

AND

Senior Manager (Khanan)
U.P.S.M.D.C. Limited 58/1 Govind Nagar
Race Course Dehradun

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide Notification No. L-29012/76/96-IR. (Misc.) dated 14-5-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya Prabandhan U.P. Rajya Khanij Vikas Nigam Limited Dehradun dwara Sri V. K. Sharma ko dinank 31-10-91 se samaya vetanman na diya jana nyoyochit hai ? Yadi nahi to karmkar kis Tereekh se samaband vetanman diye jane ka adhikari hai ?

2. The case of the concerned workman Sri V. K. Sharma is that he was engaged as clerk A on 23-3-87, with the opposite party U.P.S.M.D.C. Limited Dehradun. From 23-3-88 he became regular electrician. The opposite party is denying regular pay according to pay scale its employees. The concerned workman is entitled for pay scale of 1380—2040 from 31-10-91, but the same was not paid.

3. The opposite party has also filed reply in which it has been alleged that these pay scale of selection grade is payable after completion of 7 years of service. As the concerned workman has not completed 7 years of service on 31-10-91, he is not entitled for these scale of pay.

4. In the rejoinder nothing new was alleged.

5. 3-3-98 was fixed for evidence. He did not turn up. In this way there is no evidence on behalf of the concerned workman to prove his case. In its absence my award is that the concerned workman is not entitled for scale of pay Rs. 1380—2040 w.e.f. 31-3-1991, for want of proof.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

कां.आ. 1565.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजस्थान स्टेट टंगस्टन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17-9-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29012/18/89-आई०आर० (विविध)]

बी. एम० डैविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd July, 1998

S.O. 1565.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan State Tungstone Development Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 17-9-1997.

[No. L-29012/18/89-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 94/89

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश

क्रमांक एल-29012/18/89-आर० (विविध)

दिनांक निल।

टंगस्टन साईन्स मजदूर संघ, डेगाना, जिला नागौर —प्रार्थी

बनाम

जनरल मैनेजर (ऑपरेशन), राजस्थान स्टेट टंगस्टन डेवलप-
मेंट कारपोरेशन लि०, जयपुर —अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री एस० के० बंसल, आर०एच०जे०एस०

प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री एम० एफ० बेग

अप्रार्थी निगम की ओर से : श्री जी० एल० माथुर

दिनांक अवार्ड : 10-6-1997

अवार्ड

भारत सरकार द्वारा यह अधिसूचना गिम्पानिडिन
विवादित बिन्दु का निर्णय करने के लिए प्रेसिड की गई है :

"Whether the action of the management of Rajasthan State Tungston Development Ltd., Jaipur in dismissing Shri R. S. Rathore, Helper from service w.e.f. 16-10-1988 vide order dated 15-10-1988 is just ? If not to what relief the workman concerned entitled ?"

2. प्रार्थी यूनियन ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश किया और उनका कथन है कि इस विवाद से सम्बन्धित श्रमिक श्री आर० एस० राठौड़ यूनियन का सक्रिय कार्यकर्ता है एवं वर्तमान में सेवा मुक्ति के समय भी वह उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। श्री आर० एस० राठौड़ को प्रथम नियुक्ति 11-6-76 को ब्लास्टर हैल्पर के पद पर की गई थी तथा वह मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता रहा परन्तु विपक्षी प्रबन्धक श्रमिक से यूनियन की गतिविधियों में सक्रिय होने से व्यक्तिगत रूप से नाराज रहते थे। यूनियन का यह भी कथन है कि आर० एस० राठौड़ की सेवाएं विपक्षी प्रबन्धक द्वारा 16-10-88 को समाप्त कर दी, सेवा-मुक्ति आदेश अनेक्सचर-2 है। यूनियन का यह भी कथन है कि आर० एस० ई० एम०डी०सी० लि० जयपुर द्वारा

श्रमिक श्री आर० एम० राठी को स्थानान्तरण प्रबन्धक के यहां 17 मई, 1978 को किया गया और स्थानान्तरण आदेश अनेक्सचर-3 है। यह भी कथन है कि श्रमिक को कार्य के बारे में प्रशंसा प्रमाण-पत्र अनेक्सचर-1 दिया गया और उसके कार्य के आधार पर श्रमिक को साईड सुपरवाइजर के पद पर 29-11-84 को पदोन्नत किया गया परन्तु यूनियन का पदाधिकारी होने के कारण उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिसके आदेश अनेक्सचर-3-ए है। यूनियन का यह भी कथन है कि श्रमिक को 11-8-87 को असत्य व निराधार तथ्यों पर अनेक्सचर-4 आरोप-पत्र दिया गया जिसमें उस पर आरोप लगाया गया कि श्रमिक आर० एम० राठी दिनांक 31-7-87 को प्रातः 8 बजे अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के बाद सर्वे विभाग में अधिकारी की अभुमति लिये बिना 8.20 मिनट पर प्रातः अपने कार्य-स्थान में चला गया पूरे दिन वापस ड्यूटी पर नहीं आया और अलिकेशन विभाग में जाकर श्री गणपतलाल फिरोदा व श्री बलराम, सहायक सुरक्षा अधिकारी के साथ अभद्र एवं झगड़ालू व्यवहार किया और अन्य कर्मचारियों को उकसाने की कोशिश की ताकि वे श्री फिरोदा व बलराम की पिटाई करें। यूनियन का कथन है कि श्रमिक ने आरोप-पत्र का जवाब अनेक्सचर-5 दिया जिसमें उसने स्पष्ट कहा कि उसने कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि श्री गणपतलाल ने बलराम के जरिये उसे बुलाया था और बुलाकर श्रमिक के पहुंचने ही नरपत सिंह ने साथ मिलकर गणपतलाल ने उसे लात व मुक्कों से पीटना शुरू किया और उसके कपड़े भी फाड़ दिये तथा उसकी जेब से 50/- रुपये व बच्चों के मेडीकल बिल व अन्य कागजात निकाल लिये। उसे दर्जीसिंह, मंगाराम, प्रभु व छोटू सिंह आदि लोगों ने आकर बीच-बचाव कर बचाया और इन्होंने निराधार तथ्यों के आधार पर श्रमिक के खिलाफ अनेक्सचर-7 एफ.आई.आर० दर्ज कराई जिसके आधार पर सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया है और आनी जिम्मेदारी में बचने के लिए झूठे आरोप लगाये गये हैं। यूनियन का यह भी कथन है कि श्रमिक के विरुद्ध इस घटना की अनेक्सचर-6 एफ.आई.आर० दर्ज करवाई गई जिसमें अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई। यूनियन का यह भी कथन है कि जांच निष्पक्ष एवं श्रद्धा व समुचित नहीं थी इसलिए उसकी सेवा-मुक्ति धारा 25-एफ, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जो बाद में अधिनियम कहलायेगा) के प्रावधानों की उल्लंघना में की गई है इसलिए, सेवा-मुक्ति को अवैध घोषित करते हुए श्री आर० एम० राठी को सभी लाभ सहित व से वेतन सेवा में बहाल किया जाये।

4. विपक्षी राज० स्टेट टंगस्टन विकास निगम ने जवाब पेश किया और उनका कथन है कि राजेन्द्र सिंह राठी की सेवाएं दिनांक 1-7-84 से विपक्षी के अधीन आर० एम० एम० डी० सी० से स्थानान्तरित हैल्पर के पद पर की गई थी। विपक्षी का यह भी कथन है कि 21-11-84 या किसी अन्य दिनांक से आर० एम० राठी की पदोन्नति साईड सुपरवाइजर के पद पर कभी नहीं की गई क्योंकि

प्रतिष्ठान में साईड सुपरवाइजर का कोई पद स्वीकृत नहीं था। और इस पद के लिए निर्धारित वेतनमान भी नहीं था। विपक्षी का यह भी कथन है कि आर० एम० राठी को बलराम सिन्धोराटी गाई नहीं बुलाकर लाया और आर० एम० राठी द्वारा 31-8-87 को जो घटना दर्ज करवाई गई है उसका मामला भी चल रहा है और उसे विभाग में विपक्षी जांच के परिणामस्वरूप दर्जित किया गया है जो कि सही है इसलिए क्लेम खारिज किया जाये।

5. दिनांक 9-10-92 की जांच अनुचित व अवैध मानी गई जिस पर विपक्षी को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। विपक्षी ने अपनी साक्ष्य में सर्वश्री प्रभात कुमार, प्रतापराम, नरपत सिंह, रामसिंह, गणपतलाल फिरोदा, बलराम व लक्ष्मणरास के शपथ-पत्र पेश किये हैं और लक्ष्मणरास का कोई प्रति-परीक्षण नहीं करवाया गया इसलिए उसका शपथ-पत्र साक्ष्य में नहीं पढ़ा जायेगा। अन्य शपथ-पत्रों पर प्रार्थी ने प्रति-परीक्षण किया। यूनियन की ओर से सर्वश्री छोटू सिंह, मंगाराम, राजेन्द्र सिंह राठी व प्रभुराम के शपथ-पत्र पेश किये गये हैं जिन पर विपक्षी ने प्रति-परीक्षण किया। प्रार्थी राजेन्द्र सिंह ने आय के बारे में शपथ-पत्र पेश किया जिस पर विपक्षी ने प्रति-परीक्षण किया।

6. दिनांक 1-2-95 को इस न्यायालय द्वारा हिन्दुस्तान जिक लि० को पक्षकार बनाया गया जिसकी ओर से भी जवाब पेश किया गया है उनका जवाब से कथन है कि पक्षकार सं० 2 दो ने डेगाना टंगस्टन परियोजना का व्यवसाय 30-1-91 के आपसी समझौते के अनुसार दिनांक 4-6-91 से हस्तगत किया एवं हस्तान्तरण के समय जिन श्रमिकों की सेवाएं हिन्दुस्तान जिक को स्थानान्तरित की गई एवं स्थानान्तरण के समय जिन श्रमिकों की सेवाएं हिन्दुस्तान जिक को स्थानान्तरित की गई जिन्होंने जिक लि० की सेवा में रहना स्वीकार कर अपनी सेवाएं हिन्दुस्तान जिक लि० को दीं, उन सूची में इस वाद में वर्णित प्रार्थी राजेन्द्र सिंह का नाम नहीं है इसलिए उसकी सेवाएं हिन्दुस्तान जिक लि० में कभी नियोजित नहीं हुई जिससे उनके खिलाफ कोई दादरसी प्रार्थी नहीं पा सकता। उनका यह भी कथन है कि कि टंगस्टन माइन्स मजदूर संघ यूनियन के साथ हिन्दुस्तान जिक लि० का द्विपक्षीय समझौता 16-3-94 को समझौता अधिकारी जयपुर के समक्ष हुआ जिसके पैरा सं० 5 में वर्णित सूची में 9 में से 7 श्रमिकों को दिनांक 19-3-94 को सेवा में लिया गया और अन्य 267 श्रमिकों को सूची के अनुसार सेवा में लिया गया इसलिए सूची के अंजावा नाम वाले श्रमिकों को नौकरी में लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विपक्षी सं० 2 के खिलाफ कोई क्लेम नहीं बनता इसलिए क्लेम खारिज किया जाये। उनका यह भी अभिकथन है कि विपक्षी का नाम इस स्टेज पर जोड़ना न्यायाधिकरण के कार्यक्षेत्र की सीमा से बाहर है क्योंकि न्यायाधिकरण को तो केवल उपरोक्त अधिसूचना का निर्णय करना है इसलिए प्रार्थी का क्लेम मय हर्जाने खर्चा खारिज किया जाये।

5. पक्षकारान के प्रतिनिधिगण की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में आरोप-पत्र अनैक्सचर-4 है जो निम्न-लिखित है :—

“आपके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसके अनुसार 31-7-97 को सुबह 8 बजे आपने अपनी ड्यूटी पर उपस्थिति देने के बाद सर्वे विभाग में अधिकारी की अनुमति लिये बिना 8.20 बजे (प्रातः-काल) अपने कार्य-स्थल से चले गये और पूरे दिन वापिस ड्यूटी पर नहीं आये। अपने कार्य-स्थल को छोड़ने के बाद आप ऐलोकेशन कार्यालय आफिस के पास गये। जहाँ आपकी कोई नियमित ड्यूटी नहीं है और न ही किसी अधिकारी ने आपको वहाँ बुलाया था। ऐलोकेशन कार्यालय में जाकर आपने तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक (उप खनिज अभियन्ता) श्री गणपतलाल फिलौदा एवं श्री बलराम सहायक सुरक्षा अधिकारी के साथ अभद्र एवं झगड़ालू व्यवहार किया। आपने एक बाहरी आदमी के (खदान पर कार्यरत नहीं) परियोजना परिसर में बिना अनुमति आने को श्री गणपतलाल फिलौदा के मना किये जाने पर उनके साथ झगड़ा किया और उनके साथ गाली-गलौज की। जब आपसे कहा गया कि आप ऐलोकेशन आफिस से निकल कर अपने कार्य-स्थल पर चले जायें तो आपने श्री फड़ोवा को और अधिक गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि आप परियोजना प्रांगण के बाहर गम्भीर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। उसके साथ ही आपने उपस्थित अन्य कर्मचारियों को उकसाने की कोशिश की कि श्री फड़ोवा और श्री बलराम की पिटाई करें। आपने यह झगड़ा सुबह 10.30 बजे तक जारी रखा। जिससे कि कई सुपरवाइजर एवं श्रमिक वहीं रुके रहे एवं खदान के कार्य में बाधा पड़ी।

उपरोक्त बातों को देखते हुए इस खदान पर लागू स्थाई आदेशों के तहत निम्नलिखित दुराचरण (मिसकण्डक्ट) आरोपित होते हैं :—

1. परियोजना प्रांगण में झगड़ा करना एवं दंगाई, अश्लील, नीच व्यवहार करना
(Figsuge Riolous disorderly and indecent behaviour within the premises of the project).
2. खदान के कार्य में जान-बूझकर बाधा पहुंचाना
(Causing wilful damage to the work in progress).
3. बिना अनुमति के अपने कार्य-स्थल को छोड़ना
(Leaving work without permission).

इस सन्दर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोपों को आप अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को 18-8-87 या उससे पहले प्रस्तुत करें। उक्त दिनांक तक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर या स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर आपके खिलाफ उचित नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।”

7. इस आरोप-पत्र में श्रमिक पर तीन आरोप लगाये गये हैं। प्रथम तो यह कि 31-8-87 को श्रमिक राजेन्द्र

मिह ने बलराम व गणपतलाल के साथ झगड़ा किया व अभद्र व्यवहार किया। दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि खान के कार्य में जान-बूझकर बाधा पहुंचाई और तीसरा यह कि बिना अनुमति के श्रमिक ने अपना कार्य-स्थल छोड़ा।

8. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री जी० एल० माथुर का तर्क है कि इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे सिद्ध होता है कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने 31-7-87 को सुबह 8.20 पर गणपतलाल के कार्यालय में जाकर गालियां दीं और अभद्र व्यवहार किया और गणपतलाल व बलराम के साथ मारपीट का प्रयत्न किया और यह भी साबित होता है कि वह अपने कार्य-स्थल पर पूरे दिन अनुपस्थित रहा इसलिए उसके खिलाफ अभद्र व्यवहार व झगड़ा करने के आरोप सिद्ध होते हैं। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करते हैं कि दूसरे कर्मचारियों को गणपतलाल व बलराम के साथ मारपीट करने के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध नहीं होता इसलिए वे इसे प्रेस नहीं करते। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में जो जांच करवाई गई थी वह भी पढ़ी जायेगी क्योंकि उसके अनुचित व अवैध होने से कोई प्रभाव नहीं है जिससे भी प्रार्थी के खिलाफ लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं और उसके खिलाफ जो दण्डादेश पारित किया गया है वह आरोपों की गम्भीर प्रकृति को देखते हुए सही है इसलिए इस दण्डादेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाये और क्लेम खारिज किया जाये। इस तर्क के समर्थन में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने हार्ई कोर्ट, केरला 1989 इटुकी डिस्ट्रिक्ट ऐस्टेट बनाम नेबर कोर्ट, एरनाकुलम वगैरह को पेश किया है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में यह वावरसी लम्बे असें बाद अगर कोई दी जायेगी तो अतः इस प्रकरण में पुनः सेवा में लेने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिये परन्तु अधिक से अधिक हर्जाना विलवाया जाना चाहिये। अपने इस तर्क के समर्थन में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने डब्ल्यू०एल०आर० 1994 (राजस्थान) 102 खूमा राम चौधरी बनाम रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज, जयपुर, डब्ल्यू०एल०आर० 1993 (राज०) 314, आर०एस०आर०टी०सी० बनाम हबीब खान को पेश किया है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में आर०एस०टी०डी०सी० का कार्य हिन्दुस्तान जिक लि० को 4-6-91 से हस्तान्तरित कर दिया गया व उसके समस्त अधिकार व जिम्मेदारियों भी हिन्दुस्तान जिक लि० में बिलय हो गई हैं इसलिए आर०एस०टी०डी०सी० इसके लिए जिम्मेदार नहीं है परन्तु हिन्दुस्तान जिक लि० इसके लिए उत्तरदायी है इसलिए कम्पनी के विरुद्ध प्रार्थी श्रमिक को कोई वावरसी नहीं दी जानी चाहिये और क्लेम राजस्थान राज्य टंगस्टल विकास निगम के खिलाफ खारिज किया जाना चाहिये। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में ए०आई०आर० 1970 (एस०सी०) 1217, बिहार रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन बनाम स्टेट ऑफ बिहार वगैरह को पेश किया है।

9. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री एम० एफ० बेग का जवाब में कहना है कि विपक्षी द्वारा गणपत लाल फिरोदा द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि 31-7-87 की घटना की थी प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दी गई थी, बाद में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया था जिसका मुकदमा 15-10-92 को निर्णीत हो चुका है और इसमें राजेन्द्र सिंह राठी व छोटू सिंह को बरी किया जा चुका है इसलिए प्रार्थी के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होता और विपक्षी द्वारा पेश की गई साक्ष्य को कि प्रार्थी ने झगड़ा किया, नहीं माना जाना चाहिये। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी का गणपत लाल फिरोदा द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में बरी हो जाना अपने आप में ऐसे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि प्रार्थी द्वारा कही गयी कहानी सत्य है और उसके द्वारा झगड़ा करना साबित नहीं होता और यह साबित होता है कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी के साथ झगड़ा किया गया इसलिए प्रार्थी के खिलाफ लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होते। यह भी तर्क है कि विपक्षी के साक्ष्य बलराम ने यह नहीं बताया कि क्या गालियां दी गई और विपक्षी के साक्ष्य राम सिंह राठी ने मारपीट करने से इन्कार किया है और प्रताप राम ने प्रति-परीक्षण में माना है कि राजेन्द्र सिंह व छोटू सिंह को बुलाने शेर सिंह गया था इसलिए इन परिस्थितियों में भी प्रार्थी द्वारा कोई झगड़ा करना साबित नहीं होता और विपक्षी द्वारा झगड़ा करना साबित होता है इसलिए उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जिससे आरोप सिद्ध होते हों। इसलिए प्रार्थी को दोष-मुक्त किया जाये यह भी तर्क है कि अगर यह भी माना जाये कि आरोप सिद्ध होते हैं तो भी अधिक से अधिक गणपत लाल फिरोदा के खिलाफ गालियां देने का आरोप सिद्ध होता है और यह ऐसा आरोप नहीं कि जिसमें किसी को सेवा-मुक्ति का दण्ड दिया जाये इसलिए यह दण्ड अधिक है इसलिए सेवा-मुक्ति के दण्ड को अपास्त करते हुए पुनः उसे सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाये। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने 1986 लैब०आई०सी० पेज 938 (मान० गुजरात उच्च न्यायालय) छोटालाल विठ्ठलदास बनाम डालर सॉल्ट एण्ड कैमीकल वर्क्स वर्ल्ड०एल०एल०जे० 1984, 546, वेद प्रकाश गुप्ता बनाम डैल्टन केबिल प्राइवेट लि० को पेश किया है।

10. गणपत लाल फिरोदा का शपथ-पत्र में कथन है कि :

1. मैं वर्तमान में हिन्दुस्तान जिक लि० संस्थान के टंगस्टन प्रोजेक्ट डेगाना में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ।

2. दिनांक 31-7-87 को मैं राजस्थान स्टेट टंगस्टन विकास निगम टंगस्टन प्रोजेक्ट डेगाना में उप-खनिज अभियंता के पद पर नियुक्त था, इस दिनांक को प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्यभार भी मेरे पास था।

3. दिनांक 31-7-87 को प्रातः 8 बजे से मैं परियोजना के एलोकेशन रूम में था व उम दिन के कार्य का एलोकेशन कर रहा था। मैंने कार्यालय के बाहर परियोजना के प्रांगण में भीड़ इकट्ठी देखी तब मैंने फोरसाल के ए० एस० ओ०

श्री बलराम जी को बुलाकर मालूम करने के लिए कहा कि श्रमिकों की भीड़ क्यों इकट्ठी है।

4. ए० एस० ओ० श्री बलराम ने मुझे बताया कि एक बाहरी व्यक्ति छोटसिंह जो कि जीवना बीमा निगम का एजेंट है ने भीड़ इकट्ठी कर रखी है मैंने छोटसिंह को बुलाया, छोटसिंह मेरे पास आया जब मैंने उससे कहा कि वे कार्य के समय नहीं आये इस पर उन्होंने मुझे कहा कि वे तो आयेगे और बर्गर श्रुतिमति के माइन्स में कहीं भी आने जाने का उनका अधिकार है। वे मेरे साथ बड़ी श्रद्धा से पेश आये। मैं छोटसिंह से बात कर ही रहा था कि राजेन्द्र सिंह राठी मेरे कमरे में आ गये वे बोले कि मेरे भाई को क्यों बुलाया है। श्री राजेन्द्र सिंह बड़े तेज से थे व मुझे गालियां दे रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे भाई को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और मुझे मां बहिन की गालियां देने रहे मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे कई आए और चले गये। तैम में गालियां बकते हुए हाथ उठा कर मुझे मारने मेरी ओर झपटे तभी वहां उपस्थित सुपरवाइजर व ए० एस० ओ० ने उसे पकड़ लिया। वहां उपस्थित नरपतसिंह राठी, रामसिंह माइनिंग मेट इत्यादि ने छोटसिंह व राजेन्द्रसिंह को पकड़ कर कमरे से बाहर ले गये। कमरे के बाहर जाकर भी राजेन्द्रसिंह बकता रहा व श्रमिकों को ललकारा कि अब मौका आ गया है इसको मज्जा चखाने का इसकी पिटाई करते हैं। राजेन्द्र सिंह ने मुझे धमकी दी कि डेगाना आना तुझे देख लूंगा और तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। फिर राजेन्द्र सिंह मोटर साईकिल पर बैठ कर डेगाना चला गया। व काम से अनुपस्थित रहा। इस घटना के कारण एलोकेशन कार्य में विलम्ब हुआ तथा श्रमिक विलम्ब से अपने कार्य पर पहुंचे जिससे उत्पादन को हानि हुई।”

11. गणपत लाल फिरोदा के शपथ पत्र का समर्थन प्रभात कुमार, प्रतापराम, नरपतसिंह, रामसिंह राठी व बलराम के शपथ पत्रों में होता है।

12. मेरे विचार में इनके शपथ पत्रों को नहीं मानने का कोई कारण नहीं। दूसरे केवल गणपत लाल द्वारा दर्ज कराई गई एफ० आई० आर० में प्रार्थी व उसके भाई को फौजदारी मुकदमें में बरी कर देने से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी द्वारा कहीं गई कहानी सही है परन्तु इस प्रकरण में जो साक्ष्य प्रकरण में प्रार्थी की ओर से आई है उसके मुकाबले में विपक्षी की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है। दूसरे प्रार्थी यह प्रकरण ले के आया है कि उसको बलराम के जरिये बुलाया गया और फिर उसके साथ एकदम मारपीट शुरू कर दी गई। प्रथम तो यह कि बलराम का यहीं यह कथन नहीं है कि उसके जरिये राजेन्द्र सिंह को बुलाया गया। दूसरे यह बात मानव व्यवहार में उचित प्रतीत नहीं होती कि किसी व्यक्ति को बुलाया जाये और काफी व्यक्तियों के समक्ष उसे बिना किसी कारण ही मारपीट की जाये। इसलिए प्रार्थी का कथन है कि उसने बलराम के जरिये बुलाया गया और उससे मारपीट की गई, माने जाने योग्य नहीं। तीसरे विपक्षीगण यह प्रकरण लेकर आये हैं कि छोटलाल राजेन्द्र सिंह का भाई शेर कर रहा था। जिससे उसे बुलाया गया और बुलाने पर उसने

गणपतलाल के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसका भाई राजेन्द्र सिंह भी आ गया जिसने भी अभद्र व्यवहार किया। यह तथ्य राजेन्द्र सिंह का भाई भी जानता है कि वह उस दिन राजेन्द्र सिंह वी भाईसह पर छोड़ने गया था। इस प्रकार छोटेसिंह उस परिस्थिति में उपस्थित था जो भी विपक्षी की साक्ष्य का कि छोटे सिंह वहां जो उपस्थित था, का समर्थन करता है। इन परिस्थितियों में छोटे सिंह, मंगाराम राजेन्द्रसिंह, व प्रभुराम का कथन कि राजेन्द्र सिंह को बलराम के जग्गि बुलाया था और बुलाने पर वह गया तो मारपीट शुरू कर दी, माने जाने योग्य नहीं और विपक्षी द्वारा जो झगड़ा शुरू होने का कारण दिया गया है, उचित है, इसलिये प्रार्थी की साक्ष्य को विपक्षी की साक्ष्य के मुकाबले नहीं माना जा सकता। इन परिस्थितियों में बलराम का यह कथन कि क्या गालियां दी थी उसे पता नहीं, का कोई प्रभाव नहीं क्योंकि गणपत सिंह ने अपने शपथ पत्र के प्रति परीक्षण में स्पष्ट कहा है कि उसकी यां चौद की गालियां दी थी। राम सिंह राठीड़ के प्रति परीक्षण में इस कथन का भी कोई प्रभाव नहीं है कि राजेन्द्र सिंह व फिरोछा राहव के बीच मारपीट नहीं हुई थी। क्योंकि गणपतसिंह फिरोदा का स्वयं का कथन है कि "तैश में गालियां बकते हुए हाथ उठाकर मुझे मारने मेरी ओर झपटे तभी वहां उपस्थित सुपरवाइजर व ए० एम० ओ० ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार गणपतलाल फिरोदा व रामसिंह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है इसलिये रामसिंह राठीड़ के बयानों से प्रार्थी को कोई मदद नहीं मिलती। प्रताप राम का कथन है कि छोटेसिंह को बुलाने फेरसिंह गया था, इस कथन का भी कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि विपक्षी को साक्ष्य विश्वसनीय है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र, गणपतलाल, प्रभात कुमार, नरपत सिंह, प्रताप राम राम सिंह, व बलराम के शपथ पत्रों से यह साबित होता है कि दिनांक 31-7-87 को गणपत लाल फिरोदा राजस्थान स्टेट टंगस्टन विकास निगम, टंगस्टन प्रोजेक्ट डेगाना में उप खनिज अभियन्ता के पद पर थे और एनोकेशन रूप में थे और उस समय छोटेसिंह वहां पर था और उसने भीड़ इकट्ठी कर रखी थी जिसपर छोटेसिंह को बुलाया और उसने आकर अभद्रता की। उसी समय राजेन्द्र सिंह भी आ गया और उसने गणपतलाल फिरोदा को गालियां दीं और अभद्रता का व्यवहार किया। गणपत लाल फिरोदा को मारने के लिए झपटा परन्तु कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया जिससे राजेन्द्र सिंह उसे मार नहीं सका। इन परिस्थितियों में छोटे सिंह, मंगाराम, राजेन्द्र सिंह व प्रभुराम के कथनों, कि झगड़ा गणपत लाल ने शुरू किया, नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रार्थी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती अतः उसे नहीं माना जा सकता।

13. मेरे विचार में अनुचित जांच के दौरान जो साक्ष्य ली गई है उसे इस हद तक ही पढ़ा जा सकता है जिसमें विपक्षी के गवाहान को प्रार्थी ने कन्ट्राडिक्ट करवाया हो। उसको अपनी साक्ष्य के समर्थन के काम में लिया गया हो और अन्य किसी साक्ष्य को जो अनुचित व अवैध साक्ष्य है, नहीं पढ़ा जा सकता। हाई कोर्ट, फेरला डूकों

डिस्ट्रिक्ट ऐस्टेट वर्कर्स यूनियन बनाए अभ न्यायालय में अभ न्यायालय ने हम बात को माना था कि श्रमिक को पूरा मौका नहीं दिया गया है, इसलिए अनिवार्य साक्ष्य ली गई थी, इन तथ्यों के आधार पर यह विशिष्टचय किया गया कि पुरानी जांच भी मटीरियल और रिकार्ड है। परन्तु इस प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं। इस प्रकरण में तमाम जांच को अनुचित माना गया है इसलिए पूरी जांच को रिकार्ड इस प्रकरण मटीरियल और रिकार्ड नहीं माना जा सकता। प्रदर्श एम-6, एम-4, एम-3, डब्ल्यू-6 भी प्रार्थी को कोई मदद नहीं करने क्योंकि इन दस्तावेजों में प्रार्थी को कोई मदद नहीं मिलती।

14. प्रार्थी श्रमिक पर दूसरा आरोप यह है कि उसने खदान के कार्य में जात-वृद्धकर बाधा पहुंचाई और तीसरा आरोप है कि बिना अनुमति के कार्य स्थल छोड़ा। इस सम्बन्ध में श्री प्रभात कुमार का शपथ-पत्र में निम्नलिखित कथन है:

"मैं टंगस्टन प्रोजेक्ट, डेगाना में सर्वे आफिसर के पद पर नियुक्त हूं। श्री राजेन्द्र सिंह राठीड़ मेरे अधीन हैल्पर था।

2. दिनांक 31-7-87 को राजेन्द्र सिंह प्रातः 8.00 बजे ड्यूटी पर आया था। मैं भी उस समय सर्वे आफिस में ड्यूटी पर था। लगभग 8.15 बजे राजेन्द्र सिंह मेरे से अनुमति लिये बगैर अचानक कार्यालय छोड़कर बाहर चला गया। राजेन्द्र सिंह के चले जाने के कुछ ही देर बाद मैंने एनोकेशन रूप से जोर-जोर से उसकी आवाजें आते सुनी। वह गालियां दे रहा था। कुछ समय बाद मैंने टाइम आफिस के बाहर ही हल्का सुना व देखा कि राजेन्द्र सिंह फौरमाल गाड़ों से हाथापाई कर रहा है।

3. दिनांक 31-7-87 को प्रातः 8.15 बजे कार्यालय छोड़ने के पश्चात् राजेन्द्र सिंह ड्यूटी पर दिन भर नहीं आया न ही कोई सूचना या अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र ही दिया।

4. पूर्व में भी राजेन्द्र सिंह दिनांक 6-6-87 व 21-7-87 को बगैर सूचना व अनुमति के अनुपस्थित रहा था।"

15. मेरे विचार में इस शपथ-पत्र को नहीं मानने का कोई कारण नहीं। दूसरे इस शपथ-पत्र के तथ्यों को कहीं प्रति परीक्षण में भी खण्डित नहीं किया गया। तीसरे विपक्षी ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि उसने बिना अनुमति के कार्यस्थल नहीं छोड़ा क्योंकि कार्यस्थल पर जाने से पूर्व ही निगम के अधिकारी जो डी०एम०ई० स्वयं हैं, ने प्रार्थी को बुलाया था। प्रार्थी को निगम के अधिकारियों द्वारा बुलाना साबित नहीं होना और प्रार्थी एवं गणपतलाल के बीच झगड़ा होना सिद्ध होता है किन्तु झगड़ा प्रार्थी द्वारा किया गया था इसलिए प्रार्थी का जवाब माने जाने योग्य नहीं है। इसलिए प्रभात कुमार के शपथ-पत्र

मे साबित होता है कि प्रार्थी उस दिन 8.00 बजे इयटी पर आया और 8.15 बजे इयटी से बिना अनुमति कार्यालय छोड़कर चला गया और इसके पश्चात् बिना अवकाश व बिना सूचना के सारे दिन कार्यालय से अनुपस्थित रहा। इसलिए उस पर बिना अनुमति कार्यालय छोड़ने का आरोप सिद्ध होता है। प्रार्थी श्रमिक ने अपने शपथ-पत्र में न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह अपने कार्य-स्थल में नहीं गया वरन् उसे बुलाया गया था। वास्तविकता यह है कि उसे गणपतलाल, बलराम, नरपतसिंह ने प्रांगण से बाहर निकाल दिया था। प्रार्थी का यह शपथ-पत्र माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा कथन उसने अपने प्रार्थना-पत्र में नहीं किया। दूसरा उसके द्वारा झगड़ा किया जाता सिद्ध होता है अतः प्रार्थी का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है। इसलिए राजेन्द्र सिंह पर लगाया गया यह आरोप कि खदान के कार्य में जान-बूझकर बाधा पहुंचाई और बिना अनुमति के अपना कार्य-स्थल छोड़ा, सिद्ध होता है। श्री गणपतलाल का शपथ-पत्र में कथन है कि वह काम से अनुपस्थित रहा इस घटना के कारण एलोकेशन कार्य में विलम्ब हुआ तथा श्रमिक विलम्ब से अपने कार्य-स्थल पर पहुंचे जिससे उत्पादन की हानि हुई। श्री रामसिंह राठीड़, नरपत सिंह का भी शपथ-पत्रों में ऐसा ही कथन है। प्रार्थी राजेन्द्र सिंह राठीड़ का अपने शपथ-पत्र में कथन है कि उस समय श्रमिकगण अपने कार्य पर आ चुके थे और उसने किसी श्रमिक को काम पर जाने से नहीं रोका।

16. मेरे विचार से विपक्षी की साक्ष्य के मुकाबले में इस साक्ष्य को नहीं माना जा सकता। अतः गणपतसिंह, रामसिंह व नरपत सिंह के शपथ-पत्रों से साबित होता है कि एलोकेशन कार्य में विलम्ब हुआ जिससे श्रमिकगण कार्य पर विलम्ब से पहुंचे और कार्य में हानि हुई। इस प्रकार खदान कार्य में जान-बूझकर झगड़ा करके बाधा पहुंचाई। अतः प्रार्थी पर लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं। आज जो मेरे समक्ष स्थाई आदेश पेश किये गये हैं उनके अनुसार खण्ड 13 के उप-खण्ड 9, 11 व 21 के अन्तर्गत ये दुराचरण की परिभाषा में आता है। मेरे विचार में श्रमिक द्वारा अपने अधिकारी को बिना किसी कारण जान-बूझकर गाली-गलौच करना व उसको मारने के लिए दौड़ना गम्भीर दुराचरण है और गम्भीर अनुशासनहीनता का प्रतीक है। खण्ड 13 के उपखण्ड 9, 11 व 21 निम्नलिखित हैं:—

13. Disciplinary action for misconduct.—A workman may be suspended for a period not exceeding 4 days at a time. Fined or dismissed without notice or compensation lieu of notice, if he is found guilty of misconduct:

(ix) drunkenness, fighting, riotous or disorderly or indecent behaviour within the premises of the project.

(xi) Causing willful damage to the work in progress or to any property of the project.

(xxi) Leaving work without permission.

17. इस प्रकरण में भी श्रमिक राजेन्द्र सिंह ने अपने उच्चाधिकारी गणपतलाल फिरौदा के साथ बिना किसी कारण गाली-गलौच की और उसको मारने का प्रयास किया परन्तु

श्रमिकों के बीच-बचाव के कारण वह मारपीट नहीं कर सका। दूसरे प्रार्थी राजेन्द्र सिंह ने यह कृत्य गणपतलाल उच्च अधिकारी के साथ उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के समक्ष व उसके कार्यालय में ही किया इसलिए इसकी गम्भीरता और भी बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता के प्रकरण मे मेरे विचार में सेवा-मुक्ति के दण्ड को बहाल नहीं किया गया तो फील्ड में काम करना कठिन ही नहीं असम्भव हो जायेगा। तीसरे इस प्रकरण में प्रार्थी राजेन्द्र सिंह ने अपने उच्चाधिकारी से बिना कारण झगड़ा किया और फिर कार्य से अनुपस्थित रहा, ये तथ्य उसके कृत्य की गम्भीरता को और भी बढ़ा देता है जिससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी को अपने उच्च अधिकारी की कोई इज्जत नहीं। चौथे खदान कार्य में झगड़ा करने के कारण बाधा हुई एवं विलम्ब हुआ और इससे उत्पादन में गिरावट हुई जिससे भी देश का ही नुकसान हुआ। अतः यह आरोप भी श्रमिक के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकार प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के खिलाफ लगाये गये तीनों ही आरोप गम्भीर हैं और इन परिस्थितियों में प्रार्थी को जो सेवा-मुक्ति का दण्ड दिया गया है वह उचित है और उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। मेरे इस विचार का समर्थन उख्य. एल. प्रार. 1995 (2190) 314 प्रार. आर.टी.सी. बनाम हबीब खान से भी होता है। 1984—एल.एल.जे. (एस.सी.) पेज 546 वेद प्रकाश गुप्ता बनाम डेवटन केबिल कम्पनी में माननीय न्यायाधिरक्षियों ने यह विनिश्चय किया कि आरोपित के खिलाफ गालियां देने का आरोप है जो कि गम्भीर नहीं है और इससे विश्वास का खोना नहीं पाया जाता है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं इसलिए यह निर्णय प्रार्थी को कोई मदद नहीं करता। 1986 नैत्र.आर्.टी.सी. पेज 938 (सुपरा) में केवल गालियां देने का आरोप था जिम्में सेवा-मुक्ति के दण्ड को उचित नहीं ठहराया गया परन्तु इस प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं इसलिए तथ्यों के आधार पर यह निर्णय भी प्रार्थी की कोई मदद नहीं करता। अतः आरोपों की गम्भीरता व उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को दिया गया सेवा-मुक्ति का दण्ड मेरे विचार से उचित है और इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

18. पक्षकारान् द्वारा उठाये गये ये प्रश्न कि हिन्दुस्तान जिक लि. कम्पनी को आर.एस.टी.डी.सी. के अधिकार हस्तान्तरित हो गये थे अतः प्रकरण में कौन-सा पक्षकार उत्तरदायी है, का निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रार्थी की सेवा-मुक्ति उचित एवं वैध मानी गई है।

19. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित अर्वाइ पारित किया जाता है:—

“व्यवस्थापक, राजस्थान स्टेट टंगस्टन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., जयपुर द्वारा श्रमिक श्री आर. एस. राठीड़ को सेवा से दिनांक 15-10-88 के आदेश से दिनांक 16-10-88 से समाप्त किया जाना उचित एवं वैध है। प्रार्थी आर. एस. राठीड़ व्यवस्थापक आर०

एस०टी०डी०सी० व हिन्दुस्तान जिक लि० के विरुद्ध कोई दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है।"

20. अर्वाइ आउ दिनांक 10-6-97 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अर्वाइ की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भजी जाये।

एम० के० बंसल, न्यायाधीन

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998

का. आ. 1566.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-17012/118/90-आई. आर. (बी-II)
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th July, 1998

S.O. 1566.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workman, which was received by the Central Government on 15-7-98.

[No. L-17012/118/90-IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
जबलपुर म. प्र.
डी. एन. दीक्षित
पीठासीन अधिकारी

प्र. क्र. सीजीआईटी/एलसी/आर/195/90

जनरल सेक्रेटरी,
इन्श्योरेंस एम्पलाईज यूनियन
296, अन्प नगर,

इन्दौर (म. प्र.) 452 008

... प्रार्थी

विरुद्ध

सीनियर डिविजनल मैनेजर,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश,
19, महात्मा गांधी मार्ग,

इन्दौर (म. प्र.) 452 001

... प्रतिप्राथी

अर्वाइ

दिनांकित : 26-6-1998

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या : एल-17012/118/90-आई. आर. (बी-2) दिनांक 1-10-90 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

अनुसूची

"Whether the charge sheet issued by the Sr. Divisional Manager, L.J.C. of India Indore Division, Indore dated 19-5-86 to Sri L. N. Vijayvargiya, Assistant and later the proceedings of the departmental enquiry on the basis of the said charge sheet were valid and in accordance with the procedure? Similarly whether the punishment of dismissal and later its reduction to bringing down the employee to his minimum of the scale is commensurate with the gravity of the charges? If not to what relief the workman is entitled for and from which date?"

2. श्रमिक के अनुसार श्री एल. एन. विजयवर्गीय वर्ष, 1984 में जीवन बीमा निगम के इन्दौर कार्यालय में एकाउंट शाखा में असिस्टेंट थे। दिनांक 1-9-84 को इस श्रमिक ने हाजी मोहम्मद इब्राहिम की बीमा पालिसी रुपये 4,125/- का चेक प्राप्त किया तथा रजिस्टर में इंदराज किया। इस चेक के द्वारा चार बीमा पालिसियों का भुगतान किया गया था, जिसमें एक पालिसी हाजी मोहम्मद इब्राहिम की थी। दिनांक 2-9-84 को इस हाजी मोहम्मद इब्राहिम की मृत्यु हुई। इस संबंध में श्रमिक ने पृथक्ता की गई और उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांचकर्ता अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23-8-86 को प्रस्तुत की और सीनियर डिविजनल मैनेजर, इन्दौर ने अपने आदेश दिनांक 8-1-87 के द्वारा श्रमिक की सेवा समाप्ति का दण्ड दिया। अपील में जोनल मैनेजर, कानपुर ने आदेश दिनांक 28-1-89 के द्वारा सेवा समाप्ति के दण्ड को परिवर्तित किया तथा कर्मचारी को पे-स्केल के न्यूनतम में रखे जाने का दण्ड दिया। श्रमिक के अनुसार विभागीय जांच में घोर अनियमितताएं की गईं। आरोप-पत्र अस्पष्ट था। विभागीय जांच में महत्वपूर्ण तथ्यों पर कोई साक्ष्य नहीं दी गई। श्रमिक को जो दण्ड दिया गया, वह कदाचरण के अनुपात में कठोर है।

3. प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसार श्रमिक ने चेक दिनांक 1-9-84 को प्राप्त किया। इस संबंध में गंभीर विवाद है। श्रमिक का कार्यकालाप संदेहास्पद है। विभागीय जांच विधिवत की गई है। इसकी पुष्टि अपीलकर्ता अधिकारी ने की है। श्रमिक को अनुकम्पा आधार पर पुनः नौकरी में रखा गया है और इसलिए स्केल का न्यूनतम दिया गया है। जिस दिनांक को श्रमिक चेक पाना बताता है, उस दिनांक को चेक पाने और रजिस्टर में लिखने का कार्य श्री रामपाल वर्मा का था। चेक के संबंध में कार्यवाही करने का कार्य श्री इंगले का था। श्रमिक ने 1-9-84 को चेक प्राप्त किया और इसे श्री इंगले को 5 या 6 सितम्बर को दिया। श्रमिक ने इतने दिनों चेक अपने पास क्यों रखा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रबंधन के अनुसार श्रमिक को दिया गया दण्ड कदाचरण की तुलना में अत्यन्त कम है। प्रबंधन चाहता है कि विभागीय जांच और दण्ड की पुष्टि की जावे।

4. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28-2-95 के द्वारा यह पाया है कि विभागीय जांच में अपनार्ई गई प्रक्रिया विधिवत है और श्रमिक को उचित अवसर अपने बचाव के लिए दिया गया है।

5. अब यह विचार करना है कि क्या जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष सही है तथा श्रमिक को दिया गया दण्ड कदाचरण के अनुरूप है अथवा नहीं।

6. जांचकर्ता अधिकारी श्री बी. एस. मेहता की रिपोर्ट दिनांक 29-8-86 रिकार्ड में है। इसके अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 1-9-84 को बीमा निगम में आर. आर. रजिस्टर लिखने का काम श्री रामपाल वर्मा का था। इस दिनांक को ग्राहकों के सभी चेक प्राप्त करने का काम श्री बी. जे. इंगले का था। ये दोनों दिनांक 1-9-84 को ड्यूटी पर थे। इसके बावजूद श्रमिक ने यह चेक दिनांक 1-9-84 को प्राप्त किया और आर. आर. रजिस्टर में इसे लिखा। इन दोनों कामों को करने का उत्तरदायित्व इस दिनांक को श्रमिक का नहीं था।

7. श्रमिक ने चेक 1-9-84 से 5-9-84/6-9-84 तक अपने पास रखा। यह बात भी नियमों के विपरीत है। जैसे ही चेक प्राप्त होते हैं, इसे भुगतान के लिए दिनांक 1-9-84 को श्री इंगले को देना था। श्रमिक ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने जीवन बीमा निगम का चेक 5 दिन तक अपने पास क्यों रखा।

8. मृतक हाजी मोहम्मद इब्राहिम का एक लाख का बीमा दिनांक 28-2-84 को हुआ था। इसकी किस्त तिमाही भरी जानी थी। इनकी मृत्यु दिनांक 2-9-94 को हो गई। जो चेक 25-8-84 को दिया गया, उसका सम्बन्ध चार पालिसियों से था। दिनांक 1-9-84 को इस अकाउंट में जितने का चेक था, उतने पैसे नहीं थे। बीमाधारी की मृत्यु 2-9-84 को होने से यह स्वाभाविक था कि इसकी किस्त दिनांक 1-9-84 को पटाई गई, इस संबंध में जांच-पड़ताल हो। जांच-पड़ताल में यह पाया गया कि श्रमिक को किसने चेक दिया, इस संबंध में श्रमिक ने समय-समय पर भिन्न-भिन्न कथन किये हैं। श्रमिक का काम इस दिनांक को ग्राहकों से चेक प्राप्त करने का नहीं था। श्रमिक का काम ग्राहकों से भुगतान के रजिस्टर में लिखने का भी नहीं था। नियम के अनुसार कोई भी जीवन बीमा निगम का कर्मचारी बीमे की राशि अपने पास नहीं रख सकता। श्रमिक ने 5-6 दिन तक यह चेक अपने पास रखा।

9. इन्हीं आधारों पर जांचकर्ता अधिकारी ने श्रमिक को कदाचरण का दोषी पाया, इसकी पुष्टि सीनियर डिबीजनल मैनेजर और जूनियर मैनेजर ने की है। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच का रिकार्ड के परीक्षण के बाद में इस निष्कर्ष से सहमत है कि श्रमिक ने आर. आर. रजिस्टर में जो इंदरज किया वह उनकी ड्यूटी नहीं थी। जो चेक प्राप्त किया, वह भी उनकी ड्यूटी नहीं थी तथा चेक को अपने पास 5 दिनों तक नियमों के विरुद्ध रखा। श्रमिक ने गंभीर कदाचरण किया। श्रमिक पर लगाए गये तीनों आरोप

सिद्ध होते हैं। मैं जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष की पुष्टि करता हूँ।

10. नियंत्रक अधिकारी सीनियर डिबीजनल मैनेजर, जीवन बीमा निगम, इन्दौर ने श्रमिक को दिनांक 8-1-87 को सेवासमाप्ति का दण्ड दिया। अपील में मोनल मैनेजर, कानपुर ने अनुकम्पा आधार पर श्रमिक को नौकरी में रखा, किन्तु इनको पे-स्केल के न्यूनतम वेतन स्केल पर रखा। इसका निष्कर्ष यह है कि श्रमिक को पुनर्नियुक्ति इस स्केल में दी गई है। श्रमिक का जो कदाचरण है, उसका एक मात्र दण्ड सेवा समाप्ति ही उचित है। श्रमिक को पुनर्नियुक्ति देकर प्रबंधन ने अनुकम्पा बताई है। मेरे मत में श्रमिक को दिया गया दण्ड उचित है। इसकी पुष्टि की जाती है।

11. ऊपर लिखी विवेचना का निष्कर्ष यह है कि विभागीय जांच में अपनार्ई गई प्रक्रिया विधिवत है तथा जांच अधिकारी के निष्कर्ष सही हैं। श्रमिक को दिया गया दण्ड उचित से कम है। अवार्ड दिया जाता है कि प्रबंधन के द्वारा अपनार्ई गई प्रक्रिया विधिवत है और श्रमिक को दंड दिया गया दण्ड सही है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण का दोनों पक्ष अपना-अपना व्यय वहन करें।

12. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियां भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी. एन. दीक्षित पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1998

का. आ. 1567:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—12012/339/96—आई. आर. (बी.-II)
सनातन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1998

S.O. 1567.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on 20-7-98.

[No. L-12012/339/96-IR (B-II)]

SANATAN, Desk Officer

Industrial Dispute No. 129 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Uma Kant son of Nathu Lal,
r/o Bharti Pustak Bawan Kali Bari,
Bareilly U.P.

AND

The Regional Manager,
Punjab National Bank,
156 Civil Lines Bareilly.

APPEARANCES :

Sudhir Sharma—for the management and Mukesh Singh
—for the workman.

AWARD

1. Central Govt. Ministry of Labour, vide notification No. L-12012/339/96/IR(B-II) dated 6-8-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the PNB Bareilly in terminating the services of Sri Uma Kant ex-daily paid labour w.e.f. Feb. 94 is justified? If not to what relief is the concerned workman is entitled

2. The case of the concerned workman is that he worked as a peon as daily rated worker from 1-1-87 to 30-3-91 at Civil Lines Branch of the opposite party at Bareilly. thereafter he worked from 5-7-91 to 10-10-93 at Shahiabad Pur Branch and further from 15-10-93 to 22-10-94 at Shyam Gani Branch. Thereafter his services were terminated in breach of provisions of section 25F of I.D. Act.

3. In the written statement it has been alleged that the concerned workman had worked in the year 1991 for 4 days, in the year 1992 for 5 days, in the year 1993 for 65 days and in the year 1994 for 16 days as daily rated worker to do work according to exigency of bank. In none of the years he had completed 240 days.

4. In the rejoinder nothing new has been alleged.

5. In support of his case, the concerned workman has examined himself as W.W-1 P. N. Trivedi M.W-1 has stated that the concerned workman has not worked as peon at Civil lines Branch. Anil Kumar Agrawal M.W.2 has stated that the concerned workman has not worked as Shahiabad Branch of the bank. Nalin Saxena MW-3 as stated that the concerned workman has not worked at Shyam Nagar Branch of the bank. There are Ext. W-1 to W-208 documents. Out of which Pxt. W-206 and 207 will be relevant which go to show that the concerned workman was actually a protégé of one K. C. Kapoor Manager. He used to take him wherever he was transferred. It was recommended that the concerned workman is the personal candidate of Kapoor hence he may be adjusted. This paper go to show that the concerned workman was never actually engaged as peon. Instead he was provided work at the whim of Manager. Hence my finding is that concerned workman was never engaged as peon.

6. The concerned workman Uma Kant has not stated that at the time of retrenchment he was not given retrenchment erroneous. It is pleaded that the Hotel Laboin Union (R&D) prove that provisions of section 25F has been breached.

7. In view of above my finding is that termination of the services of the concerned workman is not bad. Consequently he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1998

का. प्र. 1568 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम; 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—12012/87/97—आई. प्रार. बी-II]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1998

S.O. 1568.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on 20-7-98.

[No. L-12012/87/97-IR (B-II)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT KANPUR

Industrial Dispute No. 101 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Sanjeev Kumar son of Hira Lal Kanojia,
resident of 459 Sadar Bazar Bareilly U.P.

AND

The Regional Manager,
Punjab National Bank,
Regional Office 156 Civil Lines,
Bareilly. U.P.

APPEARANCE :

Mukesh Singh—for the workman and Sudhir Sharma—
for the Management.

AWARD

1. Central Government. Ministry of Labour, vide notification No. L-12012/87/97/IR. B-II dated 8-7-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Punjab National Bank Bareilly in terminating the services of Sanjeev Kr. Kanojia ex-daily paid peon w.e.f. 13-9-95 is legal and justified? If not to what relief the workman is entitled to?

2. The case of the concerned workman Sanjeev Kumar Kanojia is that he continuously worked as peon at B. I. Bazar Branch Bareilly of the opposite party Punjab National Bank from December 1986 to 12-9-95, as daily rated worker. Thereafter his services were terminated in breach of provisions of sec. 25F of I.D. Act without payment of retrenchment compensation and notice pay.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that concerned workman was not engaged as a peon. Instead he used to be engaged according to need of work. He did not complete 240 days in any calendar year. There had been no breach of section 25F of I.D. Act.

4. In the rejoinder nothing new has been alleged.

5. In support of his case concerned workman Sanjeev Kumar Kanojia has examined himself as W.W.1 whereas A. K. Mehrotra has examined himself as M.W.1 on behalf of the bank. Besides workman has filed documents ext. W-1 to W-6.

6. In the first place it will be seen if the concerned workman has worked as peon or not.

7. Workman has stated that he has worked as peon. A. K. Mehrotra management witness has denied this fact. Ext. W-25 to 39 are photocopies of Dak Register through which letters were delivered locally and in this register the concerned workman has been shown as peon. Thus it is the own admission of the bank that the concerned workman was working as peon. Hence, my finding is that the concerned workman has worked as a peon.

8. Next it will be seen if there had been breach of provision of section 25F of I.D. Act. The burden of proof of this fact rests on the workman. He has stated that he had worked in Cantt. Branch from December 1986 to 12-9-95. When he asked for regularisation he was removed. He has no where stated that at the time of termination retrenchment compensation and notice pay was not given. In this way breach of provisions of section 25F of I.D. Act is not proved. It was the only ground on which the termination was challenged.

9. In the end my award is that as there has been no breach of provisions of section 25F of I.D. Act his termination is not bad and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1998

का. आ. 1569 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबंध निराजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-7-98 को प्राप्त हुआ था

[सं. एल-17011/5/96-आई. आर. (बी.-II)]
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd July, 1998

S.O. 1569.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-II, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workman, which was received by the Central Government on 21-7-98.

[No. L-17011/5/96-IR(B-II)]
SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. II, MUMBAI

PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/25 of 1997

Employers in relation to be Management of Life Insurance Corporation of India.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers: Ms. S. M. Paranjpe, Advocate.

For the Workmen: Mr. R. D. Bhat and Ms. S. M. D'Souza, Representative.

Mumbai, the 23rd June, 1998

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-17011/5/96/IR(B-II), dated 08/16-07-97, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication:

"Whether the action of the management of LIC of India through their contractor M/s. Uma Catering Service in terminating the services of 11 workers namely S/Shri 1. Shankar Pujari, 2. M. Ganesh, 3. Bakrisuna, 4. Madaswamy, 5. Manish, 6. Chaudan, 7. Nagaraj, 8. Mohd. Hanif, 9. Kamalashira P. 10. Manjunath and 11. M. D. Banarui is legal and justified if not, to what relief the said workmen are entitled?"

2. The General Secretary of the Hotel Labour Union (Red Flag) filed a Statement of claim (Exhibit-3) on behalf of the workmen mentioned in the reference.

3. The union contended that the workmen authorised the union to represent their case before the Tribunal. It is submitted that the Life Insurance Corporation (hereinafter called as the employer) is maintaining a training centre called Ordinary Training Centre at Santacruz (W), Mumbai. The employer provides residential training to its staff members and officers. There are different types of courses conducted in the Centre. The courses are conducted in immediate succession and the courses may differ and the trainees may differ, but the training is given on a continuous basis. As the training is given on a residential basis the employer has maintained the canteen for providing tea, breakfast, lunch and dinner to all the trainees who are deputed to the training centre departmentally by the employer. It is therefore, the work in the canteen is a continuous nature. The canteen is maintained by the employer. It is compulsory to provide tea, breakfast, lunch and dinner, to the employees who attend the training. It has become a service condition and the canteen is maintained for providing such services.

4. It is pleaded that to deny the relationship of employer and employee between the employer and the workmen working in the said canteen the employer has brought in one purported contractor who is only the name lender or at the most the person working as the agent of the employer. The purported contract has been signed between the employer and the contractor in the name of Uma Catering Services who is the proprietor concerned owned by one Shri Dhawakar Shetye. The address of Uma Catering Services is 31, Indira Bhavan, Chabildas Road, Dadar, Mumbai.

5. It is asserted that from the terms of the contract it is crystal clear that the workmen working in the canteen are directly under the control and the supervision of the officers of the employer. Their appointment, service conditions and termination are regularised by the employer. It is therefore as per the law laid down in *Perimal Chandra Reha and Ors. Vs. L.I.C. of India*, the workmen working in the canteen are the workman of the employer. It is therefore they are entitled to all the benefits of the regular employees of the employer.

6. It is averred that the workmen are continuously working in the said canteen from 1988 onwards. Their service conditions are pathetic. They are not given proper wages, no attendance registers are maintained, no payment registers are maintained. They are also not given weekly off nor the leave. They had to work 12 hours a day continuously without any overtime. It is therefore with a view to seek the relief the workmen joined the union in August 1994. By letter dated 23-8-94, the union approached the Regional Labour Commissioner to intervene in the matter. When the matter came to the knowledge of the employer the purported contractor brought goondasess to the premises on 23.8.94 and threatened the Hotel workmen and physically assaulted them and removed them alongwith their belongings from the hotel premises. It is submitted that in view of their working for more than 12 hours a day they have to keep their belonging in the canteen block. The union thereafter by their letter dated 3-9-94 requested the Principal of the training institute to reinstate all the workmen with a continuity alongwith the back wages. It is submitted that the services of these workmen were terminated without any notice or a retrenchment compensation. As no reliefs were granted they approached the Regional Labour Commissioner in the matter.

7. The union pleaded that all these eleven workmen are infact and in law are the employees of the employer that is the L.I.C. Their termination is illegal and unjustified. It is therefore submitted that they may be reinstated in service with full back wages and attended benefits and service conditions w.e.f. 28-8-94. They may be declared as the workmen of the LIC and other consequential reliefs may be granted to them.

8. The management resisted the claim by the Written Statement (Ex-4). It is submitted that the workmen mentioned in the reference were never employed by the Corporation nor by Uma catering service. Under such circumstances the purported termination by the employer cannot be said to be illegal. It is asserted that the fundamental assumption on which the reference is based is itself erroneous. It is pleaded that the Hotel Labour Union (Red Flag) has no locus standi on raise the dispute because there are several union which represent the interest of Class-IV workers and the Hotel Labour Union (Red Flag) does not represent any such class-IV workers. It is not recognised by the Corporation at any point of time as being representation of interest of Class-IV. It is therefore submitted that the dispute cannot be permitted to be agitated by the union.

9. The employer pleaded that the ordinary training centre is equipped to run courses for a maximum of 50 persons at a time. The workers employed by M/s. Uma catering service which provides the canteen arrangement to the employer are much less than fifty persons. It is therefore the Factories Act do not apply to the employer. The provisions of the canteen arrangement has no service condition nor is it obligatory on the employer to provide such a service to its employees. It is pleaded that the facts of Reha's case are quiet different from the facts in this reference. The ratio laid down in that case has no application to the present set of facts. It is pleaded that the order does not provide for canteen facility as a term or conditions of service of the employees of the Corporation. It is asserted that the Life Insurance Corporation of India (staff) Regulations, 1968 provides for canteen facilities to the employees of the Corporation. The maintenance of the canteen is in short the function of the corporation nor incidental to the functions of the Corporation. The provision of the canteen facility to the employees of the Corporation is not a term or a condition of the service. There is no class, cadre or grade or post of canteen employees in the staff regulations or in the rules issued by the Central Government or in any other provisions relating to the terms and conditions of the service of employees of the Corporation. It is averred that the agreement with M/s. Uma Catering Services clearly speaks that the employer had nothing to do with it. It is averred that the employees employed by Uma caterers cannot be said to be the employees of the Corporation. It is averred that the purported workers alleged working in the canteen are working directly under the control and supervision of Uma caterers and the Corporation had nothing to do with it. It has no disciplinary control over the same. It has no powers to appoint them nor it can take any action against them. It is submitted that there is no privity of contract between the Corporation and the 11 purported worker any of them. It is pleaded that the question of termination of service without notice or retrenchment compensation allegedly due in law or in the alleged factual premises or otherwise does not arise in the facts and circumstances of the case.

10. The employer pleaded that the demand raised by the union is unjustified. In fact and in law and cannot be maintained. It is denied that the workmen were working in Uma catering services since 1988. It is submitted that the workmen are not entitled to any of the reliefs as claimed and the reference may be answered accordingly.

11. The issues that fall for my consideration and my findings there on are as follows :—

Issues

Findings

- Whether the workmen mentioned in the reference were employed by the Corporation ?

No.

- Whether the workmen employed by Uma caterers in the canteen can be said to be employees of LIC ?

No.

- Whether the management of LIC had terminated the services of 11 workmen through the contractor M/s. Uma Caterers

No.

- Whether the workmen are entitled to any reliefs as claimed ?

No.

REASONS

12. To hold up the case the union examined Balkishan Gowda (Exhibit-9); Balaram Sayaji Chauhan (Exhibit-12) the workmen and relied upon the documents which were filed at Exhibits-7 & 8. As against that the employer examined T. L. Lobo (Exhibit-14) and relied upon the documents which were filed on the record. Written arguments were filed by the employer and the union at Exhibit-16 & 17 respectively. Certain facts can be said to be not in dispute. The LIC had a training institution at Santacruz. In the said institution different courses are conducted for the benefit of the employees of the Corporation. Those courses are of different tenure and in succession. At one point of place there might be a gap of six to seven days. But the process of teaching in the institute is continuous one. The institute impart training to the employees who are given residential accommodation and also to the employees who are non residential. The employees who reside there are served with tea, breakfast, lunch and dinner. The institution came into existence somewhere in 1988. Since beginning Uma caterers is given a contract in respect of the canteen in the said premises.

13. From the testimony of Balkrishna & Balaram and from that of Lobo it is crystal clear that the corporation never engaged the workmen nor anybody in the canteen. The workmen were never interviewed by the Corporation nor any appointment letters were issued to them. Infact Balkrishna and Balaram accepts the position that they were given the employment by Diwakar Shetty then popularly known as the Seth and Andrew the Manager of the Canteen. In the statement of Claim and from their testimony it reveals that somewhere in August '94 Shetty brought some local goondas and drove them out of the canteen premises. They were never allowed to work thereafter. It is not their case also that the officers of the Corporation had taken any action against them. Infact in the complaint which is lodged to the police there is reference of Shetty and not of officers of the Corporation. It is therefore very clear that the services of these employees were never terminated by the Corporation. It is clear that when they were removed from the canteen they were not given any notice nor retrenchment compensation.

14. The union addressed a letter dtd. 3-9-94 to the Principal of the institution contending that the 11 persons mentioned in the letter were working in the Uma catering services. In the demand raised before the Assistant Labour Commissioner by the letter dated 7-12-94 the same persons names were included. At the relevant time they were alleged to be in service. In fact the employer had not seriously disputed the persons mentioned in the list but it appears that their sole contention is that they have nothing to do with them as they were employees of the Uma caterers.

15. Lobo affirmed that maintenance of the canteen is not a function of the L.I.C. nor it is incidental to the function of the L.I.C. He affirmed that the provisions of the canteen facilities/services is not a term or condition of service of LIC employees. There is no class, cadre or a post or a grade of canteen employees in the regulations of the LIC. L.I.C. is not at all concerned with the recruitments, service conditions and disciplinary action or dismissal of workers by Uma caterers. No complaint was made by LIC at any time against any workers of Uma caterers in respect of the catering arrangement at the institution. The profits arising out of the catering arrangement belong to the caterers alone. The Tax Deducted at Source was collected and paid by L.I.C. to the Income Tax Authorities in respect of Uma caterers who have been described as the contractors in the TDS service. The Corporation had not given funds or financial

assistance to Uma caterers for catering arrangement. No licence have been issued in the name of Corporation in respect of the canteen arrangements with the Uma Caterers. The Uma Caterers are paying salaries of the canteen workers. It is affirmed that the function of the canteen committee of the Corporation is limited to ensure that no sub-standard food is served by the contractors. On this basis it is tried to argue on behalf of the employer that there is no relationship of employer and employee between the Corporation and the workmen mentioned in the reference.

16. As against that it is tried to argue on behalf of the union that in view of the contract it is crystal clear that the employer is in true sense is the employer of these workmen. The union relied upon the Clauses 12, 19 and 28 of the contract given to Uma caterers. In Clause 12 it is mentioned that when in the hands of the Corporation the employees are guilty of misconduct any way unfit or untalented for service he will be removed by the caterer. After perusal of this clause I am not inclined to accept that Corporation was in position to remove the concerned employee. He was to bring to the notice of the caterer regarding the unsuitable employee and request for removal. After perusal of clause 19, 26 and 28 it cannot be said that the Corporation had a control over the canteen and was conducting the supervision. At the most it can be said that as a customer he was to place the demands of particular food in advance to the contractor to be served to them.

17. There are various tests which are being laid down by various High Courts from time to time to ascertain the relationship of employer and employee. There is however no any one condition which can be considered as the only test. Hence one has to see all attending facts and circumstances in order to come to the conclusion whether there exists relationships of employer and employee. The union relied upon the tests mentioned in *M.G.K.U. Vs. Cipla Ltd.* 1996 II CLR 770 and the ratio laid down in *Parimal Chandra Reha and Ors Vs. LIC and Ors.* 1995 II CLR 194. It is tried to argue on behalf of the union that ratio laid down in these two authorities is aptly applicable to the present set of facts. It can be seen that in Reha's case the dispute was respected to 42 workmen in the canteen in four of different offices of LIC in Calcutta. Those canteens were in existence prior to 1956 and thereafter they were conducted by canteen committees, contractors and Cooperative Societies. The preamble to the canteen agreement clearly speaks of LIC's desires to run the canteen by a contractor on a profit basis. Therefore the Supreme Court came to the conclusion that the L.I.C. had not explicitly undertaken to provide the canteen service to its employees in Calcutta. It had implicitly done so. There the distinction was made between provision of facilities for the canteen and provision of canteen service. Their Lordships observed "Whether a particular facility or service has become implicitly a part of the service conditions of the employees or not, will depend, among others, on the nature of the service, facility, the contribution the service in question makes to the efficiency of the employees and the establishment, whether the service is available as a matter of right to all the employees in their capacity as employees and nothing more, the number of employees employed in the establishment and the number of employees who avail of the service, the length of time for which the service has been continuously available, the hours during which it is available, the nature and character of management, the interest taken by the employer in providing, maintaining, supervising and controlling the service, the contribution made by the management in the form of infrastructure and funds for making the service available etc." Looking to the present set of facts which I have already observed above the ratio given in this authority is not applicable.

18. The employer on the other hand placed reliance on *R.B.I. Vs. Workmen* (1996) 3 SCC 267. In that case their Lordships observed, in the absence of statutory and other legal obligation and in the absence of any right in the bank to supervise and control the work or the details thereof in any manner regarding the canteen workers employed in three types of canteens it cannot be said that the relationship of master and servant exist between the bank and the various persons employed in three types of canteens. They are not workmen of the R.B.I. and that they are not comparable employees employed in the officers lounge. Therefore the

demand for regularisation is unsustainable and they are not entitled to any reliefs.

19. The ratio given in the above said authority has application to the set of facts before me. Relying on the ratio given in the said authority I came to the conclusion that the workman employed by Uma caterers cannot be said to be employees of the Corporation as contended by the Union.

20. It has not come in the evidence that the Corporation compelled or suggested Uma caterers to terminate the services of the workmen working in the canteen. It is the case of the union that as the workmen approached them for getting different types of benefits, the union in their turn approached the Assistant Labour Commissioner the proprietors of Uma caterers threatened these workmen and drove them out of the canteen premises. In other words they terminated their service from August 1994. It is crystal clear that the Corporation had nothing to do with the case of the Uma caterers. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

1. The 11 workers mentioned in the reference are not the employees of the L.I.C.
2. The management of the L.I.C. had not terminated the services of 11 workers through the contractors M/s. Uma Catering Services.
3. The workmen mentioned in the reference are not entitled to any of the reliefs as claimed.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. भा. 1570.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12011/1297-आर्. आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1570.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1998.

[No. I-12011/1297-IR (B-II)]

SANATAN, Desk Officer.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 14 of 1998.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Allahabad Bank.

ANNEXURE
BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT KANPUR

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice A. K. Chakravorty.
..Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Management : Mr. P. M.
Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen : None.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.
AWARD

By Order No. L-12011/12/97-IR (B-II) dated 01-04-1998 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of Allahabad Bank decided to reducing the allowance of encoder machine operator from Rs. 282/- to Rs. 245/- per month is legal justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?”

2. When the case is called out today for filing written statement by the union, none appears for the union, nor any step is taken on its behalf. Management is represented by the learned Advocate. It appears from the record that on the last date i.e. 2-6-1998 the union did not appear and did not take any step in the matter. Since the union has not taken any step inspite of opportunities being given to it, it is clearly discernable that the union is no longer interested in conducting the case.

3. In the aforesaid circumstances, in the absence of any material whatsoever for any decision in respect of the schedule under reference, this Tribunal has no other alternative but to pass a “No Dispute” Award in this case.

4. A “No Dispute” Award is accordingly passed and the reference is disposed of.

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 2nd July, 1998

Sd./-

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. आ. 1571.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—12011/153/94—आई. आर. (बी.-II)]
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1571.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-98.

[No. L-12011/153/94 IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUST-
RIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
PANDU NAGAR, KANPUR
Industrial Dispute No. 100 of 1997

In the matter of dispute between:

Sri Shiv Sharma
C/o Ram Sewak Sharma
Mohalla Zamidaran Khudaganj
Shahjahanpur.

AND

Regional Manager
Bank of Baroda
Regional Office
Shahjahanpur Region
Govindganj, Shahjahanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide notification No. L-12011/153/94-I.R. (B-II) dated 2-7-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal —

Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of Sri Shiv Sharma a daily wager worker w.c.f. 26-7-93, is legal and justified ? If not to what relief the said workman is entitled to?

2. The case of the concerned workman Shiv Sharma is that he was engaged as a peon on 2-7-85 at Khudaganj Branch District Shahjahanpur of the opposite party Bank of Baroda. Although he had worked for continuously on the instruction of the branch, still his engagement was shown in broken periods. Even he had to work on Sundays and other holidays and no wages were paid to him, some times wages were paid to him, where as in vouchers the names of Vinod Veer Pal Ram Vilas, Ramesh, Narendra, Ram Autar, Ram Veer, Ram Sewak and Satpal etc., were shown. His objection in this regard was not heeded to. As the concerned workman had continuously worked at different branches of the opposite party from time to time he had completed 240 days in a year before his termination. As he had been removed from service in breach of provisions of section 25-F of I.D. Act, his termination is bad. Besides juniors to him were retained in services, hence there has been breach of provisions of section 25-G of I.D. Act. Lastly it was alleged that as he had completed the required number of days according to approach paper, he

was entitled to be considered for permanent absorption.

3. The management has filed reply in which it has been denied that the concerned workman was never engaged as a peon. Instead he used to be engaged as daily rated worker from time to time according to exigency of work. Hence provisions of sections 25F and 25G are not attracted at all. In any case, the concerned workman has not completed 240 days.

4. In the rejoinder nothing new has been alleged.

5. In support of his case, the concerned workman Shiv Sharma W.W.1 has examined himself besides he has filed ext. W-1 to W-18 Management has examined their manager Avinash Kumar Mayank as M.W.1, further ext. M-1 to M-18 documents have been filed.

6. At the out set it may be mentioned that the claim of the concerned workman on the basis of approach paper cannot be considered as it does not find mentioned in the reference order and this tribunal cannot go beyond the reference under section 10(4) of I. D. Act.

7. In the next place it may be mentioned that the concerned workman has not adduced any evidence to prove breach of provisions of section 25-G of I. D. Act.

8. Now it will be seen if the concerned workman has worked as peon. Naturally the concerned workman Shiv Sharma W.W. 1 has stated that he was engaged as a Peon and he used to perform duties of a Peon. Avinash Kumar M. W. 1 has denied this fact Ext. M-1 to M-18 are vouchers in the name of the concerned workman go to show that he used to be engaged as a casual worker. The concerned workman has filed Ext. W-1 to W-18 out of which Ext. W-5 to Ext. W-6 may be referred which are the certificate by the manager of the Bank in which it has been mentioned that some time the concerned workman had worked as water boy and some times as a casual worker on daily basis. In Ext. W-6 word "AS SUB-STAFF" have been added. This certificate show that the concerned workman had worked for 17 days in 1985 and for 4 days 1996. In my opinion merely by working for such a short period it cannot be held that the concerned workman was initially engaged as a Peon on regular basis. Ext. W-18 is the letter by Regional Manager to Branch Manager Khudaganj Branch by which inquiry has been sought as to how Shiv Sharma has been engaged unauthorisedly. Taking into consideration the other certificate filed by the concerned workman and also taking into consideration evidence of the parties I come to the conclusion that the concerned workman was not engaged as a Peon. Instead he used to be engaged as a casual labour on daily basis.

9. Now it will be seen if the concerned workman had completed 240 days in a year. In this regard there is evidence of the concerned workman that he had continuously worked and vouchers were paid in the name of others the details of whom have been given above. Although Avinash Kumar has exami-

ned but he has not denied this fact. Hence, it is established that the concerned workman had actually worked and vouchers were prepared in the name of others. Since the management had indulged in falsehood in respect of this matter I dis-believe their version and believe the version of the concerned workman and hold that he had continuously worked.

10. In the case of S. K. Vidyarthi versus State of Bihar FLR 1997(96) 237 it has been explained that a daily rated worker who does not work against any post is not entitled for benefit of section 25-F of I. D. Act.

11. In view of this authority of Hon'ble Supreme Court, it is not necessary to see if there has been breach of section 25-F of I. D. Act.

12. As a result of above discussion my Award is that termination of the concerned workman is not bad and he is not entitled for any relief.

Sd./-

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. आ. 1572.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में; केन्द्रीय सरकार विजया बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/23/93-आई. आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1572.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Vijaya Bank and their workman which was received by the Central Government on 23-7-98.

[No. L-12012/23/93-IR (B-II)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU CHENNAI

Friday, the 22nd day of May, 1998

PRESENT :

Thiru S. Ashok Kumar, M.Sc., B.L., Industrial Tribunal

Industrial Dispute No. 74 of 1993

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 between the Workmen and the Management of Vijaya Bank, Madras).

BETWEEN :

The Workmen represented by,
The Joint Secretary, Vijaya,
Bank Emp. Organisation,
283, Piccofts Road,
Triplicane, Madras-600 005

AND

The General Manager,
Vijaya Bank,
123, Marshal's Road,
Egmore, Madras-600 008

REFERENCE :

Order No. L-12012/23/93/IR (B.II), Ministry of Labour,
dated 30-7-93, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Monday, the 2nd day of March, 1998, upon perusing the reference, claim, counter statements and all other material papers on record, upon hearing the arguments of Thiru K. M. Ramesh, Advocate appearing for the petitioner and Thiru P. B. Krishnamurthy, Authorised Representative for the management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the action of management of Vijaya Bank in terminating the services of Sri K. Murugesan, w.e.f. 15-10-91 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled to?"

2. On service of notices, both the petitioner and the respondent appeared before this Tribunal and filed their claim and counter statement respectively.

3. The main averments found in the claim statement filed by the petitioner are as follows.—The respondent bank has taken in its employment employees who had worked at its various offices on temporary basis for periods from 90 days and above. A circular was issued in the year 1988 in that connection by the respondent bank setting out therein the scheme for absorption of permanent appointment as peons. The workman Sri K. Murugesan falls under the category having worked in one or two offices of the respondent bank on temporary basis during the period between 1985 and 1988. The services of the workman were utilised during the above period and thereafter he was denied the right to work even on temporary basis. Several other employees who were working similarly on temporary basis also faced the same situation in the respondent bank. The petitioner-union took up the cause of the affected workman with the management of the respondent and a settlement u/s. 18(1) of the I.D. Act, 1947 was arrived at. The terms of settlement deals with the mode of selection and ultimate absorption of empanelled candidates in the permanent vacancies arising existing in future in the category of peons. The workman, Sri K. Murugesan, who had earlier worked as a temporary employee and has qualified to be considered for the selection and for ultimate absorption in the permanent services of the bank, attended the interview conducted by the respondent bank and came out successfully. Orders were issued during March 1991 by respondent bank appointing him at its Dindigul branch from 15-4-91 on continuous basis after observing the formalities connected with the selection of the temporary employees. The workman Sri Murugesan has already worked at Moore Street, branch at Madras and DAO, Madras on various days on temporary basis both prior to and after the selection. While serving at Dindigul branch as peon effective from 15-4-91, the workman was advised by the Zonal office of the respondent bank as under :—

"Further to the letter No. OR : AVKM : 91 dt. 23-8-91 of Branch Manager, Dindigul branch informing you about your unsatisfactory performance at our Dindigul branch ever since you were engaged as temporary peon at the said branch from 15-4-91, it is reported now that there has been no improvement in your performance and you have not been discharging your duties to the satisfaction of your official superiors at our Dindigul branch, till date. As such you are hereby informed that your services are no more required by the bank from 15-10-91 onwards. Further, please note that you cease to be in the service of the bank with effect from 15th October 1991."

The services of Sri K. Murugesan were terminated by the respondent bank w.e.f. 15-10-91, and the same was not for a reasonable cause. The order of termination is based on the subjective assessment of the Dindigul Branch Manager of the respondent which has been merely accepted by the Zonal Office of the respondent bank. The order of termination is illegal, and not maintainable and amounts to punitive action. The termination of service of workman Sri K. Murugesan is unwarranted and unjustified. Sri K. Murugesan has been in the service of the respondent bank, since 1985 having worked intermittently at its various offices in temporary capacity. The workman had acquired sufficient knowledge of bank's routine and as such he had been familiar with the bank work and there has been no adverse remark against Sri K. Murugesan, either with regard to his work conduct. Sri K. Murugesan does not fall under Item 6 of the Settlement where disqualification of a candidate is enumerated and hence it is obvious that he did not have any unsatisfactory past record of service in the respondent bank. He was given the permanent posting at Dindigul branch though he had worked prior to and after the selection at Madras. The order of termination contains certain bald allegations against the workman. The workman was denied the opportunity to make his submissions in respect of certain wild allegations levelled against him. The termination of services of Murugesan is punitive and it was expected of the respondent bank to observe the procedure laid down in the Bipartite Settlement therefor. The termination is violative of para 522(1) and 522(4) of Sastri Award. The petitioner-union prays to hold that the respondent bank is not justified in terminating the services of Shri K. Murugesan w.e.f. 15-10-91 and to direct the respondent bank to reinstate the workman in service with all attendant benefits.

4. The main averments found in the counter statement filed by the respondent are as follows. Shri K. Murugesan was engaged as temporary peon at Dindigul branch for 153 days between the period 1-1-83 and 30-6-88 against intermittent vacancy. The temporary engagement of Shri K. Murugesan at respondent's Dindigul branch was in accordance with the provisions contained in Clause 20.7 of the first Bipartite Settlement, which reads as under :—

"In suppression of paragraph 21.20 and sub-clause (c) of paragraph 23.15 of the Desai Award, "temporary employee's will mean a workman who has been appointed for a limited period of work which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman."

As per the provisions mentioned above, the bank used to engage workmen on temporary basis, as and when there was any leave vacancy or when there was any temporary increase in work. As there were many such persons who were engaged by the Bank on temporary basis, in the past, in accordance with the provisions of the Bipartite Settlement, mentioned above, Bank with a view to providing them an opportunity of permanent absorption in the service of the Bank for such of those persons who worked as temporary peons in the bank for 90 days or more between 1-1-83 and 30-6-1988, signed a settlement on All India Basis on 19-8-88 with the representatives of the two recognised workmen union of the Bank i.e. Vijaya Bank Worker's Organisation and Vijaya Bank Employees' Association under Section 2(P) of the I.D. Act, 1947. In terms of the provisions contained in the settlement referred to above, an application was submitted by K. Murugesan, to be considered for selection for the purpose of appointing him as Peon. Shri K. Murugesan attended the interview and the Bank included him in the panel prepared for the absorption of temporary peon in the permanent cadre in the Bank's service. As per clause 20.8 of the First Bipartite Settlement, "a temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of 3 months during which the bank has to make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary employment may also be taken into account

as part of his probationary period." In the case of members or subordinate cadre, the period of probation is six months. According to the provision of Sastry Award, Probationer means an employee who is provisionally employed to fill a permanent vacancy and has not been made permanent or continued in service. The award further provides that at the end of the period of probation or at the end of the extended period of probation as the case may be, the employer can either confirm, the probationer in the service or terminate his service, if his work is found unsatisfactory. The performance of work of Shri K. Murugesan at the Dindigul branch was unsatisfactory and the branch issued several letters informing him the same and advising him to improve his performance. Even after the receipt of the letters from the Branch Manager advising him to improve his performance to work, Shri Murugesan did not show any sign of improvement whatsoever. Ultimately the controlling authority vide his letter No. NDZ : IRS : 19729 of 91-92 dated 3-10-91 confirming Shri Murugesan that his services are no more required by the bank w.e.f. 15-10-91 for the reason mentioned therein Shri K. Murugesan was working under the Branch Manager, Dindigul and as such the Branch Manager, Dindigul is the best person to assess the performance of Shri K. Murugesan during his probationary period. There is no violation of the provisions contained in Section 2(oo) and Section 25(F) of the I. D. Act, and Paragraphs 522(1) and 522(4) of Sastry Award. Shri K. Murugesan's service was dispensed with at the end of the probation period in accordance with the provisions contained in the Sastry Award. The services of a probationer can be dispensed with on account of unsatisfactory work or unsuitability or some other justifiable reason at the end of the probationary period. The bank can dispense with the service of probationer if he is not considered fit for confirmation. Accordingly, Shri K. Murugesan's service was dispensed with by the bank vide letter No. MDZ : IRS : 10729/91-92 dated 3-10-91. The period of probation gives an opportunity to the employer to observe the work, ability, efficiency, sincerity and conduct of the employee and if he is found not suitable, the employer has the right to dispense with his service at the end of the prescribed period of probation. Section 25(F) of I. D. Act, 1947 has no application in the instant case. It is not the case of the union that the employer bank should have paid one month's pay while dispensing with the service of Shri K. Murugesan. The violation, if any of the paragraph 522(1) of the Sastry Award, does not entitle Shri K. Murugesan to claim any relief under Chapter V-A of the I. D. Act, 1947 as none of the provisions contained therein were violated by the bank. The rights that would accrue to Shri K. Murugesan under the Provisions of the Sastry Award modified by Desai Award and subsequent Bipartite Settlement are entirely different and distinguishable from that contained under the provisions of the I. D. Act, 1947.

5. Thiru M. Gurumuthy, Regional Secretary of the petitioner-union was examined as WW-1 and Exs. W-1 to W-7 have been marked. On behalf of the respondent management, Thiru M. V. Murthy, Manager of the respondent bank has been examined as MW-1 and Exs. M-1 to M-20 have been marked.

6. The Point for consideration is : Whether the action of the management of Vijaya Bank in terminating the provides of Shri K. Murugesan w.e.f. 15-10-91 is justified ? If not to what relief workman is entitled to ?

7. The Point—The workman K. Murugesan was working as Sub-staff in the Moore Street, Branch of the respondent bank at Madras in 1988. Ex. W-2 certificate issued by the Branch Manager would show that he has worked in the said branch as a peon for 144 days. With a view to provide an opportunity to such of those temporary employees who have worked as temporary peons in the bank for a period of 90 days or more than that in the past, the respondent management bank arrived at a settlement with the two recognised workmen unions on 19-8-88 and as a result of which Ex. W-1 circular dated 19-8-88 was issued wherein it was decided as follows :

"All temporary employees who have worked under the period from 1-1-83 to 30-6-88 should be advised in writing by the concerned Branch office to submit an application to the Branch which they last worked. If the conditions fulfilled the eligibility criteria they should be selected by means of an interview and their names will be empanelled and the candidates

who were empanelled shall be absorbed in the regular service of the bank as peons, and the panel shall be in force till the same is exhausted or three years."

The workman Shri K. Murugesan has also submitted an application dated 25-7-91 for which the respondent bank has given an acknowledgement Ex. W-6. The advice to Shri K. Murugesan to submit an application is Ex. W-7. In the interview Shri Murugesan, was successful and the appointment order appointing him at Dindigul branch is Ex. W-3. While the workman was employed as a peon at Dindigul branch of the respondent bank, the Branch Manager, Dindigul branch MW-1 has given warning letters to the workmen which are marked as Ex. M-2, M-6, M-9, M-14, M-15 and M-18. The reply of the workman to the letters are Ex. M-11, M-12 and M-17. The workman Th. Murugesan was working at Dindigul branch of respondent bank from 5-4-91 till the date of his termination i.e. 15-10-91. During the period of his employment, the Branch Manager has issued him memos mentioned earlier and also sent letters complaining about the workers performance to the Divisional Manager which are marked as Ex. M-4, M-5, M-8, M-13, M-16 and M-18. In all the memos given to the petitioner and complaint to the Divisional Officer by the Branch Manager the misconduct alleged against the workman are as follows : 1. In spite of instructions to bring the tapals from post office by keeping them safely inside a bag or cover, the workman brought all the letters in his hand—Ex. M-2, a memo to the workman. The workman was not able to correctly locate folios, ledgers, forms etc. file papers in the concerned files, sort slips, for slip bundle/day book and bundle currency notes for keeping inside the safe. Ex. M-3 another memo dated 14-6-91. The complaints sent by the Branch Manager of Dindigul to Divisional Manager at Madras about this misconduct said to have been committed by the workman are Exs. M-4 and M-5. On 25-7-91 the Branch Manager issued another memo Ex. M-6 stating that at 10.30 a.m. when he pressed the buzzer three times to call him the petitioner failed to come inside the Branch Manager's cabin and only on the advice of the staff memos he called on him. In the explanation Ex. M-7, the workman has mentioned that he was writing draft form in the room where the forms were kept and therefore there was little delay in his attending to the call by the Manager. Not satisfied with the said explanation, the Branch Manager once again complained to the Divisional Manager by his letter dated 1-8-91 mentioning about the complaint from the day book clerk stating that the S.B. O.B.C. and post-date slips were pinned alongwith commission slips because of which not only the day book was delayed, but also the tallying work was difficult. Ex. M-10 is the complaint by a public about the misbehaviour of the workmen towards him Ex. M-11 and M-12 are the explanation given by the workman. Ex. M-13 is again the complaint sent by the Branch Manager to the Divisional Office. Ex. M-15 is a letter dated 27-8-91 given to the workman wherein it is mentioned that the workman refused to stitch note bundles and left the premises without locking the main entrance and washing the tumblers and hand using drinking water. Once again on 27-8-91, the Branch Manager has sent Ex. M-16 letter to the Divisional Office to take action against the peon. Ex. M-18 is a warning given to the workman for his failure to get a xerox copy of the explanation letter Ex. M-17. Ex. M-19 dated 31-8-91 is another letter of the Branch Manager to the Divisional Officer recommending to remove the workman immediately. Ex. M-20 is the termination order dated 3-10-91. A perusal of the several memos given by the Branch Manager to the workman would reveal that the Branch Manager has been making silly complaints against the workman which a person of normal behaviour would not do. Even for very small matters like answering to the calling bell a bit late of bringing Tapals in hand, washing the tumblers with drinking water etc. the Manager had been issuing memo after memo to build up a case against the workman so that his service may be ultimately terminated. From the records it can be seen that the petitioner had been working in various branches of the respondent for four years without any adverse remarks. Even if any of the alleged misconduct were said to have been committed by the workman, while working at Dindigul branch, the manager has neither framed any charge or conducted any enquiry. By sending several letters one after another against the workman, the Branch Manager of

Dindigul (MW-1) had been successful in terminating his services abruptly. Ever in such termination the procedure as contemplated either under the I. D. Act or Clause 495 and 522(1) of Sastry Award has not been followed. Under Clause 495 of the Sastry Award, the work of the Probationer is not satisfactory, the probation period may be extended by 3 months. But the respondent has not extended the probationary period, but has terminated his service. No doubt the petitioner was selected and appointed in a permanent vacancy. Even if he were treated as a probationer, he should have been given one month's notice or one month's pay and allowances in lieu of notice as per Clause 522(1) of the Sastry Award. But the workman was neither paid the salary nor the allowance for 1 month. Therefore, it is a clear violation of clause 522(1) of the Sastry Award. During the cross-examination of MW-1, MW-1 has clearly admitted that those who joined along with Murugesan or subsequent to him have been made permanent and if the workman has worked for 6 months properly, he would have been made permanent and that no show cause notice was issued to the concerned employee before terminating his service. In these hard days where getting an employment is so difficult, MW-1 has taken steps to terminate the service of the workman without either following the procedure or according to rules, and he has made the alleged silly mistakes as big misconducts to make out a case against the workman. In fact on 14-10-91 Murugesan is completing the 6 months by which time he should have been made permanent. But instead of making the workman permanent he has been terminated from service without any enquiry.

In the result, I hold that the termination of Thiru K. Murugesan w.e.f. 15-10-91 is not justified and he is entitled for reinstatement in service with full back wages and other attendant benefits. Award passed. No costs.

Dated, this the 22nd day of May, 1998.

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For Petitioner-workman :

WW-1 Thiru K. Gurumoorthy.

For Respondent-management :

MW-1—Thiru M. V. K. Moorthy.

DOCUMENTS MARKED

For Petitioner-workman :

Ex. W-1/19-8-88—Copy of the Bank Circular No. 166/88 and absorption of temporary peons settlement with the union (Xerox)

Ex. W-2/25-10-88—Certificate of Bank issued to Mr. K. Murugesan for temporary service period (Xerox)

Ex. M-3/14-6-91—Unsatisfactory report of the Branch (Xerox)

Ex. W-4/3-10-91—Termination order issued by bank (Xerox)

Ex. W-5/8-1-93—Conciliation failure report.

Ex. W-6/23-9-88—Acknowledgement given by Vijaya Bank (Xerox)

Ex. W-7/ —Letter by bank to Thiru K. Murugesan regarding absorption of temporary peons.

For Respondent-management :

Ex. M-1/25-3-91—Appointment order received by the Divisional Manager (Xerox)

Ex. M-2/7-6-91—Warning letter issued by the Branch Manager, Dindigul branch (Xerox)

Ex. M-3/14-6-91—Unsatisfactory report of the Branch Manager (Xerox)

Ex. M-4/17-6-91—Letter sent by the Branch Manager to the Divisional Manager regarding replacement of petitioner (Xerox)

Ex. M-5/18-7-91—Letter written by the Branch Manager to the Divisional Manager for shifting the petitioner (Xerox copy)

Ex. M-6/25-7-91—Letter written by the Branch Manager to the petitioner, show cause notice (Xerox)

Ex. M-7/27-7-91—Explanation given by the petitioner to the Branch Manager (Xerox)

Ex. M-8/30-7-91—Letter written by the Branch Manager to the Divisional Manager for replacing the petitioner (Xerox)

Ex. M-9/1-8-91—Letter written by the Branch Manager to the petitioner for misconduct and misbehaviour (Xerox)

Ex. M-10/2-8-91—Complaint given by one R. Rajendran (Xerox)

Ex. M-11/5-8-91—Letter sent by the petitioner to the Branch Manager (Xerox)

Ex. M-12/7-8-91—Letter sent by the petitioner to the Branch Manager (Xerox)

Ex. M-13/8-8-91—Letter written by the Branch Manager to the Divisional Manager.

Ex. M-14/23-8-91—Letter written by the Branch Manager to the petitioner (warning letters) (Xerox)

Ex. M-15/27-8-91—Letter written by the Branch Manager to the petitioner for initiating disciplinary action (Xerox)

Ex. M-16/27-8-91—Letter written by the Branch Manager to the Divisional Manager (Xerox)

Ex. M-17/31-8-91—Explanation given by the petitioner (Xerox)

Ex. M-18/31-8-91—Letter written by the Branch Manager to the petitioner and copy to the Divisional Manager (Xerox)

Ex. M-19/31-8-91—Letter written by the Branch Manager to the petitioner and copy to the Divisional Manager (Xerox)

Ex. M-20/3-10-91—Dismissal Order.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

को. घा. 1573.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मंत्रालय के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/178/94-आई. आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1573.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Bank and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-98.

[No. L-12012/178/94-IR(B-II)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMILNADU, MADRAS.

Friday, the 22nd day of May, 1998

Present :

Thiru S. Ashok Kumar, M.Sc., B.L., Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 193/1994

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of Indian Bank, Madras-1).

BETWEEN

The workmen represented by
The General Secretary,
Indian Bank Emp. Union,
25/II Line Beach,
Madras-1.

AND

The General Manager,
Indian Bank,
31, Rajaji Salai,
Madras-1.

REFERENCE :

Order No. L-12012/178/94-IR(B-II), Ministry of Labour, dated 21-10-94, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Thursday, the 26th day of February 1998, upon perusing the reference, claim, counter statements and all other material papers on record, and upon hearing the arguments of Tvl. Row & Reddy, S. Vaidyanathan and K. Indira, Advocates appearing for the petitioner workman and of Tvl. Aiyar & Dolia, R-Arumugam and B. Haribabu, Advocates appearing for the respondent management, and this dispute having stood over till this day for consideration this Tribunal made the following.

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of Indian Bank, Madras in not paying full wages to Shri V. Durairaj, Sub-Staff during the period of his suspension from 15-4-1988 to 23-9-89 is justified ? If not, what relief is the said workman entitled to?

2. On service of notices both the petitioner and respondent appeared before this Tribunal and filed their claim and counter statement respectively.

3. The main averments found in the claim statement filed by the petitioner-union are as follows :

The workman V. Durairaj, is employed as Peon in the Indian Bank at the Regional Office, at Trichy. On 2-4-88 he was arrested and remanded to judicial custody for his involvement in number of one Mr. Narayanan under Sections 147, 148, 341, 323, 324 and 326 of I.P.C.

On 15-4-88 he was placed under suspension with immediate effect as per the provisions of the Bipartite Settlement. On 7-9-89, the First Additional Sessions Judge (incharge), Trichy, acquitted him by giving the benefit of doubt. The acquittal was purely on merits. Enclosing the Judgement copy, a representation was given by Durairaj to the respondent Bank

on 20-9-89 requesting for revocation of the suspension. On 23-9-89, the disciplinary authority revoked the suspension order with immediate effect. However, the authority stated that the period of suspension from 15-4-88 till date of reporting would be treated as one on suspension. The employee joined duty on 24-9-89. By a letter dt. 24-10-89, Durairaj requested the Disciplinary Authority to treat the period from 15-4-88 to 23-9-89 as one spent on duty with full wages and the period prior to i.e. from 1-4-88 to 14-4-88 as one spent on privileged leave. The request was rejected by the management by its letter dt. 19-12-89. A letter dt. 21-5-90 was sent by petitioner-union on behalf of Durairaj requesting for full wages for the suspension period. There was no reply. On 14-3-92 another representation was sent by the Union. But the request was rejected by the Bank stating that there was no ground to review. Aggrieved by the said order, a dispute was raised by the petitioner union on behalf of the workman on 20-8-92 which ended up in failure. Failure report was submitted by Asstt. Labour Commissioner on 24-6-94. Hence this reference. Under para 19.3(c) of the Bipartite Settlement if an employee is acquitted by being given the benefit of doubt he may be paid such portion of such pay and allowances as the management may deem proper, and the period of his absence shall not be treated as a period spent on duty, unless the management so directs. In the case of Durairaj, the acquittal was on merits. One has not to read the judgement of the Criminal Court to find out whether the acquittal was honourable or not. Since he has been honourably acquitted he has got to be paid full wage. The acquittal was not merely by giving benefit of doubt though this expression is used in every acquittal honourable or otherwise. The petitioner prays to treat the suspension period of employee as one spent on duty and pay him the full wages.

3. The main averments in the counter statement filed by the respondent areas follows : The employee concerned was not criminally prosecuted at the instance of the management and he was arrested and remanded to judicial custody for an offence alleged to have been committed by him which was not connected with his employment in the bank. Because he was arrested for grave offence the Bank had no other so but to keep him under suspension by order dt. 15-4-88. The records made available to the Bank show that he was accused No. 2 in case no. 75/89 and charged for offences committed under Sec. 147, 302 read with 34 and 149 and 324 read with 149 IPC. Consequent upon his acquittal by criminal court irrespective of the fact whether it was an acquittal on merits or by giving benefit of doubt, his order of suspension was revoked by the order of the Disciplinary Authority dt. 23-9-89 and the period of suspension was treated as one on suspension only. The employee reported for duty on 24-9-89. The respondent denies that he should be paid his full for the period of suspension, and that the same is untenable and without substance. The workman was prosecuted for offences unconnected with his employment in the bank and the bank is not responsible for the suspension. There is no scope for invoking Clause 19(3)(c) of the Bipartite Settlement in the instant case where the employee is criminally prosecuted for

offences unconnected with his employment in the Bank and acquitted subsequently. Clause 19(3)(c) of the Bipartite Settlement will apply only when the prosecution of the employee is at the instance of the management and the offence committed by the employee has nexus to his employment in the bank. Respondent bank has no legal obligation for it to treat the period of suspension of employee as his having been on duty and pay him full wages for the said period. In this case, the bank is not responsible for keeping the employee under suspension for he got into the police case for reasons unconnected with his employment in the bank. However had he been convicted by the Criminal Court he would not have been entitled to be in the service of the bank. Since the suspension of the employee was for reasons beyond the control of the respondent bank, the employee concerned is not entitled to full wages on the principle of No work—No Pay. Since the respondent bank was constrained to keep him under suspension, the employee concerned was paid subsistence allowance. Hence he is not entitled to anything more than that. The employee concerned is not entitled to be paid anything as he was paid subsistence allowance as provided in the Bipartite Settlement during the period of suspension. The respondent prays to dismiss the claim.

5. No witness was examined on both sides. Exs. W-1 to W-6 were marked on behalf of the petitioner and on behalf of the respondent Exs. M-1 to M-4 were marked.

6. The Point for consideration is : Whether the period of suspension of Th. V. Durairaj from 15-4-88 to 23-9-89 to be treated as duty and he should be paid full wages?

7. The Point : Thiru V. Durairaj employed as a peon in the respondent bank was arrested on 2-4-88 for his alleged involvement in a criminal case and was remanded to custody. Subsequently on 15-4-88, he was placed under suspension. On 7-9-89, the employee was acquitted after trial by giving the benefit of doubt. The said delinquent sent a representation to the respondent on 20-9-89 enclosing a copy of the judgement and requested for revocation of suspension. On 23-9-89, the Disciplinary Authority revoked the suspension order with immediate effect. On 24-10-89, the said delinquent sent Ex. W-3 letter requesting to treat the suspension periods as one spent duty with full wages. The respondent bank rejected his request by Ex. W-4 letter dated 19-12-89.

8. The Learned counsel for the petitioner argued on the strength of the Bipartite Settlement on the ground that since the employee has been acquitted on merits, he should be paid full wages. The respondent management contended that Clause 19(3)(c) is not applicable to the petitioner since criminal case was not initiated at the instance of the bank. The criminal case is a result of the employee's own making for which the respondent bank is not responsible. The learned counsel for the respondent referred to the following judgement of the Hon'ble Apex Court wherein it has been held as follows :

In Ranchhodiji Chaturji Thakore Vs. Superintending Engineer, Gujarat Electricity Board & Ano-

ther (AIR 1997 SC 1802), the Hon'ble Apex Court has held as follows :—

“The reinstatement of the petitioner into the service has already been ordered by the High Court. The only question is : Whether he is entitled to back wages ? It was his conduct of involving himself in the crime that was taken into account for his not being in service of the respondent. Consequent upon his acquittal, he is entitled to reinstatement for the reason that his service were terminated on the basis of the conviction by operation of proviso to the statutory rules applicable to the situation. The question of back wages would be considered only if the respondents have taken action by way of disciplinary proceedings and the action was found to be unsustainable in law and he was unlawfully prevented from discharging the duties. In that context, his conduct becomes relevant. Each case requires to be considered in its own backdrops. In this case, since the petitioner had involved himself in a crime, though he was later acquitted, he had disabled himself from rendering the service on account of conviction and incarceration in jail. Under these circumstances, the petitioner is not entitled to payment of backwages.”

The fact of the above case referred are similar to the facts of the instant case. In this case also, it is not the respondent management who initiated criminal proceedings against the employee. The employee himself got involved in a criminal case, was arrested, detained, and subsequently tried. The involvement of the employee in a criminal case is by his own making and therefore, respondent cannot be held liable for his trial and hence Clause 19(3)(c) of the Bipartite Settlement is not applicable to the instant case.

In the result, award passed dismissing the claim of the petitioner. No costs.

Dated, this the 22nd day of May, 1998.

Sd./-

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal.
WITNESSLS EXAMINED

For bothsides : None

DOCUMENTS MARKED

For Petitioner--Workmen :

Ex. W-1/7-9-1989 : Order of First Addl. Sessions Judge, Trichy (xerox copy).

W-2/23-9-1989 : Order revoking petition (xerox copy).

W-3/24-10-1989 : Durairaj's representation to treat suspension period as one spent on duty with full wages (xerox copy).

W-4, 19-12-1989 : Respondent's letter rejecting petitioner's request.

W-5/7-8-1992 : Respondent's rejection order.

W-6/24-6-1994 : Conciliation failure report (xerox copy).

For Respondent—Management :

Ex. M. 1/ : Extract of para 19.2 and 19.3(c) of First Bipartite Settlement dt 19-10-1966 (xerox copy).

M. 2/15-4-1988 : Copy of Disciplinary Authority's letter (xerox copy).

M. 3/22-9-1988 : Copy of Disciplinary Authority's letter (xerox copy).

M. 4/23-9-1989 : Copy of Disciplinary Authority's letter (xerox copy).

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. आ. 1574:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 12012/40/95—आई. आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1574.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1998.

[No. L-12012/40/95-IR(B-II)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. I.D. 9 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

Vijay Prakash,
C/o Smt. Kamla Bhatnagar,
Neem Ki Mathia Bankhana,
Bareilly.

2003 GI/98—21

AND

Regional Manager,
Indian Overseas Bank,
10, Ashok Marg,
Lucknow.

APPEARANCE :

B. P. Saxena—for the workman.

R. L. Agrawal—for the Bank.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour vide Notification No. L-12012/40/95-IR.(B-2) dated 30-12-1996, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Indian Overseas Bank, Lucknow in dismissing the services of Sri Vijay Prakash, clerk is legal and justified? If not to what relief the workman is entitled?

2. The concerned workman was working as clerk/shroff at Regional Office Lucknow of the opposite party Indian Overseas Bank in the year 1988. He was issued a chargesheet dt. 16-2-1989 the copy of which is annexed herewith. The substance of this charge is that he and his brother Ajai Prakash had hatched a conspiracy on 2-12-82 to defraud the Bank to the tune of Rs. 672000. In that course Ajai Prakash had impersonated as S. K. Agrawal and his brother was arrested at the spot. A criminal case was registered against him which ultimately ended in acquittal. He was issued another chargesheet while he was posted at Bareilly branch of the opposite party, the copy of this chargesheet is attached herewith as Annexure-II. Substance of this chargesheet is that he has tried to defraud the Bank to the tune of Rs. 2.23 lacs on 19-12-84.

3. One K. K. Sadashiv an officer of the bank was appointed enquiry officer. After completing enquiry he submitted his report dated nil. On the basis of this report he was dismissed from service on 16-3-84. Feeling aggrieved the concerned workman raised the instant industrial dispute, inter-alia, the concerned workman has alleged that the enquiry was not fairly and properly held. This fact was denied by the bank.

4. On the pleadings of the parties a preliminary issued regarding fairness and propriety of domestic enquiry was framed. Vide finding dated 22-5-98, it was held that enquiry was properly and fairly held. While doing so this tribunal also dealt with legal objection regarding validity of chargesheet on the ground of delay etc. and the same were negated.

5. Now the parties have been heard on the question of punishment. It will be evident from the perusal of charges which is found to be proved that the concerned workman have been found to

be guilty of deliberate act of dishonesty which naturally would amount to loss of confidence. It was submitted by the authorised representative for the workman that dismissal is a economic death sentence and it should be sparingly awarded. I think the principles which have been borrowed from criminal jurisprudence regarding theory of punishment should not be applied mechanically to instant type of dispute. In the case of K. G. Jani versus State Bank of Saurashtra 1983(3) SLR 232 (Gujrat) it was found that in a case of bank employee who has been found to be dishonest, dismissal would be the appropriate punishment. If lesser punishment is awarded it would amount to condonation of corruption.

6. Thus in view of above ruling I come to the conclusion that punishment awarded to the concerned workman is not disproportionate to the gravity of misconduct. Hence it does not call for interference. Accordingly the concerned workman is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

INDIAN OVERSEAS BANK

Central Office : P.B. No. 3765, 762 Anna Salai,
Madras-600002

VIGILANCE DEPARTMENT

Madras, the 16th February, 1989

VIG : 536

Shri Vijay Prakash,
Roll No. 31374,
Clerk/Shroff,
Indian Overseas Bank,
Regional Office,
Lucknow.

Dear Sir,

CHARGE SHEET-CUM-SUSPENSION ORDER

It is reported that while functioning as Clerk/Shroff attached to our Regional Office, Lucknow you had committed the following acts of commission and omission :

On 2-12-88 one person calling himself as Shri S. K. Agarwal, Proprietor, M/s. Aarati Builder, B-11A, Nirala Nagar, Lucknow opened a Current Account No. 1412 in the name of the said firm with our Lucknow Main Branch. The account was purportedly introduced by Mr. Mudit Narain, partner M/s. Narain Automobiles, Shah Nazaf Road, Lucknow. On 8-12-88 while checking the vouchers of 7-12-88 for writing day book one voucher dated 7-12-88 for Rs. 6,72,000 for credit of the above account by TT remittance purported to be from a Delhi Branch of our bank was found. This voucher and the corresponding debit voucher dated 7-12-88

for Rs. 6,72,000 were not entered in the transfer journal. Investigation revealed that the account was not introduced by the said Mr. Mudit Narain. At that time the aforesaid Shri S. K. Agarwal called at the branch and requested the Current Account Department Officer to issue a cheque book for the said account. The said Shri S. K. Agarwal was immediately apprehended and handed over to the police and an FIR was registered in FIR No. 1185/88 dated 8-12-88 at Police Station Hazaratganj.

Investigation by the police showed that the said Shri S. K. Agarwal is no other than your own brother Shri Ajay Prakash. Further police have recovered the following items from the custody of Shri Ajay Prakash :—

- (a) Correspondence/statements bearing the signature of branch officials.
- (b) Letter of bank's customers bearing the full signatures.
- (c) Bank's stationary items viz. 12 Nos. of credit schedules, 10 Nos. of credit with advice vouchers 2 Nos. of specimen signature cards and 2 Nos. of account opening forms and two blank Savings Bank Account Pass Books and 13 pages of a diary containing addresses, code nos. banking hours of our Delhi branches.

You had visited Lucknow branch on 7-12-88 and 8-12-88 at about 4.00 P.M. and when the attempted fraud on the branch came to light you left the bank premises without obtaining any permission. From the foregoing it is charged as follows :

- (1) You had entered into a conspiracy with your brother to cheat the bank to the extent of Rs. 6,72,000.
- (2) In furtherance of the conspiracy you had got the Current Account opened at the branch by forging or getting forged signature of the introducer.
- (3) You planted the debit and credit vouchers for Rs. 6,72,000 at the branch for perportrating the fraud. In that process you had also planted a fictitious telegram said to have been issued by a Delhi branch.

If the above acts are established in an enquiry, it will render you guilty for having committed gross misconduct as follows :

- 17.5 (d) wilful damage or attempt to cause damage to the property of the bank or any of its customers;
- 17.5 (j) doing any act prejudicial to the interests of the bank, or gross

negligence or negligence involving or likely to involve the bank in serious loss :

Please show cause in writing do as to reach me within 10 days from the date of receipt of this letter as to why disciplinary action should not be taken against you, failing which the matter will be decided as it deem fit and you will be bound by the result thereof.

Pending investigation by the police and pending outcome of disciplinary action as above, please be advised that you are place under suspension with immediate effect in terms of para 17-3(a) read with para 17.12(b) of the Bipartite Settlement dated 14-12-1966 between the bank and its workmen.

Yours faithfully,

M. VIJAYAKUMAR, Disciplinary Authority

INDIAN OVERSEAS BANK

Central Office : P.B. No. 3765, 762 Anna Salai,
Madras-600002

VIGILANCE DEPARTMENT

Madras, the 28th March, 1990
Shri Vijay Prakash,
Roll No. 31374,
Clerk/Shroff (under suspension),
Indian Overseas Bank,
Regional Office,
Lucknow.

Dear Sir,

Additional chargesheet-cum-concurrent suspension order

It is reported that while functioning at our Bareilly Branch (Lucknow Region) you had committed the following acts of commission and omission :—

One Shri G. K. Sawhney was maintaining an NRE S.B. Account No. 4193 at Bareilly branch. On 11-12-84 he called at the branch and wanted to withdraw some funds for purchase of property in Mussorie. He had also stated that he had brought a demand draft for US \$ 30000 which he may deposit, if it remains unutilised. He also requested the Accountant Shri Nanajkar to issue him introduction letters for opening accounts at Dehra Dun and Delhi. Shri Nanajkar issued two separate introduction letters with the account holder's signature duly attested on separate sheets and handed over them to the account holder in sealed covers. You were observing the entire transaction.

On 19-12-84 Bareilly branch received a letter dated 14-12-84 in post purported to have been signed by Shri G. K. Sawhney requesting transfer of Rs. 2.23 lacs to his S.B. Account No. 3644 at Moradabad branch. The letter also stated that draft

for US \$ 30,000 was already despatched and the amount may be credited to the account on receipt. On 19-12-84 around 4.00 P.M. Shri Nanajkar, Accountant received a telephone call and the caller introduced himself as Shri G. K. Sawhney and requested for expediting the transfer of Funds. Shri Nanajkar enquired when the letters of introduction was given to Dehra Dun and Delhi branches how he got an account opened at Moradabad branch? The caller replied that he had been maintaining an account with Moradabad branch. On 20-12-84 NRE S.B. Account No. 4193 of Shri G. K. Sawhney was debited with Rs. 2.23 lacs and a TT WAS ISSUED ON Moradabad branch. The telegraphic transfer was received by our Moradabad branch on 21-12-84. At Moradabad branch on 15-12-84 one person calling himself as Shri G. K. Sawhney came and produced the introduction letter purportedly given by Shri Nanajkar Accountant of Bareilly branch and opened an account with an initial deposit of Rs. 101. The account holder was also issued with a cheque book. On 22-12-84 the same person called at the branch and issued a cheque for Rs. 1.52 lacs and withdrew the part of the proceeds of the telegraphic transfer credited into the account. On 26-12-84 another cheque for Rs. 70,000 was tendered by the person and the same was passed for payment. Thus a total of Rs. 2.22 lacs were withdrawn through the medium of the newly opened S.B. Account at Moradabad branch. Investigation show that :—

That when Shri G. K. Sawhney visited Bareilly branch and wanted the introduction letters to be given you were watching the conversation.

That utilising the opportunity, you had committed the fraud either singly or in collusion with your brother Shri Ajay Prakash or with others, which fact is strengthened by the following :—

- (a) One cheque bearing No. 321572 for Rs. 19,000 debited to the S.B. Account No. 4193 of Shri G. K. Sawhney on 1-8-84 was missing from the voucher pad of 1-8-84. A portion of the cheque was visible with the voucher pad confirming that the cheque has been pilfered from the voucher bundle. Obviously the cheque has been removed with a view to forge signature of G. K. Sawhney.
- (b) The letter head used for typing the forged letter of introduction has been taken from the stock of letter heads at Bareilly branch. When the police raided your house on the complaint of the account holder they seized 4 letter heads and 2 covers of the bank which was similar to the one in which the false introduction letter was issued for opening the account at Moradabad branch.

- (c) The impression of rubber stamp used on the forged letter of introduction resembles very much with the rubber stamp in use at Bareilly branch.

That the fraud would not have been perpetrated without your active participation in the same as the letter-heads, rubber stamp and specimen signature of Shri G. K. Sawhney could not be obtained from the branch by any outsider.

It is thus charged that you had caused wilful damage to the property of the bank which is a gross misconduct under para 17.5(d) of the settlement between Bank and its workmen dated 14-12-66 which also amount to gross misconduct for doing acts prejudicial to the interest of the bank involving the bank to serious loss under para 17.5(j) of the aforesaid settlement. The said provisions of the Bipartite Settlement are extracted below :

17.5 (d) : wilful damage or attempt to cause damage to the property of the bank or any of its customers.

17.5 (j) : doing any act prejudicial to the interests of the bank, or gross negligence or negligence involving or likely to involve the bank in serious loss.

Please show cause in writing as to why disciplinary action should not be taken against you within 10 days from the date of receipt of this letter. If your explanation were found unsatisfactory or no explanation is received within the stipulated time, an enquiry will be conducted on the date and venue which will be intimated to you in due course. If you fail to submit your explanation in time and/or attend the enquiry, the matter will be decided exparte and you will be bound by the results thereof.

Pending enquiry into the chargesheet please be advised that the order of suspension already issued to you as per letter dated 16-2-89 will also be applicable for this chargesheet as well, in terms of para 17.12(b) of the Bipartite Settlement as above and suspension order in respect of both the chargesheets will run concurrently.

Yours Faithfully,

M. VIJAYAKUMAR, Disciplinary Authority

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. आ. 1575:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर

के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—12012/309/95—आई. आर. (बी.-II)]

सनातन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1575.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Bank and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1998.

[No. L-12012/309/95-IR (B-II)
SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 2 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

Ramesh Chandra S/o Chandra Ram,
Gram Bahadurpur
Post Mathura
District Mathura

AND

Asstt. General Manager
Indian Bank
2-B Habibullah Estate
Lucknow.

APPEARANCES :

V. K. Gupta—for the Bank
S. K. Bhargava—for the workman.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide Notification No. L-12012/309/95-I.R. B-II dated 30-12-1996 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Indian Bank Mathura to terminate the services of Ramesh Chandra workman w.e.f. 18-5-93 and also to deny employer employee relationship between the workman and the management is legal and justified ? If not, to what relief he is entitled ?

2. The case of the concerned workman Ramesh Chandra is that he continuously worked as messenger from 19-5-90 to 18-5-93 as daily rated worker at Mathura Branch of the opposite party Indian Bank. During this period he used to perform duties of a regular peon. As his services were terminated in breach of provisions of Section 25-F of I. D. Act, the same is bad in law.

3. The opposite party has filed reply in which it has been denied that the concerned workman had worked as messenger in any vacant post as alleged by the concerned workman. In fact some times he used to be engaged for doing work of casual nature. He had not completed 240 days in a year.

4. In the rejoinder nothing new has been alleged.

5. In support of his case, concerned workman Ramesh Chandra has examined himself as TW-1, Management Bank

examined B. K. Chaturvedi MW-1 besides the management have filed Ext. M-1 to M-7. The concerned workman had also filed a hosts of documents but none of them were proved.

6. The first point which needs consideration is as to whether the concerned workman had worked on the post of peon. The concerned workman had stated that he had worked as messenger from 19-5-90 to 18-5-93. Management witness B. K. Chaturvedi had denied it. There is Ext. M-7 an affidavit filed by the concerned workman for obtaining loan. In this affidavit he has sworn that he is not employed any where. This paper goes to demolish the case of the concerned workman. Accordingly it is held that the concerned workman has not worked as messenger/peon with the opposite party.

7. The concerned workman has stated that he had continuously worked from 19-5-90 to 18-5-93. This fact has been denied by the management witness. When the concerned workman had not worked as a messenger obviously he could not work continuously. Further the evidence adduced by the management has not been cross examined that shows that the concerned workman did not dispute the correctness of evidence of the management. Hence on this score too the evidence adduced by the management is entitled for greater weight. Accordingly it is held that the concerned workman had not worked for 240 days, hence there has been no breach of Section 25-F of I. D. Act, when the services of the concerned workman were terminated.

8. In the end my award is that termination of the concerned workman is not bad and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. आ. 1576:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यू.नियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/345/96-आई. आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1576.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to management of Union Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-98.

[No. L-12012/345/96-IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 213 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

The General Secretary,

Union Bank Staff Association,
Central Office 3/192, Vikram Khand,
Gomti Nagar, Lucknow

AND

The General Manager,

Union Bank of India,
Zonal Office, Sharda Tower II Floor,
Kapoorthala Complex Aliganj,
Lucknow.

APPEARANCE :

M. L. Agrawal for the Bank and
P.K. Tiwari for the Union.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour vide notification No. L-12012/345/96-IR (B-II) dated 26-9-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Union Bank of India, Lucknow in not considering the application (I. C. Sharma), Head Cashier, Category E. Jaunpur Main Branch of the post of Special Assistant submitted by him on 6-4-96 is legal & justified? If not to what relief the said workman is entitled?

2. There is no dispute that the concerned workman I. C. Sharma was working as Head Cashier at Jaunpur Main Branch of the opposite party Union Bank of India. The opposite party bank had circulated for filling 63 vacancies of special assistants on 5-2-96 the concerned workman was eligible for this post by virtue of number of years for which he has rendered service.

3. The case of the concerned workman is that this circular of the bank reached branch late as it was not sent directly to various branches. The concerned workman being qualified had applied for the same but his name was not included. The last date for receipt of such application was 13-4-96, whereas his application was received at Zonal Office on 15-4-96. It is alleged that the application was not at fault as he had submitted application much in advance. As he has been deprived of the benefit because of fault of the management, he is entitled for being considered for promotion to the post of special assistants.

4. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that as the application of the concerned workman was received beyond 13-4-96, the

same was not considered. There was no fault in forwarding the application to the Zonal Office.

5. In the rejoinder, nothing new has been alleged.

6. Thus the only point which calls for consideration is as to whether the application of the concerned workman reached late at Zonal Office of the opposite party because of the fault of the management or the concerned workman.

7. Although the parties have filed a number of documents regarding issuance of circular, proceedings which took place for promotion of special assistant but none of parties have filed copy of application to show as to actually when the concerned workman had applied for promotion. Even the concerned workman has not examined himself to throw light on it. Instead he has examined his representative Pradip Kumar Tiwari W.W.1. He has explained the procedure for receipt of Mail at Zonal Office. However, in his cross examination he has stated that application was given to Branch Manager on 6-4-96, but it was not received at the branch office. In the end he has denied the suggestion that the concerned workman after getting the application forwarded by the branch manager had taken it back.

8. In rebuttal Rajesh Pandey M.W.1 has stated that the concerned workman had not submitted any application to the branch manager. Had it been so the same would have been forwarded to the zonal office. In my opinion in such circumstances the concerned workman ought to have entered into the witness box as he had alone had personal knowledge about the fact that he had submitted the application to the branch manager. The evidence of R. K. Tiwari cannot be accepted at it is not based on his personal knowledge. Thus in my opinion it is not established at all that the concerned workman had actually submitted application to the branch manager. It is true that the application of the concerned workman was sent to the zonal office which was received on 15-4-96, the fault if any on behalf of the management should have been proved by the workman which he had failed to do. In its absence, my finding is that the opposite party bank was not responsible in any way for the delayed receipt of application of the applicant after 13-4-96, as the application was received after the expiry of the period, the opposite party bank was justified in not considering it.

9. Hence my award is that the opposite party bank was justified in not considering the application of the concerned workman for the post of special assistant. Consequently the concerned workman is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

का. आ. 1577:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध मरिदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन. 17012/20/96-आई. आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1998

S.O. 1577.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workman which was received by the Central Government on 23-7-98.

[No. L-17012/20/96-IR(B-II)]
SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 20 of 1997

PARTIES :

Employers in relation to the management of
L.I.C. of India

AND

Their workmen.

PRESENT :

Mr. Justice A. K. Chakravarty, Presiding
Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Management :

Mr. R. K. Patra, Administrative Officer.

On behalf of Workmen :

Mr. S. Bagchi, President of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Insurance

AWARD

By Order No. L-17012/20/96-IR(B-II) dated
27-5-1997 the Central Government in exercise of

its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of LIC of India, Calcutta in superannuating Shri Hare Krishna Bhanja, Pumpman w.e.f. 1-7-93 is legal and justified ? If not, to what relief the said workman is entitled ?"

2. When the case is taken up today for examination of the witness of the union, the representative of the union refused to examine any witness or produce any legal evidence in support of its case inspite of the direction of the Tribunal to the effect. It is true that xerox copies certain documents were produced by the union alongwith its written statement. But mere production of such xerox copies without filing the original and absence of any witness to prove such documents make

them inadmissible in evidence. It is accordingly clear that the union is not interested in the matter. Representative of the management stated that since the union has not examined any witness to prove its case, management will not examine any witness.

3. In the aforesaid circumstances, in the absence of any material whatsoever for any decision in respect of the schedule under reference, this Tribunal has no other alternative but to pass a "No Dispute" Award.

4. A "No Dispute" Award is accordingly passed and the reference is disposed of.

This is my Award.

Dated, Calcutta,
The 29th June, 1998.

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer

